अदालतों में क्षेत्रीय भाषाएं

प्रधान न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़ ने कहा है कि प्रभावी न्याय व्यवस्था के लिए स्थानीय भाषाओं को अपनाना चाहिए. एक गोष्ठी में उन्होंने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जब वे न्यायाधीश थे, तब उन्होंने महसूस किया था कि वकील अपनी मूल भाषा में बेहतर तरीके से बहस कर पा रहे थे. हमारे देश में दशकों से यह मांग की जाती रही है कि पेशेवर शिक्षा की प्रवेश परीक्षा में तथा शिक्षण के माध्यम के रूप में हिंदी समेत भारतीय भाषाओं को भी शामिल किया जाए. लेकिन अभी तक पठन-पाठन में अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है. पिछले साल भी प्रधान न्यायाधीश ने कहा था कि विधि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) को केवल अंग्रेजी में आयोजित करना कानूनी पेशे को ग्रामीण और वंचित लोगों के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण है. उनके कथन कानून के पेशे में सेवा हासिल करने तथा उसके समावेशी होने से संबंधित समस्या को इंगित करते हैं. कानून की पढ़ाई में अंग्रेजी का वर्चस्व है, तो दस्तावेज भी अंग्रेजी में होते है, सुनवाई में भी अंग्रेजी का ही बोलबाला रहता है. फैसले भी आम तौर पर अंग्रेजी में ही लिखे जाते हैं. निचली अदालतों में स्थानीय भाषाओं के लिए कुछ गुंजाइश रहती है, पर सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों, विशेष न्यायालयों और ट्रिब्यूनलों में अंग्रेजी ही चलती है. कुछ दिन पहले उन्होंने न्यायाधीशों को सलाह दी थी कि वे सरल भाषा में निर्णय लिखें, जिसे समझने में सबके लिए आसानी हो. कई देशों में कानून की पढ़ाई और अदालती प्रक्रिया में क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल होता है. ऐसी व्यवस्था से न्यायिक प्रक्रिया तक नागरिकों की पहुंच आसान होती है तथा उन्हें इस पेशे में आने के लिए भी प्रोत्साहन मिलता है. प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि यदि कानून के मुख्य सिद्धांतों को छात्र अपनी मूल भाषा और संदर्भ में पढ़ेंगे, तो वे सामाजिक रूप से अधिक जिम्मेदार वकील बनेंगे तथा अपने समुदायों से उनका जुड़ाव भी पुख्ता होगा. उनके प्रयासों से सर्वोच्च न्यायालय में तकनीक को अपनाने पर जोर दिया गया है. जनवरी 2023 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को विभिन्न भाषाओं में अनूदित करने की परियोजना चल रही है. इसके तहत हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल भाषाओं में निर्णयों को उपलब्ध कराया जा रहा है. हाल के वर्षों में मेडिकल, प्रबंधन आदि कुछ पेशेवर पाठ्यक्रमों को हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की गयी है, पर इसके विस्तार की गति बहुत धीमी है. इस महीने के शुरू से लागू किये गये तीन नये कानूनों का भी अभी तक विभिन्न भाषाओं में अनुवाद नहीं हुआ है. ऐसे अवरोधों को दूर किया जाना चाहिए.

दशकों से यह मांग की जाती रही है कि पेशेवर शिक्षा की प्रवेश परीक्षा में तथा शिक्षण के माध्यम के रूप में हिंदी समेत भारतीय भाषाओं को भी शामिल किया जाए.

चिकित्सा पेशे के सामने मुश्किलें

डॉ संजना ब्रह्मवार मोहन
सह-संस्थापक, बेसिक हेल्थकेयर सर्विसेस
editor@thebillionpress.org

इन दिनों भारतीय न्याय संहिता और किडनी प्रत्यारोपण के अवैध तंत्र के बारे में चर्चाएं चल रही हैं. हम थोड़ा ठहर कर यह याद करने की कोशिश करें कि हमने पिछली बार कब यह चर्चा की थी कि हमारे युवा चिकित्सक और मेडिकल के छात्र कैसी हालत में रहते हैं और किस प्रकार अपनी पढ़ाई और अपना काम करते हैं? जब ये डॉक्टर हर रोज जिंदगियां बचाते हैं, तब क्या हम उस पर खुशी जताते हैं और उनकी सराहना करते हैं? हमें यह अच्छी तरह से याद है कि कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टरों ने कितनी शानदार भूमिका निभायी थी.

स्वास्थ्य सेवा के 'व्यवसायीकरण' को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं. उदाहरण के लिए, किडनी प्रत्यारोपण के बारे में आये दिन खबरें आती रहती हैं. ऐसी स्थिति को संज्ञान में लेते हुए इस वर्ष चिकित्सक दिवस (एक जुलाई) को लागू हुए भारतीय न्याय संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों को जेल भेजा जा सकता है. नीट परीक्षा में कई गड़बड़ियों और पीजी प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने से देश का ध्यान चिकित्सा शिक्षा की ओर गया है. परीक्षा प्रक्रियाओं को दुरुस्त करने के साथ-साथ यह देखना भी जरूरी है कि और क्या-क्या किया जाना चाहिए, जिससे हमारे डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर सकें. राजस्थान के ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र में बुनियादी स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के अपने एक दशक के काम के दौरान हमने बड़ी संख्या में युवा डॉक्टरों के साथ काम किया है तथा प्राथमिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के बहुत चिकित्सकों से भी हमारा संपर्क रहा है. डॉक्टरों को ग्रामीण भारत की वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए हमने कार्यशालाएं भी आयोजित की है. इन अनुभवों के आधार पर कुछ प्राथमिकताओं को इस लेख में रेखांकित किया जा रहा है.

यह एक धारणा है कि पहले के डॉक्टर आज के चिकित्सकों की अपेक्षा कहीं अधिक जानते थे. कई लोगों को याद होगा कि किसी दौर में डॉक्टर एक ब्रीफकेस लेकर मरीज के घर आते थे और उसे देखकर वहीं दवाई दे देते थे या लिख देते थे. वे डॉक्टर अब कहीं नहीं दिखते. पहले मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और शिक्षक भी पूरी तरह समर्पित होते थे. अब यह कमजोर होता जा रहा है. कार्यशालाओं में कई डॉक्टरों ने बताया कि कॉलेज में उनकी मौजूदगी का मतलब नहीं है और वे घर पर ही अधिकांश पढ़ाई करते हैं. उन्होंने अफसोस के साथ कहा कि उनके शिक्षकों के पास उनके लिए समय नहीं है. एक वरिष्ठ डॉक्टर ने एक मेडिकल छात्र को डांटा था कि उसका काम रोगी का उपचार है, उसके प्रति हमदर्दी रखना नहीं. निजी मेडिकल कॉलेजों से आनेवाली कहानियां भी हमने सुनी हैं. वहां के छात्र धनी परिवारों से आते हैं और कक्षाओं में उनकी रुचि बहुत कम होती है. पढ़ाई के बाद उनमें से अधिकतर अपना अस्पताल खोल लेते हैं. प्रबंधन भी शिक्षकों पर छात्रों को पास कर देने के लिए दबाव बनाता है. डॉक्टरों का एक तीसरा समूह भी तेजी से बढ़ रहा है, जो चीन, रूस और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों से पढ़कर आते हैं. भारतीय कॉलेजों में पढ़ाई की खराब गुणवत्ता के बावजूद यहां पढ़े डॉक्टरों और विदेश से पढ़कर आये डॉक्टरों में बड़ा अंतर है. रोगियों से बात करने में सूचनाओं का स्पष्ट प्रवाह नहीं होता तथा कई डॉक्टर दवाओं के बारे में बुनियादी जानकारी भी नहीं रखते. यह स्थिति ठीक नहीं है. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि डॉक्टरों के पास जानकारी और कौशल हो तथा उनमें हमदर्दी की भावना हो.

कुछ माह पहले हमारे एक डॉक्टर को उनके एक डॉक्टर मित्र का फोन आया कि एक मरीज को मलेरिया हुआ है, उसे क्या दवा दी जाए. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अकेले कार्यरत डॉक्टर से ऐसे सवाल की अपेक्षा की जा सकती है क्योंकि उन्हें एक ही दिन में कई तरह केजी मरीजों को देखना पड़ता है. इसी वजह से हम जैसे कई डॉक्टरों को एक समूह बनाना पड़ा है. हम अपने सवाल समूह में पोस्ट कर देते हैं या मार्गदर्शन के लिए किसी विशेषज्ञ से बात करते हैं. हम ऑनलाइन माध्यम से हर सप्ताह मिलते हैं तथा नयी जानकारियों, रोगों के अध्ययन और अन्य सवालों को साझा करते हैं. ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत डॉक्टरों समेत शहरों में अस्पतालों में काम कर रहे चिकित्सकों से चर्चा में हमने पाया है कि किसी संदेह की स्थिति में परामर्श करने के लिए उनके पास बहुत कम मित्र या वरिष्ठ डॉक्टर उपलब्ध हैं. हमें डॉक्टरों के लिए ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए, जिसके माध्यम से वे अपने सवालों के जवाब पा सकें तथा नयी जानकारियों को उन्हें मुहैया कराया जा सके. जरूरी नहीं है कि ऐसी जानकारियां उन्हें दवा कंपनियों से ही मिलें. पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए परीक्षा प्रणाली लाने की बात हो रही है. यह ठीक है, पर हमें और भी बहुत कुछ करना होगा.

हम विचार करें कि समाचार चैनलों और सोशल मीडिया पर कैसी खबरें चलती रहती हैं. इन दिनों विश्व कप जीतने और एक उद्योगपति के घर शादी की चर्चाएं हैं. अवैध किडनी प्रत्यारोपण की खबरें ध्यान खींचती हैं, पर उन घटनाओं की सुध क्यों नहीं ली जाती, जिनमें जीवन रक्षा होती है? कुछ दिन पहले हमारे एक क्लिनिक से एक महिला रोगी को 120 किलोमीटर दूर उदयपुर के एक अस्पताल में रेफर किया गया. वहां जाने में उसकी हालत और बिगड़ गयी, पर तुरंत जरूरी उपचार से उसे बचा लिया गया.

ऐसी खबरें भी प्रसारित होनी चाहिए. इसका महत्वपूर्ण प्रभाव डॉक्टरों पर भी होगा, जिनका अपने पेशे के बारे में एक नजरिया है, और समाज पर भी, जो डॉक्टरों को अपनी नजर से देखता है. इन दिनों भारतीय न्याय संहिता और किडनी प्रत्यारोपण के अवैध तंत्र के बारे में चर्चाएं चल रही हैं. हम थोड़ा ठहर कर यह याद करने की कोशिश करें कि हमने पिछली बार कब यह चर्चा की थी कि हमारे युवा चिकित्सक और मेडिकल के छात्र कैसी हालत में रहते हैं और किस प्रकार अपनी पढ़ाई और अपना काम करते हैं? जब ये डॉक्टर हर रोज जिंदगियां बचाते हैं, तब क्या हम उस पर खुशी जताते हैं और उनकी सराहना करते हैं? हमें यह अच्छी तरह से याद है कि कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टरों ने कितनी शानदार भूमिका निभायी थी.

हमें ऐसी कहानियों को निरंतर कहते रहना होगा. इनकी अनुपस्थिति और नकारात्मक कहानियों की सतत उपस्थिति से एक क्षोभ पैदा होता है, जो खतरनाक हो सकता है. कुछ साल पहले मध्य राजस्थान के एक अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला की मृत्यु हो गयी थी. मीडिया और परिजनों की प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही थी. लेकिन जो दुखद त्रासदी उसके बाद हुई, वह अपेक्षित नहीं थी. जो डॉक्टर उस महिला का उपचार कर रही थी, वह तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पायी और उसने अपनी जान ले ली. आज जो स्थिति है, उसे चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए. स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के अपने प्रयास में हमें चुनौतियों को टुकड़ों में नहीं, उनकी समग्रता में देखना चाहिए.

(ये लेखिका के निजी विचार हैं.)

तलाकशुदा महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता जरूरी

डॉ शीबा असलम फहमी
पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता
sheebaasla@gmail.com

सर्वोच्च न्यायालय के यह हालिया निर्णय सराहनीय है. इससे उन बेसहारा महिलाओं को कुछ राहत मिल सकती है, जो तलाक होने के बाद अपने या भाई पर बोझ बन जाती हैं. कई बार माता-पिता होते नहीं हैं और भाई खुद अपनी और अपने परिवार परेशानियों से घिरा होता है. ऐसे में उस महिला के लिए ठौर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है.

सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने फैसला दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत शादीशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है तथा यह प्रावधान सभी धर्मों की महिलाओं पर लागू होता है. यह फैसला एक याचिका की सुनवाई के बाद आया है. इसलिए यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि कोई नया प्रावधान लागू नहीं किया गया है. अदालत ने यह भी कहा है कि पूर्व पतियों द्वारा पूर्व पत्नियों को यह भत्ता देना कोई दान नहीं है, बल्कि शादीशुदा महिलाओं का बुनियादी अधिकार है. शाहबानो मामला चला ही इस आधार पर था कि तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता का अधिकार है. दानियाल लतीफी और अन्य कुछ मामलों में भी इस अधिकार को रेखांकित किया जा चुका है. इस संदर्भ में एक विसंगति है कि अगर हिंदू पति-पत्नी का तलाक होता है, तो दोनों में जिसकी आय अधिक होगी, वह कम आय वाले व्यक्ति को भत्ता देगा. यह प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 में है. इसका अर्थ है कि अगर तलाकशुदा पति की आमदनी कम है, तो वह अधिक आय वाली पूर्व पत्नी से गुजारा भत्ता मांग सकता है. पर मुस्लिम पुरुष को यह अधिकार नहीं दिया गया है. यह विसंगति कानूनी बराबरी के सिद्धांत के विरुद्ध है.

बहरहाल, सर्वोच्च न्यायालय के यह हालिया निर्णय सराहनीय है. इससे उन बेसहारा महिलाओं को कुछ राहत मिल सकती है, जो तलाक होने के बाद अपने माता-पिता या भाई पर बोझ बन जाती हैं. कई बार माता-पिता होते नहीं हैं और भाई खुद अपनी और अपने परिवार परेशानियों से घिरा होता है. जब वे भाई के परिवार के पास जाती हैं, तो वहां उन्हें एक अड़चन के रूप में देखा जाता है. ऐसे में उस महिला के लिए ठौर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है. इस लिहाज से मुस्लिम पुरुषों को भी इस फैसले से राहत मिली है अपनी बेटी या बहन के हवाले से. पति तो केवल एक महिला का होता है, पर एक पुरुष कई महिलाओं का पिता या भाई हो सकता है. इस संबंध में यह कहना जरूरी है कि शादी बहुत सोच-समझ कर की जानी चाहिए और शादी टूटने की स्थिति के बारे में पहले ही विचार कर लिया जाए. गुजारा भत्ते का यह कानून हमें उस तरफ भी ले जा रहा है, इसलिए भी इसका स्वागत किया जाना चाहिए. यह प्रावधान किसी भी लिहाज से इस्लाम और उसकी स्थापनाओं के विरुद्ध नहीं है. इस्लाम लाजिमी तौर पर यह कहता है कि तीन महीने और तेरह दिन की जो इद्दत की अवधि है, उसमें पूर्व पति जितना चाहे, उतना दे सकता है. यह नहीं कहा गया है कि कम-से-कम देना है या केवल इसी अवधि के लिए देना है. पूर्व पति जीवन भर के लिए भी दे सकता है. पर जीवन भर के भत्ते के संबंध में इस्लाम में प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि इस्लाम दोनों- पुरुष और स्त्री- के पुनर्विवाह के अधिकार को मान्यता देता है. और, जब महिला की दूसरी शादी हो जाती है, तो गुजारा भत्ता भी बंद हो जाता है.

कि पहले कहा गया है, शाहबानो मामला गुजारा भत्ते का ही था और निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक भत्ते के अधिकार पर मुहर लगी थी. उसके बाद अनेक मुस्लिम संगठनों ने तत्कालीन सरकार पर दबाव डालकर उस फैसले को संसद में बदलकर तीन महीने और तेरह दिन के भत्ते की व्यवस्था को ही चलते रहने दिया था. लेकिन दानियाल लतीफी के मामले में फिर से सर्वोच्च न्यायालय ने गुजारा भत्ते के अधिकार पर मुहर लगा दी थी. गुजारा भत्ता के इस ताजा फैसले में न्यायाधीश की यह टिप्पणी भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो महिला गृहिणी है, घर संभालती है, बच्चों का पालन-पोषण करती है, उसके सशक्तीकरण के लिए पति को अपनी कमाई को उससे साझा करना चाहिए. अदालत ने तो साझा एटीएम और खाते का भी सुझाव दिया है. दुनियाभर में नारीवादी आंदोलन में अरसे से यह बात कही जा रही है कि जो परिवार संभालने का काम रही है, इसके लिए उसे सजा नहीं दी जा सकती, उसका करियर यही है. इसके लिए उसे समुचित सम्मान मिलना चाहिए, जो आर्थिक लाभ के रूप में हो. इस सलाह का खूब स्वागत किया जाना चाहिए. यह सभी धर्मों की महिलाओं के लिए है. नारीवादी आंदोलन का हमेशा से कहना रहा है कि जिस दिन महिलाएं अपने श्रम का हिसाब मांगेंगी, उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जायेगी.

यह भी समझा जाना चाहिए कि केवल कानूनी प्रावधानों और अदालती फैसलों से सामाजिक बदलाव नहीं आ सकता है. उसके लिए समाज को भी सक्रिय होना आवश्यक है और समुदायों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होनी चाहिए. संगठित क्षेत्र में मुस्लिमों की उपस्थिति नगण्य है. मुस्लिम समुदाय के श्रम बल का बहुत बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है और वहां भी वह अधिकतर निचले पायदान पर है. वहां कमाई भी कम है और उसका औपचारिक भुगतान नहीं होता है. ऐसे में समुचित गुजारा भत्ता दे पाना आसान नहीं होता. गुजारा भत्ता मिलने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, इसके साथ-साथ विसंगतियों और समस्याओं का ठोस समाधान किया जाना चाहिए. तब सचमुच में सकारात्मक बदलाव आ सकेगा.

(ये लेखिका के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

चीन की अर्थव्यवस्था की राह में बाधाएं

कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जिन समस्याओं ने 'पीक चाइना' की कहानी को जन्म दिया, वे कई सालों से बन रही थी. टोरंटो यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर लॉरिन ब्रांट का कहना है, 'काफी ज्यादा उत्पादन क्षमता की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था 2000 के दशक की शुरुआत में तेजी से बढ़ी.' साल 1978 में तत्कालीन राष्ट्रपति डेंग शियाओपिंग के शासन में सुधार और खुलेपन की नीतियों की शुरुआत हुई थी. अगले तीन दशक में जीडीपी में बढ़ोतरी के लगभग 70 फीसदी हिस्से के लिए उत्पादकता का योगदान रहा. चीनी अर्थव्यवस्था की विशेषज्ञ ब्रांट कहती हैं, 'वित्तीय संकट के बाद से उत्पादन क्षमता कम हो गयी. अब यह 2008 से पहले की तुलना में शायद एक-चौथाई रह गयी है.' चीन पर नजर रखने वालों को उम्मीद थी कि अगले हफ्ते चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की अहम बैठक में कई अल्पकालिक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बड़े प्रोत्साहन उपायों का प्रस्ताव रखा जायेगा. अब उन्हें लगता है कि चीन इसके बजाय एडवांस और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने पर ध्यान देगा. साथ ही, पेंशन और निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देगा. चीन का कुल कर्ज उसकी जीडीपी के 300 फीसदी से ज्यादा हो गया है. इसका एक बड़ा हिस्सा स्थानीय सरकारों के पास है. लगातार 12 महीनों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट आ रही है. सिर्फ 2024 के पहले पांच महीने में ही 28.2 फीसदी की गिरावट आयी है. नयी तकनीकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारी निवेश के बावजूद चीन के कुछ व्यापारिक साझेदार चीनी आयातों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं. ब्रांट ने बताया कि 'यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, जिसने अनुसंधान और विकास के साथ-साथ लोगों और उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचे पर बहुत अधिक निवेश किया है. हालांकि, इसका उस तरह से लाभ नहीं उठाया जा रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि बनाये रखने में मदद मिल सके.'

बोधि वृक्ष

धन और स्वतंत्रता

धन हर किसी को आजादी और स्वामित्व की समझ देता है. हमें विश्वास है कि धन के साथ हम अपने लिए सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और किसी की सेवाओं का मूल्य लगा सकते हैं. किसी भी चीज के स्वामित्व का अर्थ उसके अस्तित्व पर पूर्ण नियंत्रण से लिया जाता है. जब हम जमीन का एक टुकड़ा खरीदते हैं, तब सोचते हैं कि हम उसके स्वामी हैं, यद्यपि जमीन का अस्तित्व स्वामी के न रहने के बाद भी रहेगा. ऐसे में हम उस चीज के स्वामी कैसे हो सकते हैं, जो हमारे बाद भी लगातार रहती है? धन हमें यह विचार भी देता है कि हम ताकतवर और स्वतंत्र हैं. यह विचार हमें इस तथ्य के प्रति अंधा करता है कि हम परस्पर निर्भरता की दुनिया में रहते हैं. हम किसानों, बावर्चियों, वाहन चालकों और आस-पास के कई लोगों की सेवाओं पर निर्भर रहते हैं. इसलिए हम इस तथ्य को अनदेखा कर देते हैं कि हम उन पर निर्भर हैं. आखिर क्यों धन के साथ लोग घमंडी हो जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धन स्वतंत्रता की भावना जागृत करता है.

दूसरी तरफ, निर्भरता की जानकारी व्यक्ति को विनम्र बनाती है. स्वतंत्रता की झूठी भावना द्वारा मानवता के आधारभूत गुण को दूर कर दिया गया है. हम धन को मानव से बढ़कर मूल्यवान नहीं मान सकते. संपत्ति कोई भी अपनी क्षमता, कुशलता, विरासत या भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त कर सकता है. संपत्ति पाने के तरीकों से उनके अपने परिणाम मिलते हैं. भ्रष्टाचार के लिए भी ठीक वही उद्देश्य शांति और प्रसन्नता है. फिर भी शांति और प्रसन्नता तब तक भ्रांति जनक रहते हैं, जब तक साधन भ्रष्ट होते हैं. इस प्रकार, धन का स्वामित्व स्वतंत्रता का भ्रम उत्पन्न करता है. धन को कई बार माया के रूप में भी संदर्भित करते हैं. दूसरी तरफ, कुछ लोग धन को ही समाज में व्याप्त तमाम बुराइयों के लिए दोषी मानते हैं. जिस प्रकार धन का स्वामित्व अहंकार लाता है, उसी तरह नकारना भी किसी को दंभी बना देता है. कुछ लोग जो धन का त्याग कर देते हैं, अपनी गरीबी में भी ध्यान और संवेदना प्रदर्शित करने के गर्व में रहते हैं.

-श्री श्री रवि शंकर

प्रबंध सूत्र

समय की धारा में सबको बहना है

आलोक पुराणिक
स्तंभकार
puranika@gmail.com

वे कहते थे कि वे भविष्य में एक्टिंग करेंगे और मरने से पहले बहुत बड़े एक्टर साबित होंगे. वे सरकारी अफसर थे. वे कहते थे कि वे भविष्य में एक उपन्यास लिखेंगे, जो धूम मचा देगा, मरने से पहले वे बहुत बड़े उपन्यासकार होंगे. वे प्रोफेसर थे. वे दोनों मर गये, बिना एक्टिंग किये हुए या बिना उपन्यास लिखे. इच्छाएं कामयाबी में तब तब्दील होती हैं, जब उनके बीच एक सटीक टाइम टेबल का पुल होता है. अधिकतर लोग इच्छाओं के साथ मर जाते हैं. इनमें से कई ऐसे होते हैं, जिनमें क्षमता थी, वे इच्छाओं को नतीजों में बदल सकते थे. आपकी हमारी मुलाकात कई ऐसे लोगों से होती है, जो अच्छी किस्सागोई करते हैं, ये लोग लिखते, तो कायदे के लेखक बन सकते थे.

क्षमता परिणाम नहीं लाती, कर्म से परिणाम आते हैं. यह बात कई लोग नहीं समझते. इच्छाओं के साथ जीना और सोचना कि कभी हम कामयाब बन जायेंगे, यह एक तरह से खुद को धोखा देना है. परिणाम के लिए प्रतिभाशाली से प्रतिभाशाली बंदे को अनुशासनबद्ध तरीके से टाइम टेबल के साथ काम करना होता है. ऐसे कई प्रतिभाशाली लोग हैं, जो कुछ समय तक काम कर पाते हैं, फिर गुम हो जाते हैं. समय की धारा में सबको बहना होता है, जो रुक जाते हैं, वे अनुशासन वाले लोग होते हैं, जिनके पास एक टाइम टेबल होता है. जो इच्छाएं टाइम टेबल में नहीं आतीं, वो सिर्फ जागी आंखों के सपने हैं, जिनका कोई परिणाम नहीं आता. कितने गंभीर हैं आप अपनी इच्छा को लेकर, इसका फैसला इससे होगा कि अपने चौबीस घंटे में कितने घंटे उस इच्छा को दे रहे हैं. हम में से हरेक के पास बहाने हो सकते हैं कि हम बिजी हैं, हमारे पास ये काम है, वो काम है, इसलिए हम अपनी उस इच्छा को वक्त नहीं दे पा रहे हैं.

ठीक है, आपके पास टाइम नहीं अपनी इच्छा के लिए, तो वह कभी तब्दील नहीं होगी परिणाम में. पर कई लोग बाद में शिकायत करने लगते हैं कि हम तो बहुत प्रतिभाशाली थे, पर नसीब हमारे साथ न था, या फलां उतना प्रतिभाशाली न था, पर देखो कितना आगे निकल गया. उसने टाइम टेबल बनाकर लगातार काम किया, यह बात आम तौर पर नहीं देखी जाती. हम में से कई के पास बेपनाह दौलत हो सकती है, पर वक्त बेपनाह नहीं है. चौबीस घंटे ही सबके पास हैं. उसमें से टाइम निकालकर टाइम टेबल पर लाना होता है. सीधी-सी बात है, पर बहुत मुश्किल बात है यह. जो इस सीधी-सी बात मुश्किल बात को साध लेते हैं, उनकी इच्छा परिणाम में तब्दील हो जाती है. बाकी तो अधिकतर लोग मरते वक्त नाकाम हसरतों का पुलिंदा ही होते हैं.

आपके पत्र

अफवाह से बढ़ रहा आपसी विद्वेष

महान दार्शनिक जेएच प्राइस ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह राजनीति में अभिरुचि नहीं रखता है. आज की राजनीतिक सर्वव्यापी है. लोग सोशल मीडिया पर अपने विचार रखते हैं. लेकिन, इनके विचार सोशल मीडिया पर आनेवाली गलत सूचना के कारण अक्रामक हो जाते हैं. इसका ध्यान रखना चाहिए इस तरह के विचार से समाज में वैमन्यसता बढ़ रही है. इसलिए अफवाहों की जांच कर ही अपने विचार दें. कभी भी ऐसी बात नहीं करें, जिससे समाज में विद्वेष फैले और दुश्मनी बढ़े.

अभिनव कुमार, बेगूसराय

ऑनलाइन ली जाये नीट की परीक्षा

नीट के पेपर लीक होने के बाद एनटीए की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं. इसलिए नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता आवश्यक है. हाल के वर्षों में परीक्षाओं में धोखाधड़ी और घोटाले की घटनाएं सामने आयी हैं, जिससे छात्रों पर बुरा असर पड़ा है. इसलिए नीट के लिए भी ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली अपनानी चाहिए. ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में प्रश्न समय पर और बिना किसी देरी के सीधे परीक्षा के समय पर ही आते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की धांधली की संभावना समाप्त हो जाती है.

पवन कुमार, गया

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • सोमवार • 15 जुलाई • 2024
www.rashtriyasahara.com

एनडीए को झटका

देश के सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के शनिवार को आए नतीजों में 'इंडिया' गठबंधन के घटक दलों ने भाजपा को करारा झटका देते हुए 10 सीटें जीत लीं। भाजपा दो सीट ही जीत सकी जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई। पश्चिम बंगाल की चार, हिमाचल प्रदेश की तीन, उत्तराखंड की दो, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु की एक-एक सीट के लिए चुनाव हुआ था। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, 'आप', टीएमसी और द्रमुक ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। नतीजों से इंडिया गठबंधन के घटक दल गद्गद् हैं, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने नतीजों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दावा कि लोगों ने

भाजपा के अहंकार, कुशासन और नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है और नतीजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की गिरती राजनीतिक साख का प्रमाण हैं। खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट करके इन नतीजों पर मतदाताओं का आभार जताया है। खास बात यह रही कि उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब में जनता ने पाला बदलने वाले नेताओं को नकार दिया। उत्तराखंड की दोनों सीटें कांग्रेस ने जीत लीं। सर्वाधिक चर्चा प्रसिद्ध तीर्थस्थल बद्रीनाथ सीट की है, जहां कांग्रेस अपनी सीट बरकरार रखने में सफल रही। यहां भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस के सिटिंग विधायक थे लेकिन पाला बदल कर भाजपा में जा मिले। भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया लेकिन कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने उन्हें पराजित कर दिया। हिमाचल प्रदेश में भी रोचक परिदृश्य उभरा है। देहरा सीट से मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की पत्नी कमलेश जीतीं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को हराया। प्रदेश में पहली बार होगा जब पति-पत्नी सदन में साथ होंगे। कांग्रेस के विधायक 40 हो गए हैं, जबकि भाजपा की 28 सीटें हैं। फरवरी में राज्य सभा चुनाव के वक्त विधायकों की बगावत से कांग्रेस की सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे थे, जो टल गया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा क्षेत्र में भाजपा ने कांग्रेस को फिर झटका देते हुए अमरवाड़ा सीट जीत ली। पश्चिम बंगाल में दीदी का जलवा कायम है, और टीएमसी ने चारों सीटें जीत लीं। भाजपा से तीन सीटें छीनी हैं। बेशक, नतीजे भाजपा के लिए खतरे की घंटी हैं, जिनका उप्र में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव तथा हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के आसन्न असेंबली चुनाव पर निश्चित असर दिखेगा।

तुरंत हटाएं अवरोधक

सर्वोच्च अदालत ने हरियाणा सरकार से अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर लगाए अवरोधक हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने राजमार्ग को अवरुद्ध करने के अधिकार पर भी प्रश्न उठाए। कोई राज्य हाईवे को कैसे बंद कर सकता है। यातायात नियंत्रित करने को उसका दायित्व बताते हुए अदालत ने कहा कि किसान भी देश के नागरिक हैं। उन्हें खाना दीजिए, चिकित्सकीय देखभाल कीजिए। पीठ ने कहा वे आएंगे, नारे लगाएंगे, वापस चले जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा द्वारा फसलों के न्यूनतम समर्थन

मूल्य की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली चलो की घोषणा के बाद हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग में बैरीकेड्स लगा दिए थे। शीर्ष अदालत हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। जैसा कि फरवरी में प्रदर्शनकारी किसानों और हरियाणा के सुरक्षाकर्मियों के दरम्यान हुई झड़प में हुई किसान की मौत की जांच के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में पैनल गठित करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार का कहना है कि 400-500 किसान पंजाब की तरफ बैठे हैं। सबसे बड़ी अदालत की नाराजगी उस यातायात अव्यवस्था के कारण है, जिससे जनता को हर रोज जूझना पड़ता है। इस पर हैरत नहीं होती कि सरकारें किस बेरुखी से व्यस्त सड़कों पर अवरोधक लगाने के आदेश जारी कर देती हैं। पांच महीनों से ऐसी सड़क को बाधित रखना, जिसका प्रयोग ढेरों लोग नियमित तौर पर करते हैं। यहां तो किसानों के उग्र आंदोलन की दलील दी जा सकती है जबकि देखने में आता है कि राजनेताओं की सुविधा और उनके कार्यक्रमों के मद्देनजर देश भर में अवरोधकों के धड़ल्ले से उपयोग होते रहते हैं। अदालतों की कड़ी टिप्पणियों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकारी आदेशों या नियमों के विरोध का हक नागरिकों से छीना नहीं जा सकता। उन्हें काबू में रखने के तरीके मानवीय और व्यावहारिक भी हो सकते हैं। बात नाराज किसानों की ही नहीं है, बल्कि सड़क को लंबे समय तक बंद रखने और वैकल्पिक व्यवस्था देने में कोताही की भी है। उम्मीद की जानी चाहिए अदालत के इस आदेश से सरकारें सीख लेंगी और भविष्य में अवरोधकों का बेजा प्रयोग थम जाएगा।

कौशल दिवस/योगेश कुमार गोयल

युवाओं को रोजगार जरूरी

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रासंगिक अन्य कौशलों के विकास के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 15 जुलाई को 'विश्व युवा कौशल दिवस' मनाया जाता है। दरअसल, पूरी दुनिया आज कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनमें से कई चुनौतियां खासकर युवा वर्ग को बहुत प्रभावित करती हैं। यह दिवस युवाओं और 'तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण' (टीवीईटी) संस्थानों, फर्मों, नियोक्ताओं, श्रमिक संगठनों, नीति-निर्माताओं तथा विकास भागीदारों के बीच संवाद का महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। लैंगिक असमानता को समाप्त करने तथा कमजोर लोगों तक संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित करने में भी खास माना जाता है।

आंकड़ों के मुताबिक, पूरी दुनिया में 200 मिलियन से भी ज्यादा युवा या तो बेरोजगार हैं, या उनके पास नौकरी तो है लेकिन वे गरीबी में जी रहे हैं। 1997-2017 के बीच युवा आबादी में 139 मिलियन की वृद्धि हुई, वहीं युवा श्रम बल में 58.7 मिलियन की कमी आई। वैश्विक स्तर पर अधिकांश युवा अभी भी स्थिर या संतोषजनक नौकरी पाने के लिए औसतन 13.8 महीने तक प्रतीक्षा करते हैं, जो शिक्षा से नौकरी तक कठिन संक्रमण को दर्शाता है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती युवा बेरोजगारी आज की अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए विश्व युवा कौशल दिवस का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की चुनौतियों के संदर्भ में युवाओं के लिए बेहतर सामाजिक-आर्थिक हालात पैदा करना है। केंद्र सरकार की ऐसी ही महत्त्वपूर्ण पहल है 'कौशल भारत', जिसके जरिए युवाओं को आवश्यक कौशल से लैस करने के प्रयास किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस का कहना है कि न केवल आज, बल्कि हर दिन शिक्षा को बदलने के लिए काम करते हुए यह सुनिश्चित करने के भी प्रयास होने चाहिए कि युवाओं के पास वह सब कुछ हो, जो उनके लिए अधिक शांतिपूर्ण, टिकाऊ भविष्य को आकार देने वाला और उनका कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक है। अब चूंकि विभिन्न उद्योगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों का तेजी से उपयोग कार्य के परिदृश्य को बदल रहा है, इसलिए भविष्य की नौकरियों के लिए युवाओं को तैयार करने के मद्देनजर उन्हें आवश्यक एआई कौशल से लैस करना जरूरी हो गया है।

अनमोल वचन

अपने सारथी, पहरेदार, रसोईया और भाई के शत्रु मत बनो। ये सारे आपको किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं।
-रावण

बेवजह का विरोध

डिजिटल अटेंडेंस
अमित भनोट

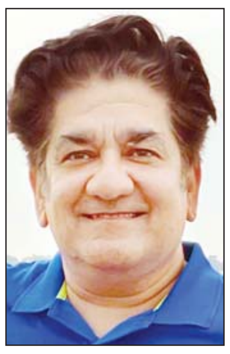

आज हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां चाय, ब्रेड, दूध आदि जैसे रोजमर्रा के खर्चों और खरीदारी के लिए डिजिटल मोड जनता की पहली पसंद बन चुका है। अमेजॉन के एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि ऑनलाइन खरीदारी के लिए जहां 90 प्रतिशत भुगतान डिजिटली किया जा रहा है वहीं स्टोर्स में भी डिजिटल भुगतान 50 प्रतिशत जनता की पहली पसंद बन गया है।

देश में डिजिटल क्रांति ने जीवन के हर पहलू को न सिर्फ छुआ है, बल्कि बदल कर रख दिया है। ऐसे में जब हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा परिषदीय स्कूलों में लागू की गई डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था का प्रदेश के शिक्षकों द्वारा यह कहते हुए विरोध हो रहा है कि यह 'अव्यावहारिक' है, तो निश्चिय ही आश्चर्य होता है। कोई बड़ी बात नहीं कि विरोध कर रहे शिक्षकों के मोबाइल में भुगतान करने के लिए 'भीम एप', मनोरंजन के लिए ओटीटी ऐप, खाना ऑर्डर करने के लिए 'डिलीवरी एप', खरीदारी के लिए भी विभिन्न ऐप पहले से ही मौजूद हों। ऐसे में सिर्फ डिजिटल अटेंडेंस का विरोध करना खुद ही व्यावहारिक नहीं लगता। योगी सरकार ने 8 जुलाई से सभी परिषदीय स्कूलों में मौजूद सभी 12 रजिस्टरों को डिजिटल करने का फैसला लिया है, और सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इसे सख्ती से लागू करवाने का निर्देश दिया है। इन्हीं रजिस्टरों में शिक्षकों की अटेंडेंस का रजिस्टर भी शामिल है, जिसमें फेस रिकग्निशन के जरिए स्कूल परिसर में ही स्कूल खुलने और बंद होने के 15 मिनट पहले और बाद में हर शिक्षक को अपनी उपस्थिति टैब के जरिए डिजिटली दर्ज करानी है।

नई व्यवस्था के विरोध को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इसमें 30 मिनट का ग्रेस टाइम भी दे दिया है। इसी व्यवस्था का विरोध यह कहते हुए हो रहा है कि इसमें व्यावहारिक दिक्कतें हैं, वहीं बरसात में मौसम और आकस्मिक स्थिति में शिक्षक द्वारा इस व्यवस्था का अनुसरण करना संभव नहीं होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह विरोध सिर्फ इसलिए है कि इसमें कुछ दिक्कतें आएंगी या फिर किसी और चीज की पर्दादारी है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। एक ओर तो प्रदेश के 133035 प्राथमिक, कंपोजिट और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हमेशा ही बनी रहती है वहीं जो शिक्षक हैं भी, उनमें से कई, स्कूलों में नहीं आते हैं, या सिर्फ एक बार रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज कर, निकल लेने की फिराक में रहते हैं।

राज्य के शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में प्रदेश में कुल 453594 शिक्षक थे जबकि 126028 पद रिक्त हैं, ऐसे में यदि मौजूद शिक्षक भी विद्यालय न आएं तो शिक्षा

की स्थिति समझी जा सकती है। यह सीधे-सीधे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यदि हमें प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करनी है तो सरकार को व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। डिजिटल रजिस्टर उसी दिशा में उठाया गया कदम जान पड़ता है। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोग के लिए 2,09,863 टेबलेट्स उपलब्ध कराए गए हैं। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए टेबलेट उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया जारी है।

निर्देशों के अनुसार समस्त अध्यापक 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक आगमन उपस्थिति प्रातः 7.45 से 8 बजे तक और प्रस्थान दोपहर 2.15 से 2.30 बजे तक लगाएंगे। एक अक्टूबर से 31 मार्च तक आगमन उपस्थिति सुबह 8.45 बजे से सुबह नौ बजे तक और प्रस्थान उपस्थिति 3.15 बजे से 3.30 बजे तक दर्ज कर सकेंगे। एक प्रश्न हमें और शिक्षकों को खुद से भी पूछना चाहिए। यदि पुरानी फिजिकल रजिस्टर वाली व्यवस्था दुरुस्त थी तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा की स्थिति ऐसी क्यों है? 2023-24 में 2022-23 की तुलना में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों में छात्रों की संख्या में 24 लाख से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, जो चौंकाने वाला आंकड़ा है। 2023-24 में इन स्कूलों में छात्रों की संख्या 16784645 थी जो पिछली बार से 24 लाख कम है। यह तब है जब कोरोना काल में घटती आमदनी के चलते सरकारी स्कूलों में छात्रों का पंजीकरण खासा बढ़ा था। घटती संख्या के पीछे मुख्य कारण यह भी है कि शिक्षक पढ़ाने आते ही नहीं। ऐसे में डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था इसमें अपेक्षित सुधार ला सकती है। डिजिटल व्यवस्था के विरोध में एक बात और कही जा रही है कि यह ऐप कई बार शिक्षक की लोकेशन स्कूल से अलग कहीं और दिखाता है। डिजिटल दुनिया में शुरुआती समय में कई बार ऐसा होता है लेकिन यह कमी किसी भी ऐप में समय के साथ ठीक की जा सकती है, लेकिन इसके लिए पूरी व्यवस्था को अव्यावहारिक कह कर नकार देना कतई सही नहीं है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दोनों स्तरों में लगातार सुधार जारी हैं, वहीं जरूरत के अनुसार नियमों में रियायतें भी दी जा रही हैं। आधे घंटे का 'ग्रेस' इसी दिशा में उठाया गया कदम है।

अगर समग्र रूप से देखें तो किसी भी राज्य की शिक्षा व्यवस्था सीधे हमारे मानव संसाधन के भविष्य से जुड़ाव रखती है, और समय के साथ इसमें बदलाव विकसित भारत के सपने को साकार करने में अहम है। यदि प्रदेश का शिक्षा तंत्र और शिक्षक अपने ध्येय का बखूबी पालन करते हैं, तो इसका सकारात्मक असर सीधे प्रदेश की प्रोडक्टिविटी पर तो होगा ही, वहीं हम बेहतर नागरिकों का निर्माण भी करेंगे। इसे देखते हुए एक समाज के तौर पर हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को पूरी गंभीरता से लेना चालिए। हमें ऐसे शिक्षा के मंदिरों का निर्माण करना है जहां स्कूल में हमारे बच्चों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं हों, शौचालयों की व्यवस्था हो, मिड डे मील के रूप में भोजन की उचित व्यवस्था हो, पक्का स्कूल हो, बैठने के लिए डेस्क हो, कॉपी-किताबें हों और सबसे महत्त्वपूर्ण उचित संख्या में शिक्षक हों, जो विद्यालय में समय से आएं और बच्चों को शिक्षित कर विकसित भारत का निर्माण करने में सहयोग करें जिसके लिए डिजिटल प्रक्रिया क्रांतिकारी कदम है। सभी शिक्षकों को आगे आकर डिजिटल प्रक्रिया का स्वागत करना चाहिए, वहीं प्रदेश सरकार को भी चाहिए कि शिक्षकों की मांग पर ध्यान दे और इस ऐप में सभी व्यावहारिक स्थितियों जैसे कनेक्टिविटी, टैगिंग, जीपीएस लोकेशन संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए जरूरी बदलाव लगातार करे।

हमें ऐसे शिक्षा के मंदिरों का निर्माण करना है जहां स्कूल में हमारे बच्चों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं हों, शौचालयों की व्यवस्था हो, मिड डे मील के रूप में भोजन की उचित व्यवस्था हो, पक्का स्कूल हो, बैठने के लिए डेस्क हो, कॉपी-किताबें हों और सबसे महत्त्वपूर्ण उचित संख्या में शिक्षक हों, जो विद्यालय में समय से आएं और बच्चों को शिक्षित कर विकसित भारत का निर्माण करने में सहयोग करें जिसके लिए डिजिटल प्रक्रिया क्रांतिकारी कदम है

- भारत में सोने के आयात का सबसे बड़ा स्रोत स्विटजरलैंड है जिसकी हिस्सेदारी लगभग 40 फीसद है। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात की हिस्सेदारी 16 फीसद और दक्षिण अफ्रीका की हिस्सेदारी 10 फीसद है
- चीन के बाद भारत दुनिया में सोने का दूसरा बड़ा उपभोक्ता है। यह आयात मुख्य रूप से आभूषण उद्योग की मांग पूरा करता है। मजबूत घरेलू मांग रहने से देश में सोने का आयात 2023-24 में 30 फीसद बढ़कर 45.54 अरब डॉलर का हो गया

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला बताता है कि अतिरेकी-भेदभाव और अति-ध्रुवीकरण से हिंसा पैदा होती है। किसी भी लोकतंत्र पर यह सच लागू होता है। लेकिन अमेरिका में बंदूक संस्कृति और बंदूक हिंसा का माहौल है, जहां आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, लोगों की संख्या से ज्यादा बंदूक हैं।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक
@Chellaney

मुद्दा | **डॉ. असद रजा**

जनसंख्या समस्या और समाधान

जुलाई 12 से 31 तक विश्व में विशेष रूप से हमारे देश में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाया जा रहा है जिसमें जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए जागरूकता रैलियां निकाली जा रही हैं। जनसंख्या वृद्धि की समस्या के समाधान के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के बयान आए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तथा भाजपा बिहार के राज्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए परंतु एनडीए के घटक दल जदयू के नेता इस बारे में कठोर कानून बनाने का समर्थन नहीं करते क्योंकि उन्हें दलित और मुस्लिम मतदाताओं के बिदकने का भय है।

वास्तव में जदयू और टीडीपी जैसे मोदी सरकार के घटक दलों को चिंता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करने से उनका मुस्लिम और दलित वोट खिसक सकता है। इसलिए ये दल परिवार नियोजन के लिए जन-जागरूकता पर बल देते हैं। कुछ अति धर्मभीरु और मजहबी लोग बच्चों को अल्लाह की देन समझते हैं। मानते हैं कि अन्न-भोजन देने की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी है। इसलिए जनसंख्या को रोकने के लिए कठोर कानून की जरूरत नहीं है परंतु यह तर्क नहीं, कुतर्क है। ऐसा होता तो अफ्रीका आदि क्षेत्रों में लोग भूख से क्यों मरते? निश्चय ही हमारा देश विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। हमने इस मैदान में चीन को भी पछाड़ दिया है, और आज एक अरब 45 लाख से अधिक आबादी का बोझ उठा रहे हैं। बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण तथा अपराध में वृद्धि का एक प्रमुख कारण आबादी में भारी इजाफा भी है। देश में बढ़ती सांप्रदायिकता और घृणा का एक बड़ा कारण भी जनसंख्या में वृद्धि है। बहुसंख्यक हिन्दू आबादी मुसलमानों की बढ़ती आबादी को खतरा मानती है। उनमें से कुछ का यह भी मानना है कि भविष्य में भारत भी पाकिस्तान की भांति इस्लामी राष्ट्र बन सकता है। यद्यपि यह काल्पनिक भविष्याणी है क्योंकि देश में मुसलमानों में भी बच्चों की जन्म दर कम हुई है परंतु हिन्दुओं में यह दर अधिक कम हुई है। कई अदूरदर्शी मौलवी तथा मुस्लिम नेता भी जनसंख्या रोकने के लिए कड़े कानून का विरोध करके

हिन्दुओं की आशंका को मजबूत करते हैं। भाजपा सहित संघ परिवार के सभी संगठन तथा उदारवादी मुसलमान जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्षधर हैं परंतु इस तथ्य की भी अवहेलना नहीं की जा सकती कि उच्च और मध्यम वर्ग के हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन के परिवार साधारणतया दो या तीन बच्चों तक सीमित होते हैं क्योंकि उन्हें अपने बालकों को उत्तम शिक्षा दिला कर सफल नागरिक बनाना होता है, उन्हें पौष्टिक भोजन तथा साफ-सुथरा घर और वस्त्र उपलब्ध कराने होते हैं जबकि निम्न वर्ग के लोग चूंकि अशिक्षित या अर्धशिक्षित होते हैं, और उनके लिए मनोरंजन का एकमात्र साधन सैक्स होता है। अतः वे अधिक बच्चे पैदा करते हैं तथा उन्हें उनकी शिक्षा दीक्षा की चिंता नहीं होती अपितु वे अपने आठ दस वर्ष के बालक को किसी ढाबे पर काम पर लगा देते हैं, और बालक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाता है। चूंकि मुसलमान, दलित और आदिवासी ही अधिकतर गरीब और आर्थिक-सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं, इसलिए उनके ही अधिक बच्चे होते हैं। निस्संदेह मोदी सरकार को कठोर जनसंख्या कानून बनाना चाहिए परंतु कटु सत्य यह भी है कि संसद में ऐसा सख्त कानून पास कराना कठिन होगा क्योंकि मौजूदा संसद में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। इसलिए कोई कानून पास कराने के लिए उसे सहयोगी दलों विशेष रूप से जदयू और टीडीपी का समर्थन लेना होगा परंतु दोनों दल मुस्लिम और दलित वोटर को दृष्टि में रखते हुए कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून को शायद समर्थन न दें।

इसलिए इस कानून को भाजपा शासित प्रदेशों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ आदि की विधानसभाओं में पास कराके सख्ती से लागू कराना होगा। प्रावधान करना होगा कि कानून लागू होने के बाद राशन कार्ड केवल चार व्यक्तियों यानी माता, पिता व दो बच्चों का ही बनेगा और दो बच्चों को जन्म देने के पश्चात पति या पत्नी में से किसी एक को नसबंदी करानी होगी अथवा लिखित में सरकार को आश्वासन देना होगा कि भविष्य में तीसरा बालक पैदा नहीं करेंगे। तीसरा बच्चा पैदा करने वाले माता-पिता को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। वैसे राजस्थान में कानून है कि दो से अधिक बच्चों वाले माता-पिता को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार को यह कानून तो बनाना ही चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रति दिन सुबह, दोपहर और रात्रि में दस सेकंड का परिवार नियोजन से संबंधित सरकार द्वारा तैयार किया हुआ विज्ञापन आवश्यक रूप से दिखाए तथा हर भाषा के दैनिक अखबार को परिवार नियोजन का विज्ञापन अनिवार्य रूप से प्रकाशित करना होगा।

कुरीतियां | **श्रीराम शर्मा आचार्य**

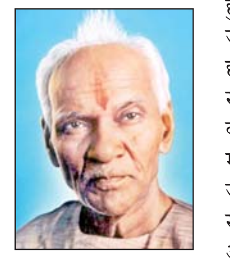

हम अपनी सामाजिक कुरीतियों पर ध्यान दें तो लगता है कि लोहे की गरम सलाखों से बनी हुई जंजीरों की तरह वे हमें जकड़े हुए हैं और हर घड़ी हमारी नस-नस को जलाती रहती हैं। घर में तीन-चार कन्याएं जन्म ले लें तो माता-पिता की नींद हराम हो जाती है। आजकल साधारण नागरिकों की आमदनी इतनी ही मुश्किल से हो पाती है कि अपना पेट पाल सकें। ऐसे में सामान्य नागरिक के लिए उतना धन जमा करना कैसे संभव हो सकता है, जितने की कन्या के विवाह में जरूरत पड़ती है-मांगा जाता है। यह संकट कौन कन्या का पिता किस पीड़ा और चिंता के साथ पार करता है, इसके पीछे लंबी करुण कहानी छिपी रहती है। कर्ज का ब्याज, भावी जीवन में अंधेरा, शेष बच्चों की शिक्षा एवं प्रगति में गतिरोध जैसी आपत्तियों को कन्या का विवाह अपने पिता, छोटे भाई-बहिनों के लिए छोड़ जाता है। विवाह का पत्थर छाती पर से हटा तो अर्थ संकट का आरा अपनी काट शुरू कर देता है। मृत्यु एक दिन कष्ट देकर शांति की गोद में सुला देती है पर यह जीवित मृत्यु तो पग-पग पर काटती, नोचती, छेदती और चीरती रहती है। हिन्दू समाज में विवाह-शादी के अवसर पर जैसा अंधापन और बावलापन छा जाता है उसे देखकर हैरत होती है। पृथ्वी के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक घूम जाइए, कोई भी देश, धर्म, समाज ऐसा न मिलेगा जहां विवाह-शादियों के अवसर पर पैसे की ऐसी होली जलाई जाती हो जैसी हमारे यहां जलाई जाती है। बरात की निकासी, आतिशबाजी, बाजे, नाच, स्वांग, दावत, जाफत देख कर लगता है कि शादी वाले कोई लखपति, करोड़पति हैं, और अपने अनाप-शनाप पैसे का कोई उपयोग न देख उसकी होली जला देने पर उतर आए हैं। जिन्हें अपने बच्चों का लालन-पालन और शिक्षण दुर्लभ है वे यदि ऐसे स्वांग बनावें जैसे कि विवाह के दिनों में आम तौर से बनाए जाते हैं तो उसे समझदारी की कसौटी पर केवल 'उन्माद' ही कहा जा सकता है। सारी दुनिया में कहीं भी ऐसा 'सत्यानाशी विवाहोन्माद' नहीं देखा जाता। मामूली-सी रस्म की तरह, बहुत छोटे घरेलू उत्सव की तरह लोग विवाह-शादी कर लेते हैं। भार किसी को नहीं पड़ता, तैयारी किसी को नहीं करनी पड़ती। पर एक हम हैं, जिनके जीवन में बच्चों का विवाह ही जीवन भर भारी समस्या बना रहता है, और इसी उलझन को सुलझाते-सुलझाते मर-खप जाते हैं।

रीडर्स मेल

तेल सरसों में बढ़ती मिलावट

इन दिनों खाने के तेलों खासकर सरसों के तेल में मिलावट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आए दिन इस तरह के समाचार देखने और सुनने को मिल रहे हैं। सरसों के तेल में मिलावट की वजह से होने वाले रोगों को ड्रॉप्सी कहा जाता है। ड्रॉप्सी का पहला मामला सन 1877 में बंगाल में सामने आया था। हालांकि इस रोग का उत्तर भारत में प्रकोप ज्यादा था, जहां सरसों के तेल का प्रमुख रूप से सेवन किया जाता है। असल में आपको किसी भी तरह का तेल खरीदते समय बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी कंपनी के दावों के झांसों में आकर तेल मत खरीदिए। किसी भी ब्रांड का तेल अधिक मात्रा में खरीदने से पहले थोड़ा जान लीजिए और स्वाद तथा गुणवत्ता जांचने के बाद ही अधिक मात्रा में खरीद कीजिए। तेल खरीदने से पहले सतर्कता बरतने से ही मिलावटी तेलों से बचा जा सकता है। मिलावटी तेल आपके परिवार के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए चिंता करना जरूरी है। सस्ते के फेर में मत पड़िए, क्योंकि यह बाद में आपको बहुत महंगा पड़े सकता है। अच्छा चुनिए, अच्छा खाइए। इस तरह आप खुद को और अपने परिवार को तेल में मिलावट के 'खेल' से बचा पाएंगे और यह 'खेल' इन दिनों ही नहीं, बल्कि बहुत पहले से चला आ रहा है।

अमित बैजनाथ गर्ग, जयपुर

शराब घोटाला साजिश है या...

आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार करने के जो आरोप लगे हैं, वे अभी जांच की प्रक्रिया के हिस्सा हैं। जांच होने के बाद ही यह तय हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। दिल्ली के शराब घोटाले में जिस प्रकार से साजिश की बात कही जा रही है, उससे यह तो कहा जा सकता है कि इसमें साजिश हो सकती है क्योंकि अगर मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य सूत्रधार साबित होते हैं, तो यह भी एक साजिश ही मानी जाएगी, लेकिन अगर केजरीवाल को फंसाया गया है तब तो यह और भी गंभीर साजिश कही जाएगी। फिलहाल, इस मामले में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा क्योंकि अब यह मामला बहुत ही गंभीर हो गया है जिसकी परतें उधड़ना बाकी है। अंदर क्या निकलता है, इसे देखने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी और हां, इसमें राजनीतिक गुणा-भाग तो नहीं ही किया जाना चाहिए।

सुरेश हिन्दुस्तानी, ई मेल से

आपातकाल का वो समय

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून, 1975 को लगाया गया आपातकाल आजादी के बाद देश के इतिहास का सबसे बड़ा काला अध्याय है। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, प्रेस और न्यायपालिका की आजादी भी समाप्त हो गई थी। 21 महीने के आपातकाल के दौरान लोगों को आजादी में भी गुलामी का अहसास होने लगा था। अब केंद्र सरकार ने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस लोक सभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने भाजपा से संविधान को खतरा बताया एवं अपने आप को संविधान का रक्षक। चुनाव के दौरान कांग्रेस को इस दुष्प्रचार का लाभ मिला एवं भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। भाजपा कांग्रेस के दुष्प्रचार को समाप्त करने में जुट चुकी है, इसलिए कांग्रेस को सरकार का यह कदम उसे रास नहीं आ रहा है। लेकिन हकीकत में यह कदम उठाया जाना बेहद जरूरी है।

ई हिमांशु शेखर, गया

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्त्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 331
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। । समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

आबादी और संसाधनों में बेहतर तालमेल जरूरी

विश्व जनसंख्या दिवस पर जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भारत के लिए आने वाले समय में नई चुनौतियों के संकेत दे रही है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि भारत की आबादी 2060 के दशक की शुरुआत में करीब 1.7 अरब तक पहुंच सकती है। इसके बाद 12 फीसदी की गिरावट के बावजूद यह पूरी सदी के दौरान दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा। भारत सरकार की ओर से जारी प्रजनन दर के आंकड़े इस लिहाज से राहत देने वाले हैं कि देश के 36 में से 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) गिरकर 1.91 (प्रति महिला बच्चों का जन्म) पर आ गई है।

प्रजनन दर की यह गिरावट बड़ी उपलब्धि है। पचास के दशक में जब टीएफआर 6.4 थी, बढ़ती आबादी देश के लिए चिंता के बड़े कारणों में से एक थी। यह परिवार नियोजन के कार्यक्रमों का सुखद परिणाम है कि टीएफआर लगातार घटती गई। अब यह 1990 के 4.6 से भी काफी नीचे है। संयुक्त राष्ट्र की संभावना रिपोर्ट में भारत की मौजूदा टीएफआर को आधार बनाया गया या नहीं, स्पष्ट नहीं है। भारत की आबादी को लेकर विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संगठन जो रिपोर्ट जारी करते रहे हैं, उनमें 2011 की जनगणना को पूर्वानुमानों का आधार बनाया जाता है। उस जनगणना के बाद के अधिकृत आंकड़े किसी के पास नहीं हैं। भारत में हर दस साल में होने वाली जनगणना 2021 में कोरोना के कारण टालनी पड़ी थी। अब जनगणना जल्द से जल्द कराने की जरूरत है, ताकि देश की आबादी को लेकर तस्वीर साफ हो सके। वैसे भी जनगणना के आधार पर ही सरकार की विभिन्न योजनाएं आकार लेती हैं। दरअसल, बढ़ती आबादी अब भारत के लिए उस तरह की चिंता का कारण कतई नहीं है, जिससे हम पचास-साठ साल पहले जूझ रहे थे। संतोषजनक प्रजनन दर का स्तर हम हासिल कर चुके हैं। इसमें गिरावट को लेकर हमारे सामने वैसी समस्याएं भी नहीं हैं, जिनसे चीन और जापान जैसे देश दो-चार हो रहे हैं। चीन में प्रजनन दर 1.2 और जापान में 1.3 तक गिरने के बाद वहां की सरकारों को आबादी बढ़ाने के लिए तरह-तरह की प्रोत्साहन योजनाएं चलानी पड़ रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र के पूर्वानुमान पर भरोसा किया जाए तो अभी से संसाधनों के विस्तार की दीर्घकालिक योजनाएं बनाने की जरूरत है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन आदि से जुड़े बुनियादी ढांचे का विस्तार करना होगा। प्रजनन दर की तरह गरीबी पर भी अंकुश की कोशिश होनी चाहिए। आबादी बढ़ने की स्वाभाविक प्रकिया के बीच आबादी और संसाधनों में बेहतर तालमेल की जरूरत है।

विश्व युवा कौशल दिवस आज: नकारात्मक इस्तेमाल पर नियंत्रण करके ही मिलेगा कौशल का सुपरिणाम

युवा कौशल है विश्व शांति का रास्ता

सुशील कुमार
भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और बिहार पुलिस अकादमी में सहायक निदेशक के तौर पर कार्यरत
@patrika.com

शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने, जिम्मेदार वैश्विक नागरिक बनाने और स्थायी और सतत विकास के लिए युवाओं को आवश्यक कौशल से लैस करने और उस कौशल के इस्तेमाल से एक शांतिपूर्ण, समावेशी, मानवीय और विकासशील दुनिया का निर्माण हमारी प्राथमिकता होना चाहिए।

मानव सभ्यता के विकास में कौशल और श्रम का महत्त्वपूर्ण योगदान है। पहली बार आग के आविष्कार से लेकर आज कृत्रिम बुद्धि (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के इस्तेमाल तक की यात्रा हमारे कौशल और श्रम का प्रतिफल ही तो है। इसमें सबसे उत्पादक वर्ग समूह युवाओं का ही है। उनके कौशल और श्रम की बदौलत ही देश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर पाते हैं। आज विश्व युवा कौशल दिवस है और संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को शांति और विकास के लिए युवा कौशल के तौर पर मनाने का निर्णय किया है।

मुश्किल यह है कि दुनिया भर में नई तकनीकों के इस्तेमाल से मानव जीवन को ज्यादा सुगम और सुविधाजनक बनाने की होड़ मची है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा हमारे जीवन और समाज में कटुता, वैमनस्यता और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किए जा रहे नकारात्मक आविष्कारों और प्रवृत्तियों की ओर खींच रही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किए गए इस दिवस का उद्देश्य विश्व स्तर पर युवाओं को रोजगार, काम और उद्यमिता के लिए महत्त्वपूर्ण कौशलों से लैस करना है। आज विश्व के कई देश युद्ध में फंसे हैं। रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध तो चल ही रहा है, इजरायल पर हमास के हमले के बाद फिलिस्तीनी इलाके भी इजरायली हमले झेल रहे हैं। मध्यपूर्व में फारस की खाड़ी के कई देशों में युद्ध जैसे हालात हैं, वहां महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की जिंदगी खतरे में हैं। ऐसे में आवश्यक है कि शांति निर्माण और संघर्ष सुलझाने में युवाओं और उनके कौशल की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो। संयुक्त राष्ट्र ने इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर 2024 को शांति और विकास के लिए युवा कौशल के वर्ष के तौर पर मनाने का आह्वान किया है। दुनिया भर में मानवता का भविष्य युवाओं के हाथ में है। यह इस बात पर ज्यादा निर्भर है कि वे अपने अर्जित कौशल और हुनर का इस्तेमाल आज की चुनौतियों से जूझने में कैसे करते हैं और एक शांतिपूर्ण कल कैसे गढ़ते हैं। डिजिटल क्रांति के इस दौर में वे सूचना के स्तर पर बहुत जल्दी सारी दुनिया से जुड़ सकते हैं। ऐसे में बजाय इसके लिए किसी की व्यक्तिगत या संस्थागत मानहानि, देशों के सामरिक नुकसान और शांति प्रक्रियाओं को तोड़ने और झकझोरने वाले कदम उठाने के, वे अपने कौशल और क्षमताओं का उपयोग भविष्य के लिए शांति और सद्भावनापूर्ण दुनिया के निर्माण में करें। कोविड के बाद दुनिया में डिजिटल संसाधनों के उपयोग के कई नए और अनदेखे स्वरूप सामने आए। इसका योगदान सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हैं। इससे दुनिया भर की तकनीकें तुरंत एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाई जा सकती हैं। कोविड के समय दुनिया भर में उससे निपटने के तरीके, अर्थव्यवस्था के जीर्णोद्धार के लिए तकनीकें सीखने और उनके इस्तेमाल में डिजिटल माध्यम ने बड़ा योगदान किया है। इसके साथ ही कुछ नकारात्मक परिवर्तन भी हुए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर दूसरे धर्मावलम्बियों को टारगेट करने, फर्जी खबरें और सामग्रियां प्रकाशित और पोस्ट करने से नफरत, आपसी भेदभाव और गैर बराबरी को बढ़ावा ही मिला है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में अनुमानतः 27.2 प्रतिशत जनसंख्या 15-29 आयु वर्ग के युवाओं की है जो करीब 38 करोड़ होती है। इन युवाओं में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं का एक बड़ा वर्ग है। भारत सरकार ने नवम्बर 2014 में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की स्थापना की जिसका उद्देश्य कौशल विकास के सभी प्रयत्नों का समावेशन और समन्वय के साथ ही कौशल विकास के नए आयामों की स्थापना और उनका उन्नयन है। देश में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के अलावा 1950 से ही इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट(आइटीआइ) भी बड़ी संख्या में स्थापित किए गए। इसके अलावा कौशल विकास केन्द्रों से प्रशिक्षित करोड़ों युवा हमारे देश के विकास को गति दे सकते हैं और हमारे शांतिपूर्ण, मानवीय और सद्भावपूर्ण विकास के एजेंडे को सामने रखकर दुनिया में अपनी पताका फहरा सकते हैं। विकास और तकनीक के नकारात्मक इस्तेमाल पर नियंत्रण करके ही अपने कौशल का सुपरिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आज देश में प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बनते हैं लेकिन उनमें से सिर्फ ढाई लाख ही कोर तकनीकी कार्यों में नौकरी पाते हैं, आखिर बाकी के साढ़े बारह लाख लोग हर साल क्या करने लग जाते हैं? हमारे पास इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन हम इस कौशल का इस्तेमाल बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबके लिए शांति और समृद्ध जीवन सुनिश्चित करने के लिए सतत विकास का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं।

दुनिया आज कई चुनौतियों का सामना कर रही है। हिंसक संघर्ष, नकारात्मता को बढ़ावा देने वाला ऑनलाइन वातावरण और लगातार बढ़ती आर्थिक असमानता, अवसरों को सीमित करती हैं। ये न सिर्फ व्यक्ति के भविष्य का रास्ता रोकती हैं, बल्कि सामाजिक तानेबाने की स्थिरता को भी प्रभावित करती हैं। शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने, जिम्मेदार वैश्विक नागरिक बनाने और स्थायी और सतत विकास के लिए युवाओं को आवश्यक कौशल से लैस करने और उस कौशल के इस्तेमाल से एक शांतिपूर्ण, समावेशी, मानवीय और विकासशील दुनिया का निर्माण हमारी प्राथमिकता होना चाहिए।

आइसलैंड: कुदरत के कलर पैलेट पर बिखरे नीले-काले-पीले-हरे रंग!

यह कोई पेंटिंग नहीं बल्कि आइसलैंड के दक्षिणी तट पर समुद्र में बहते एक हिमनद का प्रभावशाली दृश्य है। आइसलैंड की सबसे खूबसूरत जगहों में गिने जाने वाले इस पर्यटन स्थल को आप काल्फेफेल और हॉफ के बीच के क्षेत्र में पा सकते हैं। जब आप इस जगह को देखेंगे तो आप भी इसकी खूबसूरती के कायल हो जाएंगे। इससे पहले कि प्रकृति की रंग पट्टिका के रंग सूख जाएं, घूमने-फिरने के शौकीन हर व्यक्ति को इस समुद्र तट पर जरूर जाना चाहिए। दरअसल, आइसलैंड कच्ची और ऊबड़-खाबड़ सुंदरता की भूमि है, जो प्रकृति की ऐसी क्रूर शक्तियों का प्रमाण है जो अद्वितीय परिदृश्यों को आकार देती है। वातनाजोकुल नेशनल पार्क में स्थित यह समुद्र तट विशेष रूप से ज्वालामुखीय पीले रंग की नदी के लिए जाना जाता है जो नीले समुद्र के समानांतर बहती है। कुछ दूरी तक नदी के दोनों किनारों पर काली रेत की एक पट्टी बनी रहती है जो ज्वालामुखी गतिविधियों से बनी है, जबकि पीली रेत नदी की तलछट में मौजूद सल्फर की भारी मात्रा के कारण आती है। समुद्र तट से आगे बढ़ने पर इन रंगों में हरे-भरे खेतों का एक और खूबसूरत रंग भी जुड़ जाता है।

नेतृत्व

जरूरी है जागरूकता और संवेदनशीलता

सामुदायिक पहल व कर्मचारी कल्याण से परिलक्षित होती है प्रतिबद्धता

आध्यात्मिक वातावरण के निर्माण का प्रयास करने वाले लीडरों और मैनेजरों के लिए माइंडफुलनेस और संवेदनशीलता यानी 'कम्पैशन' आवश्यक गुण हैं। माइंडफुलनेस उन्हें पूरी तरह से जागरूक होने की अनुमति देती है, जो विचारशील निर्णय लेने और चुनौतियों के प्रति एक शांत, स्पष्ट दृष्टिकोण बनाए रखने की उनकी क्षमता को बढ़ाती हैं। यह गुण एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देता हैं जहां व्यक्तिगत बातचीत और कार्यों में माइंडफुलनेस को महत्त्व दिया जाता है और उसका अभ्यास किया जाता है। दूसरी ओर, संवेदनशीलता में दूसरों की भावनाओं और अनुभवों को समझना और उनसे वास्तव में जुड़ना शामिल है।

एक सहानुभूतिपूर्ण लीडर अपनी टीम की भावनात्मक और आध्यात्मिक भलाई का बेहतर ढंग से समर्थन कर सकता है, उनकी जरूरतों और प्रेरणाओं को पहचान सकता है और प्रभावी ढंग से उनका समाधान कर सकता है या उन्हें दिशा दे सकता है।

प्रो. हिमांशु राय
निदेशक,
आइआइएम इंदौर
@patrika.com

सहानुभूति प्रदर्शित करके, वह कर्मचारियों के बीच विश्वास और सुरक्षा की भावना का निर्माण कर सकता है, जो एक सहायक-सामंजस्यपूर्ण कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण है। इन रणनीतियों को लागू करने और इन गुणों को अपनाने से, लीडर अपने संगठनों को ऐसे वातावरण में बदल सकते हैं जहां कार्यस्थल आध्यात्मिकता विकसित होती है, व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण दोनों को बढ़ावा मिलता है और संगठन को अधिक पूर्णता और सफलता प्राप्त होती है। कई कंपनियों ने इस अवधारणा को अपनाया है। ऐसी कंपनियों की सफलता की कहानियों से महत्त्वपूर्ण सबक मिलते हैं जिन्हें अन्य संगठन अपना सकते हैं।

सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक है भारत का सबसे बड़ा समूह - टाटा। इस समूह ने लंबे समय से अपने संचालन में ईमानदारी, जवाबदेही और सामुदायिक सेवा जैसे मूल्यों को बढ़ावा देकर कार्यस्थल आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को अपनाया है। यह प्रतिबद्धता उनकी विभिन्न सामुदायिक पहलों और कर्मचारी कल्याण से परिलक्षित होती है, जो कर्मचारियों के बीच अपनेपन और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देती है। एक अन्य उदाहरण गूगल है, जिसने कार्यस्थल आध्यात्मिकता का समर्थन करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया है, जैसे सभी कर्मचारियों के लिए ध्यान और माइंडफुलनेस पाठ्यक्रम। ये कार्यक्रम तनाव को कम करने और कल्याण को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं और मानसिक स्वास्थ्य व व्यक्तिगत विकास को महत्त्व देने वाले कार्य वातावरण में योगदान करते हैं।

पानी के हिसाब से बोई जाए फसल

सुनील कुमार महला,

भारत में भू-जल का स्तर निरंतर गिरता चला जा रहा है। यदि इसी प्रकार से भू-जल स्तर का नीचे गिरना जारी रहा तो आने वाले समय में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। जल संकट के कारण दूसरी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। गिरते भूजल का मुख्य कारण यह है कि आज हमारे देश में पानी के परम्परागत स्रोत कम वर्षा व बेतरतीब दोहन के चलते खत्म होते जा रहे हैं। यही कारण है कि भूजल स्तर घटता जा रहा है।

देश में नलकूप लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में कृषि भूमि की सिंचाई के लिए हर साल 230 बिलियन मीटर क्यूबिक भूजल निकाला जाता है, जिससे देश के कई हिस्सों में भूजल का तेजी से क्षरण हो रहा है। औसत वार्षिक वर्षा भी कम है। वृक्षों की कटाई और नदियों का रुख बदलकर बांध बनाया जाना भी गिरते भूजल के कारणों में से एक है। वहीं दूसरी ओर तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और असंवहनीय कृषि पद्धतियों के कारण भी पानी की मांग बढ़ी है। कम वर्षा व अंधाधुंध दोहन के कारण भूजल स्तर में लगातार कमी आई है। भारत में भूजल का अत्यधिक उपयोग 61 प्रतिशत भूजल की कमी के लिए जिम्मेदार है। भारत विश्व के किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक भूजल निष्कर्षण का उपयोग करता है।

वास्तव में आज सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक विकास जैसे उद्देश्यों के लिए भूजल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भारत में यह एक गंभीर मद्दा है। भूजल स्तर बढ़ाने के लिए बारिश के पानी को इकट्ठा करना असरदार उपाय साबित हो सकता है। छोटे तालाबों, भूमिगत टैंकों, बांध आदि के बेहतर रखरखाव के जरिए जल संरक्षण किया जा सकता है। भूमिगत पुनर्भरण तकनीक जल संग्रहण का एक नया तरीका है। भूजल में गिरावट की समस्या के समाधान के लिए हमें फसल चक्र का सही निर्धारण भी करना होगा। कम पानी वाले क्षेत्रों में ऐसी फसलें उगाई जानी चाहिए, जिन्हें कम पानी की जरूरत पड़ती हो। जहां पानी की कमी नहीं है, वहां ऐसी फसलें लगाई जा सकती हैं, जिनमें अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। हर क्षेत्र में जल की उपलब्धता के अनुसार फसल उगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था करने पर किसान विरोध कर सकते हैं, लेकिन उनकी समझाइश की जा सकती है।

(ईमेल पर प्राप्त आलेख)

मिर्जापुर पिछले तीन-चार सालों से 'मिर्जापुर' वेब सीरीज के कारण देश में जाना जाने लगा है। लेकिन मिरजापुर की असल पहचान हिंसा या अपराध से नहीं है, बल्कि यह हिंदी पट्टी का वह सबसे खास सुरीला इलाका है, जहां से निकल 'कजरी' विधा लोक, शास्त्रीय, बॉलीवुड व सुगम संगीत के जरिए दुनिया के मंचों तक पहुंची है

न भूली - न बिसरी, जड़ता से आजाद है मिर्जापुर की 'कजरी'

उस्ताद बिस्मिल्ला खान से लेकर गिरिजा देवी जैसे वरिष्ठ कलाकारों तक ने इसे एक अलग पहचान दी। वर्तमान में शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्र जिस मंच पर जाते हैं, कजरी की फरमाइश होती है।

चंदन तिवारी लेखिका लोकगायन के लिए संगीत नाटक अकादमी के युवा सम्मान से सम्मानित बिहार, पूर्वांचल की चर्चित गायिका हैं

वेब सीरीज मिर्जापुर का तीसरा पार्ट रिलीज हो चुका है। सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा है। पहले वाला बढ़िया था या यह बेहतरीन है, इस पर बात चल रही हैं। संयोग से यह तीसरा पार्ट जब जारी हुआ है,तब सावन महीने का माहौल बन चुका है। सावन दस्तक दे रहा है। सावन को याद करते ही हिंदी इलाके के लोक गायन में कजरी की चर्चा आती है। कजरी गायन का माहौल बन जाता है। और जब कजरी की चर्चा चलती है तो मिर्जापुर का नाम आता है।

वजह, इसी मिर्जापुर को कजरी विधा की जननी माना जाता है। न सिर्फ जननी है, बल्कि गांव की गलियों में गाई जाने वाली विधा को यहां के लोगों, कलाकारों ने अपनी निष्ठा, समर्पण और मोहब्बत से इस कदर सींचा कि यह मिर्जापुर से निकल बनारस होते हुए लोक संगीत, सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत, बॉलीवुड संगीत सभी में समान रूप से स्थापित होती गई। कजरी का राग दुनिया के मंचों पर पहुंचकर रंग बिखेरने लगा।

जिस शहर मिर्जापुर का नाम लेकर वेब सीरीज बनाई गई है, वह शहर उत्तरप्रदेश के विंध्य इलाके में आता है। इसी विंध्य इलाके में मशहूर देवी मंदिर है, विंध्याचल धाम। मान्यता है कि मां विंध्यवासिनी का एक नाम कज्जला देवी भी है। इलाके के लोग कहते हैं कि कजरी नाम, इन्हीं कज्जला देवी के नाम से आया। कज्जला, कजली और कजरी, तीनों एक ही हैं। हालांकि कजरी के उद्भव की और भी कहानियां हैं। यहां हर साल विंध्यवासिनी जन्मोत्सव और कजली महोत्सव का चलन रहा है। कहते हैं कि एक समय ऐसा भी था, जब ढाई दिन के इस उत्सव की अवधि में मिर्जापुर की सारी दुकानें बंद रहती थीं। इस उत्सव में कजरी के नए शिष्य अपने गुरुओं से दीक्षा लेकर, विंध्याचल मंदिर में आकर, सुमिरनी भेंट करते थे - सुमिरनी यानी प्रार्थना। सुमिरनी कर ही कजरी के संगीत अखाड़े में पहली बार उतरते थे। संगीत के उस्तादों, खलीफाओं और गुरुओं का जुटान होता था। कजरी गायन से पहले खंजरी पूजन नए कलाकारों के लिए प्रथम गायन का अवसर होता था। जो कजरी लिखते थे, वे भी पहली बार का लिखा यहां चढ़ावे में चढ़ाते थे।

विंध्याचल धाम को कजरी ने साझी संस्कृति का केंद्र बनाया। कजरी लोकगायन के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग समान उत्साह और समान अधिकार से पहुंचते थे। इसी इलाके के बड़े कजरीबाज थे प्रेमधन। इनकी हवेली को कजरी की हवेली भी कहते थे। इस हवेली में आषाढ़ से लेकर भादो तक कजरी की महफिल जमती थी। खड़ी बोली हिंदी के प्रणेता भारतेंदु इस हवेली में आकर डेरा जमाते थे। यहां विशाल लाइब्रेरी भी थी कजरी की। इससे इतर मिर्जापुर के इलाके में कजरी के मेले लगते। एक गायन विधा को केंद्र में रखकर मेले का चलन न के बराबर दिखता है। इन बातों पर चर्चा का आशय यह कि मिर्जापुर की पहचान इस कदर जुड़ी हुई है कजरी से, लोक संस्कृति से।

पुरबिया लोकगायन में कजरी सबसे विस्तारित विधा है गायन की। खेती-किसानी से लेकर धार्मिक और सामयिक सवालों तक के स्वर इसमें जुड़ते हैं। कजरी गीतों में अपने समय का इतिहास, समय के सवाल भी निरूपित हैं। कजरी गाते भी हैं, मनाते भी हैं, खेलते भी हैं। यह किसानों के जीवन में उल्लास भरने व स्त्रियों को आजादी का राग देने वाली विधा है। खेती-किसानी से जुड़ी कामगार स्त्रियां कजरी के जरिए खेत मालिकों से बराबरी का संवाद करने का अधिकार लेती रही हैं, बिना किसी डर, भय और हिचक के।

इस पारंपरिक लोक विधा ने समय के अनुसार नवाचार किया, दूसरी विधाओं की तरह लकीर की फकीर नहीं रही। समय के साथ खत्म नहीं हुई बल्कि और बढ़ती गई, कभी पारंपरिक जड़ता का शिकार नहीं हुई। क्या कुछ नहीं है इस विधा में! सृष्टि का स्वर है, प्रकृति का रंग है, प्रेम का सौंदर्य है, विरह का राग है। कजरी गीतों में 1857 की क्रांति से पहले की कहानियां मिलती हैं तो जब गांधी अफ्रीका से लौटे मिर्जापुर के गंवई गायकों ने गांधी को कजरी का नायक बनाया।

मिर्जापुर, बनारस से सटा शहर है। बनारस के मूर्धन्य कलाकारों ने इसे देश भर में फैलाया, दुनिया के मंचों पर। इसी मिर्जापुर से पलायन को केंद्र में रखकर एक गीत निकला- 'मिर्जापुर कइले गुलजार हो, कचौड़ी गली सून कइले बलमू..।' यह गीत आज कजरी के सर्वाधिक लोकप्रिय गीतों में एक है, जिसे अनेक कलाकार स्वर दे चुके हैं। इसी तरह एक कजरी गीत का शीर्षक है- 'नागर नइया जाला कालापनिया ए हरि...।' इस गीत की कहानी पर हिंदी के मशहूर लेखक शिव प्रसाद मिश्र रूद्र 'काशिकेय' ने मशहूर कृति बहती गंगा में लिखा।

संभव है आने वाले दिनों में जब हम किसी सर्च इंजन के जरिए मिर्जापुर को सर्च करेंगे, तो अपराध-हिंसा के रंगों में सना हुआ मिर्जापुर ही दिखे गाली-गलौज की भाषा के साथ। जिन्होंने मिर्जापुर इलाके को कभी देखा-जाना नहीं है, वे इसे ही पूरा सच मान भी लेंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि कजरी संगीत पीढ़ियों से मिर्जापुर को गुलजार करता रहा है।

आपकी बात

पूर्व तैयारी आवश्यक

आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि सरकारें आपदाओं की रोकथाम के उपाय आपदाओं के आने के पहले ही करें। पूर्व तैयारी होने पर नुकसान कम होता है। साथ ही आपदा प्रबंधन सूचना तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को बचने और संभलने का समय मिल जाए।

-ओमप्रकाश श्रीवास्तव, उदयपुरा, मप्र

स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ें

स्कूली पाठ्यक्रम में शैक्षिक विषयों के साथ अनेक सहशैक्षिक गतिविधियां भी शामिल रहती हैं। इनमें खेल सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, सड़क सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा, समसामयिक विषयों पर चर्चा के साथ ही आपदा प्रबंधन को भी शामिल किया जाए। इससे बचपन से ही जागरूकता बढ़ेगी।

-पी.सी. खंडेलवाल, सांभर लेक, जयपुर

आज का सवाल

पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पर हमले का अमरीका के चुनाव पर क्या असर होगा?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'आपदा प्रबंधन तंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है?' कई प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। कुछ ऑनलाइन भी दी जा रही हैं।

इसे स्कैन करें

https://shorturl.at/Jedv1

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। सोमवार, 15 जुलाई 2024

बुलेट नहीं, बैलट

अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पर शनिवार को एक चुनावी रैली के दौरान हुआ जानलेवा हमला हर लिहाज से दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। गनीमत है कि हमले में ट्रंप को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और वह सुरक्षित हैं। हालांकि उन पर हुए इस हमले ने पहले से ही दो ध्रुवों में बंटे अमेरिकी जनमत को बुरी तरह आलोड़ित कर दिया है।

हमलों का इतिहास | अमेरिका में राष्ट्रपतियों पर इस तरह का हमला कोई नई बात नहीं है। वहां ऐसे हमलों का लंबा इतिहास रहा है। चार राष्ट्रपति और एक राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी ऐसे हमलों में जान तक गंवा चुके हैं। पिछले चार-पांच दशकों की बात करें तो रोनाल्ड रीगन, बिल क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जैसे चर्चित राष्ट्रपति हमलों का निशाना बन चुके हैं।

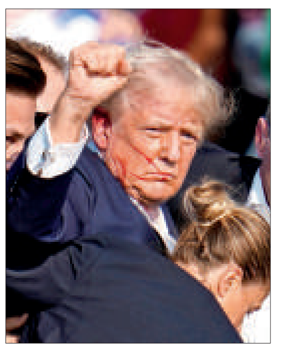

डॉनल्ड ट्रंप पर हमला

दो धड़ों में बंटा जनमत | फिर भी ट्रंप पर हुए इस हमले की अतीत की घटनाओं से तुलना नहीं की जा सकती। ट्रंप न सिर्फ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बल्कि आगामी चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से इस पद के प्रत्याशी भी हैं। अब तक के तमाम सर्वे उन्हें लोकप्रियता में सबसे आगे बता रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप राजनीति और शासन की अपनी विशिष्ट शैली के लिए जाने जाते रहे हैं। अमेरिकी इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई पूर्व राष्ट्रपति चुनाव परिणामों को पलटने के लिए दंगे भड़काने जैसे आरोपों का सामना कर रहा है या चुनाव नतीजों को स्वीकार करने से लगातार इनकार करता रहा है। इसके बावजूद लोकप्रियता में सबसे आगे नजर आ रहा है।

कड़वाहट बढ़ने का खतरा | ऐसे में ट्रंप पर हमले की इस घटना की गंभीरता बहुत बढ़ जाती है। इसका अमेरिका के आम लोगों की सोच पर, वहां की राजनीति और चुनावों पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। हालांकि ट्रंप समर्थकों का एक धड़ा इसके लिए उनके राजनीतिक विरोधियों की आक्रामक प्रचार शैली को अभी से जिम्मेदार ठहराने लगा है। देखना होगा कि यह सिलसिला चुनावों में वोटरों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिशों तक सीमित रहता है या राजनीति में और ज्यादा कड़वाहट घोलता है।

व्यापक प्रभाव | सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे अमेरिका के घरेलू राजनीतिक माहौल की बात हो या चुनाव परिणामों की, उनका असर अमेरिका तक सीमित नहीं रहता। पूरा विश्व इसके दायरे में आता है। ऐसे में जरूरी है कि जांच एजेंसियां इस घटना के असली कारणों तक जल्द से जल्द पहुंचें। हालांकि हमलावर के मारे जाने की वजह से यह काम थोड़ा और मुश्किल हो गया है। फिर भी उम्मीद है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी और साजिशों के तार खुलेंगे, वैसे-वैसे बहस भी समाज को हिंसक बनाने वाले और गन कल्चर को बढ़ाने वाले कारकों पर केंद्रित होगी। याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र में बुलेट नहीं, बैलट ही सबसे कारगर हथियार होता है।

चक्र-व्यू

पहचान से दूर

राहुल पाण्डेय

फेसबुक ने तो अब हाल कुछ यूं कर दिया है कि जिस खासियत के लिए किसी को फॉलो किया था, वह खासियत तो दूर रही, उस शख्स तक के दर्शन नहीं होते। उंगली से धक्का मार-मारकर मोबाइल पर अपनी फीड बढ़ाए जा रहे हैं कि जिन लोगों को देखने, सुनने, पढ़ने और समझने आए थे, वे कहीं तो दिखें। मगर फेसबुक ने फीड कुछ ऐसी बिगाड़ी है कि जिन्हें दिखना चाहिए, वे तो दिखते नहीं, अलबत्ता वे जरूर नजर आते रहते हैं, जिन्हें एक सभ्य समाज में किसी को नहीं दिखना चाहिए। और यह हाल उसके इंस्टाग्राम पर भी है। छोटी-बड़ी बच्चियों को लेकर जैसा कंटेंट फेसबुक और इंस्टाग्राम 'सजेस्टेड पोस्ट' कहके दिखा रहे हैं, अगर वाकई कंपनी इसकी हिमायती है तो भरी भीड़ में वही कंटेंट कंपनी वाले अपने मोबाइल या लैपटॉप पर खोलकर देख लें। दो मिनट में समाज सेवा करके रील ना बना दे तो कहिए!

ऐसा नहीं कि अपन ने कोशिश नहीं की इस जबरदस्ती से बचने की। यूट्यूब पर किसी ने बताया कि फलां चीज बंद कर दो, तो बंद कर दी। प्रोफाइल लॉक करने का सुझाव मिला तो वह भी किया। किसी ने कहा कि सबको लगातार लाइक करो, उनके यहां कमेंट करो। ये काम भी किया। मगर क्या मजाल कि जिन्हें पढ़ना, देखना, सुनना चाहते हैं, या जो दोस्त हैं, नाते-रिश्तेदार हैं, वे कहीं दिख जाएं। तर्जनी से धक्का मारते-मारते पक गए, तो कभी मध्यमा से या अनामिका से धक्का मार रहे हैं। फेसबुक को टैग करके पोस्ट भी लिखी कि भाई, ऐसा मत करो। हम तो अपने जानने वालों के लिए यहां आए थे, और बहुत हद उनके भी जानने वालों के लिए। अपहचान की ऐसी दुनिया हमें नहीं चाहिए, जहां से हम निकल ही ना सकें। तुम्हारे अमेरिका का तो नहीं पता, मगर हिंदुस्तान में ऐसी दुनिया को दुनिया नहीं, गड्ढा कहते हैं।

कहीं और इतनी बड़ी आबादी को गड्ढे में कोई धकेले तो क्रांति हो जाए! मगर अपने हिंदुस्तान में ऐसा कुछ तो होने से रहा! बल्कि यहां तो गड्ढे में पड़े इंसान को बाहर निकालने की जगह उसकी रील बना दी जाती है। ऐसी कई खबरें हैं कि फेसबुक के जबरदस्ती 'सजेस्टेड पोस्ट' दिखाने के चलते लोगों ने उसकी नॉर्मल फीड देखनी लगभग बंद कर दी है। खुद मैं अब कभी अगर वहां जाता हूं तो सीधे अपनी फ्रेंड लिस्ट में जाता हूं। ऐसा करते हुए मुझे 2004-05 में शुरू हुई हिंदी ब्लॉगिंग की आदतें याद आती हैं, जब हम सीधे किसी के ब्लॉग पर जाते थे, या आज की फेसबुक फ्रेंड लिस्ट की तरह हम अपने जान-पहचान वालों की ब्लॉग लिस्ट बनाकर सेव रखते थे। फेसबुक की यह जबरदस्ती बताती है कि तकनीक और जिद मिलकर आबादी की एक बड़ी संख्या को सालों पीछे धकेल सकते हैं। बल्कि धकेल ही दिया है।

एकदा

कलमदान का वक्त

पिता की मौत के बाद मीर तकी मीर को काफी दुख उठाना पड़ा। उनकी दुख भरी दास्तान सुनकर दिल्ली के अमीर ख्वाजा मोहम्मद बासित उन्हें नवाब की पेशी में ले गए। नवाब साहब ने मीर को देखकर पूछा, यह किसका लड़का है? बासित बोले, मीर मोहम्मद अली का। नवाब साहब बोले, यानी अली साहब इस दुनिया से सिधार गए। यह कहकर नवाब साहब अफसोस जाहिर करने लगे। फिर बोले, इनके पिता का मुझपर बड़ा अहसान है, इसलिए उनके लड़के को रोज एक रुपया मेरी ओर से। मीर ने अर्ज किया कि बस इतनी मेहरबानी और करिए कि मुझे एक दस्तखत करके दे दें तो रुपये की राह में रोड़ा अटकाने वालों का डर ना रहे। नवाब साहब बोले, यह कलमदान का वक्त नहीं है। यह सुनते ही मीर की हंसी निकल गई। नवाब साहब ने आंखें तरेर कर मीर की ओर देखा और हंसी की वजह पूछी। मीर बोले, यह भी खूब कह सकते थे कि यह नवाब के दस्तखत करने का वक्त नहीं है। कलमदान का वक्त नहीं है, यह तो जुबान का नया रूप है। कलमदान लकड़ी का एक टुकड़ा है, वह वक्त-बेवक्त नहीं जानता। जिसे भी हुक्म दिया जाए, उठा लाएगा। यह सुनकर नवाब साहब हंस दिए और बोले, बात तो यह ठीक कह रहा है, और तुरंत कलमदान मंगाया और मीर की दरख्वास्त पर दस्तखत कर दिए। बाद में नवाब साहब जंग में मारे गए। मीर लिखते हैं कि बावजूद उसके, उन्हें रोजाना एक रुपया मिलता रहा, और दिल्ली में इसी से नान-नमक का इंतजाम होता रहा।

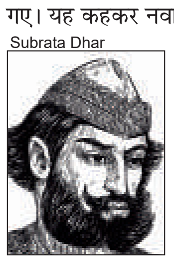

Subrata Dhar

संकलन : जमील गुलरेज

इकॉनमी के मोर्चे पर जूझ रहे शी चिनफिंग के सामने है पुरानी रफ्तार हासिल करने की चुनौती

CPC के थर्ड प्लेनम पर क्यों टिकीं निगाहें

plenum

चंद्रभूषण

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का थर्ड प्लेनम चर्चा में है। 15 से 18 जुलाई तक चलने वाली चीन की इस महत्वपूर्ण नीति निर्धारक कवायद में उसकी सीमा से बाहर बैठे पॉलिसी मेकर्स की भी खासी दिलचस्पी है। अभी वहां बेरोजगारी सामान्य से ज्यादा है और अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र संकट का सामना कर रहे हैं। पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर के अलावा भारत-चीन सीमा पर भी तनाव बना हुआ है। ऐसे में आगे की दिशा को लेकर चीन पर सबकी नजर टिकी है।

तीसरा अधिवेशन होता है खास | प्लेनम को हिंदी में 'पूर्णाधिवेशन' कहा जाता रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के अलावा बड़ी जिम्मेदारियां संभालने वाले अन्य पार्टी सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की दो कांग्रेसों के बीच होने वाले कुल पांच पूर्णाधिवेशनों में 'तीसरा' एक रवायत की तरह सबसे खास होता आया है। तंग श्याओफिंग ने 1978 में चीन के आधुनिकीकरण की घोषणा ऐसे ही एक 'थर्ड प्लेनम' में की थी और 1993 में चीनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया गया था। शी चिनफिंग को भी सबसे ज्यादा 2013 में की गई उनकी थर्ड प्लेनम घोषणाओं के लिए ही याद किया जाता है। लेकिन इस बार इस कदमताल में इतनी देरी हो चुकी है कि और बातों से पहले यह विलंब ही दुनिया के लिए चकल्लस की चीज बन गया। कायदे से यह प्लेनम पिछले साल अक्टूबर में हो जाना चाहिए था। इसके आयोजन में हुई देरी से तमाम अटकलें पैदा हुई हैं।

ग्रोथ में गिरावट | कुछ तथ्यों पर नजर डालें। कोविड को लेकर चीन ने कुछ ज्यादा ही सख्ती बरती और अर्थव्यवस्था को खोलने में देर कर दी। इससे महामारी में उसकी लय एक बार बिगड़ी तो पूरी तरह सम पर आज भी नहीं आ पाई है। 2023 में उसकी GDP ग्रोथ 4.6% दर्ज की गई जो 19 ट्रिलियन डॉलर की उसकी विशाल अर्थव्यवस्था के लिए बुरी नहीं, पर जितनी ऊंची GDP हम वहां देखते आए हैं, उसके मद्देनजर काफी कम है।

चीन के सामने क्या हैं मुश्किलें
- आर्थिक नीतियों पर लोगों में असंतोष
- विदेशी निवेश घटा, रोजगार भी घटा
- 'तुगलकी' फरमानों से परेशानी

निवेश हुआ कम | रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट का हाल बुरा बताया जा रहा है। उपभोक्ता सामानों का बाजार ठहरा हुआ है। सबसे बड़ी समस्या निवेश के स्तर पर देखी जा रही है। चीन में निजी और सरकारी उद्यमों का अनुपात 60 और 40 का है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का निवेश पिछले एक साल में बढ़ना तो दूर, 0.4% कम हो गया है। विदेशी निवेश 8% नीचे आ गया है।

रोजगार पर असर | चीन की शहरी नौकरियों में 80% निजी क्षेत्र से ही आती हैं। प्राइवेट सेक्टर में निवेश का न आना रोजगार पर बुरा असर डाल रहा है। इस सिलसिले की शुरुआत को सीधे तौर पर कोरोना की बंदी से ही जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ भूमिका शी चिनफिंग की नीतियों की भी रही है। 2012 की पार्टी कांग्रेस में पार्टी महासचिव पद पर उनके चुनाव को भ्रष्टाचार, असमानता और चीनी अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी के दबदबे के खिलाफ जनादेश की तरह प्रस्तुत किया गया था। इसी समझ पर आगे चलते हुए उन्होंने एक रेलमंत्री, एक गवर्नर और एक के बाद एक, कुल दो रक्षा मंत्रियों को उनके पदों से बर्खास्त करके उन पर मुकदमा चलवाया और सख्त से सख्त सजाएं दिलाईं।

AI Image

रियल एस्टेट संकट | चीन के बौद्धिक उद्यमी के रूप में मशहूर जैक मा और उनके ऐंट ग्रुप पर पड़े चीनी हुकूमत के हथौड़े को भ्रष्टाचार के बजाय उनके 'अति-आत्मविश्वास' को दंडित करने की तरह पेश किया गया। विदेशी निवेश पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। एवरग्रैंड ग्रुप का डूबना चीन में रियल एस्टेट सेक्टर के संकट का बड़ा नमूना था। ऐसी कंपनियों और उन्हें कर्ज देने वाले बैंकों के दिवालिया होने का सिलसिला शुरू हुआ तो कुछ इलाकों में प्रदर्शन कर रहे घर खरीदारों के खिलाफ टैंक तक भेजने पड़ गए।

उल्टी पड़ी नीति | नए चीन के प्रतीक पुरुष तंग श्याओफिंग की एक घोषित नीति यह थी, 'बिल्ली जब तक चूहे पकड़ती है तब तक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह काली है या सफेद।' तात्पर्य यह कि देश में समृद्धि आए, लोगों में खुशहाली की उम्मीद जगे तो इसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए कि कौन से तरीके इसके लिए अपनाने पड़ रहे हैं। लेकिन इस नीति पर चलते हुए 2015 आते-आते हाल ऐसा हो गया कि दोहरी कमाई वाले एक शहरी मिडिल क्लास परिवार के लिए भी अपने अकेले बच्चे की अच्छी परवरिश, बढ़िया शिक्षा मुश्किल हो गई। ऐसे में सबसे सख्त कार्रवाई चीनी हुकूमत ने ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री के खिलाफ की।

चिनफिंग को सीख | पश्चिमी मीडिया ने इसे एक तुगलकी कदम के रूप में पेश किया। थर्ड प्लेनम को लेकर वहां छप रही टिप्पणियों में यह बात बार-बार आ रही है कि शी चिनफिंग को आगे ऐसी हरकतों से बाज आने का कोई संकेत यहां जरूर देना चाहिए। इस बात को लेकर भी आक्रोश है कि अपने यहां रोजगारपरक क्षेत्रों में पूंजी लगाने और उपभोक्ता खर्चे बढ़ाने के बजाय चीन का सारा जोर तकनीकी के ऐसे क्षेत्रों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है, जो सुदूर भविष्य में ही आम लोगों के काम आ सकेंगे।

भविष्य के सुराग | थर्ड प्लेनम में चर्चा के लिए प्रस्तुत परिपत्र में बातें तो सारी गोलमोल-सी ही हैं, लेकिन उसमें सन 2035 तक 'एडवांस्ड सोशलिस्ट इकॉनमी' हासिल करने के लक्ष्य को लेकर एक दृढ़ता भी है। तंग श्याओफिंग सन 2050 तक चीन में किसी तरह का लोकतांत्रिक समाज बना लेने की बात करते थे। इस तरह का कोई दिशा संकेत जब पार्टी कांग्रेसों में ही नहीं दिख रहा तो प्लेनम में क्या दिखेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर और विदेशी पूंजी के लिए कानून और प्रशासन के स्तर पर आसानी पैदा करने के कुछ सुराग इसमें जरूर नजर आते हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

सीढ़ियों पर छिपा खुशियों का मेसेज देखा क्या

message

स्टीकर चिपकाया इस तरह गया है कि जब कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो, तो सबसे पहले उसकी नजर उसी पर जाए। पहली मंजिल के लिए चढ़ते हुए, जब आधा रास्ता तय हो चुका होता है, तभी मेसेज नुमाया होता है, 'ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर तक आने में आपने 4.42 कैलोरी बर्न की।' पहली मंजिल अभी आई नहीं है, लेकिन मेसेज आ चुका है और वह आकर्षित कर रहा है कि हमारे अगले ये कुछ कदम फिटनेस की ओर भी होंगे। इसे देखने के बाद घर से ऑफिस आने तक की थकान, गर्मी और उमस की मार - अहसास होता है कि सारे संकट दूर हो गए।

कुछ लोगों को ऑफिस में सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल लगता है, खासकर जब सामने ही लिफ्ट हो। लेकिन, यह मेसेज उनकी दोस्ती करा देता है उन सीढ़ियों से, जो जाने-अनजाने हमारे जीवन में अनदेखी ही रह जाती हैं। सोचिए, मोबाइल की स्क्रीन में देखे बिना आखिरी बार सीढ़ियों को कब पार किया था आपने? बहुमंजिला इमारतों में रहने वालों ने कितनी बार देखी हैं अपने यहां की सीढ़ियां? और कितने लोगों का परिचय है मॉल, मल्टीप्लेक्स, ऑफिस या किसी कॉम्प्लेक्स की सीढ़ियों से? आमतौर पर बंद दरवाजों के भीतर इनकी सुध तभी आती है लोगों को जब ऊपर जाने का दूसरा कोई जरिया नहीं होता। लेकिन सीढ़ियां मजबूरी भर नहीं हैं। ये जरिया हैं अच्छा महसूस करने और खुश होने का। एक साधारण-सी चढ़ाई या उतरान हमें जोड़ सकती है ऐसी भावनाओं और इतने दिलचस्प अनुभवों से, जिनका जीवन में अपना महत्व है। सीढ़ियां चुनौती पेश करती हैं हमारे सामने, कि आओ और हमें जीत लो।

AI Image

जीवन आनंद

मौका देती हैं हमें अपने कदमों के नियंत्रण और ताकत को आजमाने का। हर चरण के साथ हम ऊंचाई हासिल करते हैं और इस ऊंचाई के साथ एक नया दृष्टिकोण। सीढ़ी का आखिरी पायदान खुद में सबसे बड़ा इनाम है। उस ऊंचाई से चीजों को देखना हमारी जीवन यात्रा के आनंद का ही तो हिस्सा है। सीढ़ियां हमें धैर्य और दृढ़ संकल्प सिखाती हैं। इनका हर स्टेप चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन साथ में प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की।

सीढ़ियां पुल का भी काम कर सकती हैं। यह अतीत को वर्तमान से जोड़ सकती हैं और वर्तमान को भविष्य से। किसी खंडहर की सीढ़ियों पर रखा गया कदम इतिहास के झरोखे खोल सकता है। वहीं, मंदिर की सीढ़ियां हमें ले जाती हैं नाउम्मीदी से उम्मीद की ओर। कुछ सीढ़ियां दिखती नहीं, लेकिन होती हैं और उन पर चढ़कर ही आप सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इन पर चढ़ना इतना आसान नहीं होता। ये परीक्षा लेती हैं, डराती हैं। जोश-जोश में आकर अगर ज्यादा लंबी छलांग लगाई, तो थका देती हैं। कई बार बीच रास्ते में ही सांस उखड़ने लगती है। तब मन बदलने लगता है कि अब यहां से लिफ्ट ले ली जाए। ऐसी ही मुश्किल के लिए मार्टिन लूथर किंग का कहना था कि आपको पूरी सीढ़ियां देखने की जरूरत नहीं है, केवल पहले पायदान पर नजर रखिए। आपका हर कदम दूसरे की बुनियाद तैयार करता चलेगा।

सीढ़ियां बस चढ़ाती ही नहीं, उतारती भी हैं। ज्यादा आसान होता है उतरना। यह संकेत भी है कि जीवन चक्र में चलता है। ऊपर गए हैं, तो नीचे आने का भी डर है। इसका यह मतलब नहीं कि दोबारा ऊपर नहीं जाया जा सकता। सीढ़ियां अपनी जगह हमेशा मौजूद रहती हैं, कमी रह जाती है प्रयास करने वालों में। जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उनके ऊपर उठने का प्रतीक हैं सीढ़ियां। इनको पार करते समय याद रखिए कि इसी तरह हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। और जब आप उसे पार कर लेंगे तो हौसला बढ़ाने के लिए कैलोरी बर्न जैसी ही कोई इबारत लिखी दिखेगी, जो उकसाएगी और ऊपर चढ़ने के लिए।

शेयर करें अपने अनुभव

जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, हमें बताएं **nbtreader@timesgroup.com** पर, और सब्जेक्ट में लिखें- **'जीवन आनंद'**

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

बच्चे का stress खत्म करना है, तो यह race छोड़िए

बीके शिवानी

परिस्थितियों के गुलाम बनने से पहले अक्सर हम मन के अधीन हो जाते हैं। मन की गुलामी से मुक्ति पाकर ही हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। राम राज्य कब आएगा? इसके लिए हम सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि इंतजाम और प्रयास भी कर सकते हैं। हम हर रोज बच्चों को पढ़ाई के लिए स्ट्रेस देते हैं, पर परीक्षा के दिन कहते हैं कि स्ट्रेस मत लेना। क्या यह कहने मात्र से स्ट्रेस खत्म हो जाएगा? हम एक-दूसरे से अनजान होते हुए भी सड़क पर चलती गाड़ी से कॉम्पिटिशन कर बैठते हैं, और दूसरे से आगे जाने की होड़ में रेड सिग्नल तोड़ बैठते हैं। अगर हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, तो क्या वह कॉम्पिटिटर हमारी मदद के लिए रुकेगा?

जीवन भी एक रेस है, जिसमें आगे बढ़ने की होड़ है। इस चक्कर में हम मन को गुलाम बना देते हैं। मन की बुरी भावनाएं ही हमें दुख में धकेल देती हैं। मन तो एक बच्चे की तरह है। उसे कष्ट या दंड देकर दबाया नहीं जा सकता। बल्कि प्यार से समझा-बुझाकर उसे सुमन बनाया जा सकता है। उसे उचित लक्ष्य और सच्ची खुशी की अनुभूति कराकर ही सुधारा जा सकता है। इसके लिए हमें कमी, कमजोरी और मनचाही चीजें न मिलने पर हाय-हाय करने के बजाय पुरुषार्थ करना होगा। कुदरत ने जो कला और कौशल दिया है और उससे जो भी मिला है, उसे सहर्ष स्वीकार करना होगा, तभी जीवन सुखमय होगा। इसके लिए मन रूपी बच्चे को अंतरात्मा रूपी मां से जोड़ने की जरूरत है।

आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग ध्यान से ही हम अपने मन-बुद्धि को अंतरात्मा और सर्व आत्माओं के माता-पिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। तब हम अपनी मनोवृत्ति, स्वभाव, संस्कार और भावनाओं को शुभ और सुखदायी बना सकते हैं। तभी हम आत्मिक स्नेह, सहयोग और सद्भावना के आधार पर एक-दूसरे के जीवन में सुख, शांति और खुशी का लेन-देन कर सकते हैं। देखा जाए तो भौतिक तरक्की के चक्कर में हम अपनी खुशी खो बैठे हैं। खुशी असल में मन की स्थिति पर निर्भर करती है। किसी डर, गुस्से या नाराजगी के बल पर नहीं, बल्कि सत्य, प्रेम, न्याय, शांति, अहिंसा और भाईचारा बढ़ाकर रामराज्य ला सकते हैं।

सच है कि आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम आज इंद्रियों के गुलाम बन गए हैं। हमें साधनों का गुलाम नहीं, बल्कि उनका मालिक बनना है। तभी हम आध्यात्मिक सुख की ओर जा सकते हैं। राजयोग हमें संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाता है, क्योंकि राजयोग हमारी अंतरात्मा को शक्तिशाली बनाता है। इससे हम हर विपरीत परिस्थिति में अपने मन, चित्त और स्थिति को शांत और स्थिर रख सकते हैं।

अगर हमें कोई बद्दुआ देता है, तो बदले में हम उसे दुआ दे सकते हैं। दुआ से बद्दुआ के घाव भर सकते हैं। हमारे मूल संस्कार किसी को दुख देने के नहीं हैं। सुख-शांति के साथ रहना और दूसरों को खुशी देना मानव का मूल स्वभाव है। इन आत्मिक गुणों, आंतरिक शक्ति और शुद्ध संस्कारों को मानव जीवन में विकसित करना है। इसके लिए हमें ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग, मेडिटेशन, स्वच्छ, स्वस्थ और सात्विक जीवनशैली को अपनाना होगा। अन्न-जल की शुद्धता का ध्यान रखना होगा।

बोलने से मना क्यों करते हैं बेज़ोस

bezos

वैराग्य देव जोशी

यह बात 1990 के दशक के आखिरी वर्षों की है। जेफ बेजोस की टीम के एक जूनियर कर्मचारी ने कंपनी के बड़े अधिकारियों के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया। इसमें उसने सभी बड़ी कंपनियों की समस्याओं का खाका खींचा था। यह समस्या थी, दूर-दूर स्थित विभागों के बीच तालमेल की कमी। कर्मचारी ने प्रेजेंटेशन में सुझाया कि कुछ तकनीकों के जरिए कंपनी के अलग-अलग समूहों के बीच संवाद को बेहतर बनाया जाए। प्रेजेंटेशन को सुनते-सुनते ही जेफ बेजोस गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा, 'मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन तुम पूरी तरह से गलत हो। ज्यादा संवाद एक गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब यह होता है कि लोग आपस में मिलकर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसे तरीके तलाशने चाहिए, जिससे इन टीमों को एक-दूसरे से कम से कम बात करनी पड़े, ज्यादा नहीं।'

आज की दुनिया का एक प्रमुख वाक्य है कि बात करने से ही बात बनती है। लेकिन, ऐमजॉन के मालिक जेफ बेजोस का मानना है कि अधिक बात करना एक तरह की खराबी की निशानी है। आज जब दुनिया संचार क्रांति के दौर से गुजर रही है, मुख्यधारा के मीडिया, सोशल मीडिया, फोन कॉल और विडियो कॉल के जरिए लोग ज्यादा से ज्यादा बातें कर रहे हैं, तब बेजोस का आपस में बातचीत करने के खिलाफ तर्क देना निश्चित रूप से चौंकाने वाली बात है। उनसे जुड़ा यह किस्सा बयान किया है अमेरिकी लेखक ब्रैड स्टोन ने अपनी किताब, **'द एवरीथिंग स्टोर : जेफ बेजोस एंड द एज ऑफ ऐमजॉन'** में। स्टोन ने यह किताब 2013 में लिखी थी और तमाम मशहूर मीडिया संस्थानों ने इसे बेस्ट सेलिंग कहा है। स्टोन की इस किताब का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है।

ऐमजॉन आज की तारीख में दुनिया के सबसे जाने-माने ब्रैंड्स में से एक है। इसने शॉपिंग को बेहद आसान बना दिया है। ऐमजॉन की कामयाबी, बेजोस की कामयाबी है। आखिर यह मंजिल दोनों को मिली कैसे? जेफ और ऐमजॉन की कहानी साथ-साथ चलती है। 'द एवरीथिंग स्टोर' की शुरुआत होती है बेजोस के घर के गैराज से, जहां 1994 में उन्होंने ऐमजॉन की स्थापना एक ऑनलाइन बुक स्टोर के तौर पर की थी। उन्हें इस कंपनी को शुरू करने का ख्याल न्यू यॉर्क से सिएटल के सफर के दौरान आया। तब उन्होंने कंपनी का नाम काडाब्रा रखने की सोची थी। इसे शुरू करते वक्त बेजोस ने जो कल्पना की थी, आज की ऐमजॉन उससे बिल्कुल अलग है। ब्रैड स्टोन लिखते हैं कि बेजोस को अगर एक शब्द में परिभाषित किया जाए तो वह होगा, 'अनवरत'। वह बिना रुके, बिना थके एक निर्दयी बॉस के रूप में काम करने वाले इंसान हैं। कंपनी का नाम रखने का किस्सा भी स्टोन ने अपनी किताब में बताया है। उस दौर में वेबसाइट के नाम अंग्रेजी की वर्णमाला के हिसाब से रखे जाते थे। इसीलिए, जेफ ने अपनी कंपनी का नाम दुनिया की सबसे बड़ी नदी ऐमजॉन पर रखा। एक तो यह अंग्रेजी के A अक्षर से शुरू होता है और दूसरा, ऐमजॉन के अथाह पानी की तरह बेजोस के ख्वाब भी कंपनी को अथाह सफलता दिलाने के थे।

AI Image

विचार विंडो

ब्रैड स्टोन अपनी किताब में बेजोस की कल्पना शक्ति, उनके जबरदस्त टीम लीडर होने, निर्दयी मैनेजर और बेहद महत्वाकांक्षी होने की तस्वीर खींचते हैं। उनके कारोबारी-पारिवारिक किस्से भी इसमें दर्ज हैं। बेजोस की जिंदगी राज रही है। वह इंटरव्यू नहीं देते, लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं। ऐसे में 'द एवरीथिंग स्टोर' वह खिड़की है, जो बेजोस की जिंदगी में झांकने, उनके बारे में जानने समझने का मौका देती है।

मसला गिल्ट का

guilt

प्रणव प्रियदर्शी

वर्किंग विमिन के लिए आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कुछ समय पहले तक इस सवाल के कई जवाब दिए जा सकते थे, लेकिन अब इस क्षेत्र पर नजर रखने वालों में इस पर आम सहमति-सी दिखने लगी है। उनके मुताबिक, कामकाजी महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने गिल्ट यानी अपराध बोध को मैनेज करना। पिछले दिनों हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित टाइम्स टेकीज वेबिनार में भी यही राय उभर कर सामने आई। जगुआर लैंड रोवर टेक्नॉलजी एंड बिजनेस सर्विसेज इंडिया की सीईओ ललिता इंद्रकांति ने इस पहलू पर रोशनी डालते हुए कहा, 'इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई महिला किस तरह का विकल्प चुनती है। हम कुछ भी चुनें, अपराध बोध से हमारा पाला पड़ता ही है। हम घर बैठने का फैसला करें तो अपनी नजरों में दोषी बनती हैं और काम पर जाना जारी रखें तो भी खुद को दोषी महसूस करती हैं।' इसीलिए कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने के लिए महिलाओं को गिल्ट मैनेजमेंट सीखना ही होता है। सवाल है कि यह गिल्ट आता कहां से है? निश्चित रूप से कंडीशनिंग की भी इसमें अहम भूमिका है। लेकिन मौजूदा माहौल, आसपास के लोग भी जाने अनजाने इसे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहते हैं। नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉरपोरेशन की कंट्री एग्जीक्यूटिव वेदा सिंह के मुताबिक, 'अवचेतन में इस तरह के पूर्वाग्रह हर किसी में होते हैं। अगर कोई महिला मैटरनिटी लीव से वापस आती है और मैं सोचती हूं कि फलां काम उसके लिए ज्यादा डिमांडिंग होगा और यह सोचकर उसे कोई दूसरा आसान असाइनमेंट देती हूं तो मुझे शर्म आनी चाहिए। मैं अनजाने ही उस महिला के विकल्पों को, उसकी संभावनाओं को कम कर देती हूं।' बहरहाल, मुख्य मसला इस गिल्ट फीलिंग से उबरने में लड़कियों, महिलाओं की मदद करने का है। अच्छी बात है कि वर्कप्लेस में चाइल्ड केयर की सुविधा मुहैया कराने की बात हो या उन्हें मैंटॉर के साथ जोड़ने की, कंपनियां इस दिशा में कदम उठाती दिखने लगी हैं।

AI Image

आधी दुनिया

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ सुकून भरी हवा

8 जुलाई को 'जीवन आनंद' कॉलम में प्रकाशित लेख 'खिड़कियों के रास्ते घर में दाखिल होती खुशी' पढ़ा। किसी भी घर में दरवाजे सुरक्षा के लिए होते हैं, तो खिड़कियां सुकून के लिए। दरवाजे बाहरी दुनिया से हमें काट देते हैं, लेकिन खिड़कियां बाहर देखने की परमिशन देती हैं। बारिश की फुहारों के साथ जब डालियां लचकती हैं, तो वह दृश्य देखते ही बनता है। कुछ खिड़कियां हमेशा खुली रहती हैं, कुछ कभी-कभी खुलती हैं और कुछ कभी नहीं खुलतीं। इन तीनों हालात में खिड़कियों की अपनी कहानी है। लेखक ने बड़ी गहराई से इस विषय पर अपनी बातें रखी हैं।

बबीता रस्तोगी, ईमेल से

■ खिड़कियों से नाता

पुराने जमाने में छोटी-छोटी खिड़कियां होती थीं। इससे अंदर से बाहर देख सकते थे, लेकिन बाहर से भीतर ठीक से नहीं दिखता था। खिड़कियां बनाने का मूल उद्देश्य है कि सूरज की रोशनी और ताजी हवा इस रास्ते से हमारे घरों में दाखिल हो जाए। खिड़कियां बाहरी दुनिया से जोड़ती हैं। खिड़कियां हमारे जीवन का वह हिस्सा हैं, जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ते हुए, हमारे घर को रोशन, हवादार और सुरक्षित बनाती हैं।

दिनेश रावत, ईमेल से

■ उम्मीदों की मुस्कान

अक्सर कहते हुए सुना जाता है कि सोचा हुआ काम बिगड़ जाता है। फिर भी हम भरोसा करना कहां छोड़ते हैं। ट्रेनों में कन्फर्म टिकट नहीं मिलता है, फिर भी इस उम्मीद में वेटिंग टिकट ले लेते हैं कि कन्फर्म हो सकता है। कई बार उम्मीद पूरी हो जाती है, लेकिन कई बार नहीं भी होती। इंतजार बस इंतजार बनकर रह जाता है। यात्रा के दिन टिकट कन्फर्म होने की खुशी क्या है, इसे वही बता सकता है जिसने इसे महसूस किया हो। जैसे ही मेसेज मिलता है कि टिकट कन्फर्म, चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है।

जीवन आनंद

कविता सिंह, ईमेल से

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

उपचुनाव में I.N.D.I.A. चमका - एक खबर

- कहीं इस चमक-दमक में अंधे ना हो जाएं INDIA वाले!

पूनम गुप्ता

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.

संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

ताकि दिमाग दुरुस्त रहे

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दो मुख्य प्रतिद्वंद्वियों डेमोक्रेट प्रत्याशी राष्ट्रपति जो बाइडन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, दोनों के बीच की बहस अब अहम मुद्दों से भटककर उनकी सेहत पर आ टिकी है। हालांकि, दोनों की उम्र में सिर्फ तीन साल का फर्क है। बाइडन जहां 81 साल के हैं, वहीं ट्रंप 78 के। मगर जिस तरह राष्ट्रपति बाइडन पहले सार्वजनिक बहस में ही लड़खड़ाए, उसके बाद उनसे 'कॉग्निटिव टेस्ट' कराने तक की मांग की जाने लगी। दरअसल, इस टेस्ट में कई तरह की जांच की जाती है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि संबंधित इंसान का दिमाग कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है? यह स्थापित बात है कि उम्र के साथ इंसान का दिमाग शिथिल पड़ता जाता है और अब तो दुनिया के ख्यात न्यूरोलॉजिस्ट भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि 75 साल से ऊपर के 25 फीसदी लोगों में संज्ञानात्मक विकार की समस्या हो सकती है। ऐसे में, बाइडन और ट्रंप के बहाने दिमागी सेहत का मसला वैश्विक विमर्श के केंद्र में आ गया है।

वैसे, पहले से ही दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में जुटे हुए हैं कि आयु बढ़ने के साथ क्या-क्या तब्दीलियां आती हैं और उनका हमारे दिमाग से क्या ताल्लुक है? वैज्ञानिक यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आधुनिक तकनीक के जरिये दिमाग की उम्र कुछ घटाई जा सकती है, ताकि उसे संज्ञानात्मक विकार का शिकार बनने से बचाया जा सके? दुनिया भर में बढ़ती जीवन प्रत्याशा को देखते हुए यह शोध काफी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि डिमेंशिया, अल्जाइमर के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, लगभग 5.5 करोड़ लोग डिमेंशिया के शिकार हैं और हर साल लगभग एक करोड़ लोग इसकी गिरफ्त में आने लगे हैं। उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, मोटापा, धूम्रपान, शारीरिक गतिविधियों में कमी, सामाजिक विलगाव, एकाकीपन और अवसाद इसके जोखिम को बढ़ा देते हैं।

जब तक वैज्ञानिक दिमाग की उम्र कम करने की सटीक पद्धति नहीं ढूंढ़ लेते, तब तक इसे स्वस्थ रखने के लिए सामाजिक बनिए, अच्छी नींद लीजिए और जीवनशैली सुधारिए!

दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के जेरोन्टोलॉजी व कंप्यूटेशनल बायोलॉजी विभाग ने ऐसी कंप्यूटर तकनीक विकसित की है, जो मानव दिमाग की उम्र का आकलन कर उसमें आई गिरावट के बारे में बताती है। हालांकि, बिल्कुल सटीक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए अभी और शोध व अध्ययन की दरकार है, जिसमें वैज्ञानिक बिरादरी जुटी हुई है। मगर वैज्ञानिक व डॉक्टर इस बात की ताईद तो करते ही हैं कि हमारी जीवनशैली का दिमाग से गहरा रिश्ता है। अमेरिका में एक शहर है, लोमा लिंडा। इसके बाशिंदों की जीवन प्रत्याशा राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। यहां के काफी लोग लगभग 100 साल जीते हैं और दिमागी रूप से काफी सक्रिय रहते हैं। यहां के लोगों की जीवनशैली पर कई अध्ययन हुए हैं, जिनके निष्कर्ष डॉक्टरों व वैज्ञानिकों की जीवनशैली संबंधी सोच से मेल खाते हैं। इस शहर में शराब व धूम्रपान की बिक्री पर सख्त पाबंदी है, यहां के लोग शाकाहारी या वीगन चीजें खाते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। वहीं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में तंत्रिका विज्ञान के प्रोफेसर मैथ्यू वॉकर दिमाग की सेहत के लिए नींद को भी महत्वपूर्ण कारक बताते हैं। बकौल मैथ्यू, दिमाग का कोई भी ऐसा काम नहीं, जो नींद से बेहतर न हो और पर्याप्त नींद न लेने से खराब न हो। जब तक वैज्ञानिक व डॉक्टर दिमाग की उम्र को कम करने की किसी सटीक पद्धति तक नहीं पहुंचते, तब तक दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए सामाजिक बनिए, पर्याप्त सोइए और जीवनशैली पर ध्यान दीजिए।

हिन्दुस्तान 75 साल पहले 14 जुलाई, 1949

प्रतिबन्ध हटा

भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर से वह प्रतिबन्ध अब हटा लिया है जो गत वर्ष महात्मा गांधी की हत्या के बाद उस पर लगाया गया था। हाल ही में एक संवाद एजेंसी ने यह समाचार प्रसारित किया था कि संघ पर से प्रतिबन्ध हटने के सम्बन्ध में जो संधि-चर्चा चल रही थी, उसमें गतिरोध उत्पन्न हो गया है और निकट भविष्य में संघ पर से प्रतिबन्ध हटने की कोई संभावना नहीं है। इस समाचार के तुरन्त बाद संघ पर से प्रतिबन्ध के हटने पर सर्वसाधारण को आश्चर्य हुए बिना नहीं रहेगा। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वह समाचार वास्तविकता पर आधारित नहीं था। वास्तविकता यह थी कि संघ के विधान और भावी कार्य-पद्धति के बारे में जो आश्वासन सरकार चाहती थी, वह संघ के प्रमुख नेता श्री गोलवलकर ने देना स्वीकार कर लिया था। उसके बाद सरकार के पास प्रतिबन्ध जारी रखने के लिए कोई कारण नहीं हो सकता था। यदि संघ के नेता श्री गोलवलकर ने जिन शर्तों को अब स्वीकार किया है, उनको उन्होंने गत अक्तूबर में ही स्वीकार कर लिया होता, जबकि उन्होंने सरदार पटेल के साथ चर्चा चलाई थी, तो प्रतिबन्ध इतने दिन और जारी नहीं रहता। वह पिछला अध्याय, जिसमें सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच विरोध और कटुता उत्पन्न हुई, अब खत्म समझा जाना चाहिए। केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों द्वारा संघ के आंदोलन से संबंधित बंदियों को, जिनकी संख्या अब तक बहुत थोड़ी रह गई है, शीघ्र ही रिहा कर दिया जायेगा और संघ अपने लिखित विधान के अनुसार खुले तौर पर सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने को स्वतन्त्र होगा।

सरकार संघ से यह चाहती थी कि संघ का एक लिखित विधान हो जो सर्वसाधारण के लिए सुलभ हो, संघ अपनी प्रवृत्तियां सांस्कृतिक क्षेत्र तक सीमित रखे, हिंसा और गोपनीयता का परित्याग करे, देश के विधान और राष्ट्रीय झंडे के प्रति वफादारी प्रकट करे और उसका संगठन लोकतंत्री आधार पर निर्मित हो। सरकार के सामने संघ की ओर से पिछले मार्च में विधान का जो मस्विदा पेश किया गया था, उससे सरकार का पूरा समाधान नहीं होता था। अब सरकार की आपत्तियों के सम्बन्ध में संघ की ओर से जो स्पष्टीकरण किया गया है, उससे सरकार को विश्वास हो गया है कि संघ के विधान पर उसी भावना के साथ अमल किया जायेगा, जैसा कि सरकार चाहती है।

पानी के मौसम में आग की बात

हरजिंदर | वरिष्ठ पत्रकार

वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पर्यावरण में यह बदलाव कृषि और अर्थव्यवस्था पर भी असर डालेगा। इससे निपटने के लिए हमें जो नीति और रणनीति चाहिए, वह कहीं दिखाई नहीं दे रही।

बारिश की बूंदें जब बरसती हैं, तो वे सारे कष्ट धुल जाते हैं, जो गर्मी ने हमें दिए थे। कुछ तो इसलिए कि बारिश तापमान कम करके हमें राहत देती है और कुछ इसलिए कि बारिश जहां ज्यादा हो जाती है, वहां अपने साथ बहुत से नए कष्ट लेकर आती है। ऐसे में, पुरानी परेशानियों को भला कौन याद करता है? अक्सर हम यह सोचने की भी जहमत नहीं उठाते कि साल-दर-साल सर्दी, गर्मी और बरसात के जो कष्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनमें भी आपस में कोई रिश्ता है।

अभी कुछ दिन पहले तक उत्तराखंड और हिमाचल के जंगलों में लगी आग सुर्खियों में थी। सदियों से अटल जंगल और उनका पारिस्थितिकी तंत्र तबाह हो रहा है। इसे लेकर बहुत सी चिंताएं थीं और चारों ओर हाहाकार मचा रही थीं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों में ही उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की 900 से ज्यादा घटनाएं हुईं और लगभग 1,100 हेक्टेयर जंगल नष्ट हो गए। इनमें से कुछ बड़ी घटनाएं ही सुर्खियों में आ सकीं। हो सकता है कि कुछ घटनाएं कहीं दर्ज भी नहीं हुई हों। कुछ ऐसी घटनाएं भी थीं, जिनके गवाह चारधाम की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री भी बने। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश में ऐसी 1,038 घटनाएं हुईं। हिमाचल के जंगलों की आग तो खबरों में भी बहुत ज्यादा जगह नहीं पा सकी।

अब जब उत्तराखंड की तमाम जगहों से बाढ़ और हिमाचल में कुछ जगहों से बादल फटने की खबरें आ रही हैं, तब क्या उस वनाग्नि को याद करने की जरूरत है? बेशक जरूरत है और बहुत ज्यादा है। इस बात को समझने के लिए हमें अमेरिका के न्यू मैक्सिको के एक गांव में जाना होगा, जिसका नाम है रुइडोसो। अपने घने जंगलों के कारण यह गांव बड़ी संख्या में अमेरिकी पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। इस वजह से वहां कई रिजॉर्ट भी खुल गए हैं। कुछ समय पहले इन्हीं खूबसूरत जंगलों में भीषण आग लग गई थी। सब कुछ तबाह हो गया। पर्यटन कारोबार खत्म हो गया और इसमें लगे लोग तो बेरोजगार हुए ही, स्थानीय पर्यावरण का जो नुकसान हुआ, उसका अंदाज लगाना भी मुश्किल है।

कारोबार को तो बहुत जल्दी पटरी पर वापस लाना शायद मुमकिन न हो, लेकिन यहां के निवासी धीरे-धीरे अपने घर फिर से खड़े करने में जुट गए। मगर पिछले मंगलवार को वहां थोड़ी सी बारिश हुई, तो सब कुछ भरभराकर गिरने लगा। यह बहुत सामान्य सी बारिश थी। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज हो गया, जैसा अक्सर बादल फटने पर होता है। पानी अपने साथ राह में आने वाली हर चीज को बहाकर ले गया। गाढ़ा मटियाला पानी, जो बहकर सड़कों तक आया, उसमें ज्यादातर गृह निर्माण की सामग्री थी। रेत, सीमेंट, ईंटें, टाइलें और भी बहुत कुछ।

खबर आई, तो अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस के लोग भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया? थोड़ी सी बारिश में इतना प्रवाह तो नहीं बनता। अगले दिन उससे भी ज्यादा बारिश हुई और जो दृश्य उपस्थित हुए, वे भयानक थे। वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि वहां की जली हुई मिट्टी में बारिश के पानी को सोखने की क्षमता करीब-करीब खत्म हो चुकी है। इसलिए जितना भी पानी बरसा, वह नीचे की ओर ही नहीं बहा, अपने साथ जली हुई मिट्टी और वहां जो कुछ भी था, सब बहाकर ले गया।

भारत में ऐसा कोई अध्ययन अभी सामने नहीं आया, जिससे हम कह सकें कि यहां की स्थितियों में आग और पानी का रिश्ता क्या है? हमें नहीं पता कि इस समय उत्तराखंड से जो बाढ़ की खबरें आ रही हैं, उनमें कितना योगदान भारी बरसात का है और कितना जंगल की आग का? यह कितना जेठ का कष्ट है और कितना आषाढ़ का? हमारी दिक्कत यह है कि हम अक्सर हर मौसम के कष्ट को अलग-अलग करके देखते हैं। उनका आपस में भी कोई नाता है, इसे हम सिरे से भूल जाते हैं। जाहिर है, फिर इनका इलाज भी अलग-अलग करने की कोशिश होती है। गर्मी में हम बर्फीले तूफानों के कहर को भुला देते हैं और बरसात में उस सबको, जो भीषण गर्मी में झुलस गया था।

हालांकि, वैज्ञानिक अरसे से यही कह रहे हैं कि पर्यावरण बदल रहा है, तो हमारा सब कुछ बदल रहा है। गर्मी, सर्दी और बरसात, सब कुछ। जिसे हम मौसम की अति, यानी 'एक्ट्रीम वेदर इवेंट्स' कहते हैं, उसका असर साल भर कहीं न कहीं दिखाई देता है। वे यह भी बता रहे हैं कि पर्यावरण बदलाव ने ऐसी घटनाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ा दिया है। कभी बहुत ज्यादा सर्दी, बर्फबारी, कोहरे की खबरें आती हैं, तो कभी तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड को पार करता दिखाई देता है। कई बार तो एक ही साल में पहले सूखे का असर दिखाई देता है और फिर उसी साल बाढ़ की खबरें भी आने लगती हैं। मौसम की बहुत सारी आपदाएं ऐसी होती हैं, जिनके लिए पहले से बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे, बादल का फटना। लेकिन पर्यावरण में लगातार जो बदलाव हो रहे हैं, उन सबसे अगर हमें निपटना है, तो हर मौसम में सिर्फ फौरी उपाय करने से काम नहीं चलेगा।

हालांकि, एक दूसरा सच यह भी है कि फौरी उपाय भी हम वक्त-जरूरत ठीक से नहीं कर पाते। हर साल जब जंगलों में आग लगती है, तो कहा जाता है कि कृत्रिम बारिश, यानी 'क्लाउड सीडिंग' से इसे बुझाने की कोशिश होगी। लेकिन इससे कोई बड़ी आग बुझाई गई हो, ऐसा कोई बड़ा उदाहरण हमारे सामने नहीं है। यह तभी हो सकता है कि गर्मी से पहले ही इसका प्रयोग हो जाए और हमारे पास आग से निपटने की योजना भी तैयार हो।

हमारी दुनिया का पर्यावरण जिस ढंग से करवट ले रहा है, उसमें शायद इतने से ही बहुत दिन काम नहीं चलने वाला। पर्यावरण, मौसम और लोगों पर पड़ने वाले इनके प्रभाव को लेकर एक संपूर्णतावादी सोच और रणनीति अपनाने की भी जरूरत है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पर्यावरण का बदलाव कृषि और अर्थव्यवस्था पर भी असर डालेगा। दिक्कत यही नहीं है कि इस सबके लिए हमें जो नीति और रणनीति चाहिए, दुर्भाग्य से वह कहीं दिखाई नहीं देती, बल्कि यह भी है कि इस नीति-निर्माण के लिए जिस राजनीतिक विमर्श की जरूरत है, वह भी अपने यहां सिरे से नदारद है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

रोजगार सृजन में रेलवे की भूमिका को कम न आंकें

अमिताभ खरे | वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय रेलवे

भारत की जीवन-रेखा के रूप में भारतीय रेलवे देश के दूरदराज के कोनों को आपस में जोड़ता है, जिससे करोड़ों लोग अपने काम, शिक्षा, व्यापार और छुट्टियां मनाने के लिए यात्रा करने में सक्षम हो पाते हैं। मैदानों, पहाड़ियों, घाटियों और घाटों तक 68,000 किलोमीटर से भी अधिक के विशाल नेटवर्क वाला रेलवे राष्ट्रीय एकता और प्रगति का एक स्थायी प्रतीक है।

इसके परिचालन का पैमाना तो चौंका देने वाला है। भारतीय रेलें प्रतिदिन दो करोड़, 30 लाख से भी अधिक मुसाफिरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं। यह संख्या लगभग ऑस्ट्रेलिया की आबादी जितनी है और इस विशाल उपलब्धि का प्रबंधन 12 लाख से अधिक समर्पित कर्मचारी करते हैं, जो हमारे देश के 17 क्षेत्रों और लगभग 68 मंडलों में काम कर रहे हैं। लोको पायलटों और इंजीनियरों से लेकर पैरामेडिक्स व रेलवे सुरक्षा बल तक, भारतीय रेलवे देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, जो अत्यंत लोकप्रिय करियर की पेशकश करता है और अपने कार्यबल के लिए वेतन व अन्य लाभों पर एक बड़ी रकम खर्च करता है। हरेक वेतन आयोग के बाद उसका यह व्यय बढ़ता जाता है। पिछले दशक में भारतीय रेलवे ने अभूतपूर्व बदलाव देखा है। रिकॉर्ड स्तर पर विद्युतीकरण, आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत, रेल लाइनों के विस्तार, उन्नत सुरक्षा उपाय से लेकर आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने जैसे कई कदम इनमें शामिल हैं। यहां तक कि महामारी के दौरान भी, जब कई निजी कंपनियों ने छंटनी और वेतन-कटौती जैसे उपायों का सहारा लिया था, भारतीय रेलवे ने सब्सिडी वाली आवास सुविधा, मुफ्त चिकित्सा सहायता, बोनस से लेकर पूर्ण वेतन लाभ व भत्ते की अपनी पेशकश को जारी रखा। असमय मृत्यु, अपंगता या लापता रेलकर्मियों के बच्चों की अनुकंपा-नियुक्ति भी इसकी संवेदनशीलता और कर्मचारी-हितैषी प्रकृति को दिखाती है।

बीते एक दशक में इसने ग्रुप-सी के विभिन्न पदों पर 5.02 लाख से भी अधिक नियुक्तियां की हैं, जो पूर्व के दशक से काफी अधिक है।

दरअसल, भारतीय रेलवे की सफलता के मूल में इसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है- इसका मानव संसाधन। देश का पहिया निरंतर गतिशील रहे, इसके लिए रेलवे सैकड़ों तरह की तकनीकी व गैर-तकनीकी भूमिकाओं वाले कार्यबल के साथ अपने कर्मचारियों की विशेषज्ञता, समर्पण और जबर्दस्त तालमेल पर निर्भर है। इसलिए इस विशालकाय संगठन में सही प्रतिभाओं की भर्ती कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। देश भर में फैले 21 रेलवे भर्ती बोर्ड दूरदराज के इलाकों तक पहुंचकर 15 भारतीय भाषाओं में परीक्षाएं आयोजित करते हैं, ताकि इन भर्तियों को अधिक से अधिक समावेशी बनाया जाए।

हाल ही में एक भर्ती अभियान में 1.39 लाख पदों के लिए 2.37 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को कायम रखते हुए इस परीक्षा को सैकड़ों शहरों (211 शहरों के 726 परीक्षा केंद्रों) में कई भाषाओं में आयोजित करना एक बड़ी कामयाबी है। रेलवे की नियुक्ति परीक्षाओं में कंप्यूटर-आधारित परीक्षा-प्रणाली अपनाने से धोखाधड़ी की आशंकाएं भी कम हो गई हैं और भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी आई है। पिछले एक दशक में इसने ग्रुप-सी के विभिन्न पदों पर 5.02 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति की है, जो इससे पूर्व के दशक की 4.11 लाख संख्या से काफी अधिक है। रेलवे इस समय अपने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और अपनी पहुंच के विस्तार में जुटा हुआ है, जिनसे रोजगार के अधिक अवसर पैदा होने की उम्मीद है। रोजगार सुनिश्चित करने के इरादे से ही 15,000 से अधिक नए पद सृजित किए गए हैं। 19,500 रिक्तियों को भरने के लिए रोजगार अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। इस साल और अधिक रिक्तियां अधिसूचित होने की उम्मीद है।

बहरहाल, हालिया नियुक्ति के आंकड़े नौकरियों के सृजन के मामले में भारतीय रेलवे की अहमियत रेखांकित करते हैं। अपनी भर्ती रणनीति में लगातार सुधार कर और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर यह संगठन न केवल अपनी मानव संसाधन जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि देश में बड़े पैमाने पर प्रतिभा अधिग्रहण के मानक भी स्थापित कर रहा है। जाहिर है, अपनी मानव पूंजी के नियमित उपयोग से यह संगठन देश के समावेशी विकास और समृद्धि के नए-नए अध्याय लिख सकता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

आषाढ़ की पूर्णिमा

आषाढ़ मास में गुरु पूर्णिमा आती है। वैसे तो पूर्णिमा हरेक महीने होती है, लेकिन आषाढ़ की पूर्णिमा खास महत्व रखती है, क्योंकि उस दिन भारत में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। उस दिन चांद बादलों से घिरा रहता है और यह काव्यात्मक घटना है।

सवाल है कि आषाढ़ में तो चांद दिखाई ही नहीं देता, फिर उसे ही गुरु क्यों बनाया, जबकि बादल यानी शिष्य उसके समूचे उजाले को ढक देते हैं? दरअसल, गुरु में ऐसी अथाह करुणा होती है कि वह अपने शिष्यों के पूरे अंधेरे को पी जाता है और बदले में उन्हें अपना शीतल उजाला देता है, बशर्ते कि शिष्य समर्पित भाव-दशा में हो। वह गुरु के प्रति झुका हुआ, अनुग्रह से लबालब हो, क्योंकि यह प्रेम का आदान-प्रदान है, बुद्धि का नहीं। गुरु से कोई तर्क नहीं किया जाता।

शिष्यत्व ऐसी बात है, जो आप जिंदगी भर कर सकते हैं। शिष्य न केवल आध्यात्मिक अर्थों में बनना है, वरन जीवन के हर कदम पर हमें कुछ न कुछ सीखते रहना है। अनंत लोग भरे पड़े हैं, अनंत घटनाएं घट रही हैं। आप सजग रहें और आपमें अहंकार की अकड़ न हो, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, सिखाने वाला छोटा बच्चा भी हो सकता है, कोई चींटी हो सकती है या कोई शिक्षक। हर घटना कुछ न कुछ सिखा सकती है, लेकिन उसके लिए शिष्य होना जरूरी है और वह बड़ी कठिन बात है। मनुष्य को सीखने के लिए जो विनम्रता, चित्त की सरलता चाहिए, वह आजकल पाई नहीं जाती।

जो सीखने को तैयार है, उसे अपनी अस्मिता और अहंकार को छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि अहंकार सीखने न देगा। अहंकार आपको बदलने न देगा। अहंकार अपने से ऊपर किसी को रखने को कभी राजी ही नहीं है। सीखने को वह तैयार है, जिसने यह अनुभव कर लिया है कि अब तक अपने तईं बहुत उपाय किए, पर कुछ भी सीख न पाया। सीखने को वही तैयार है, जिसने देख लिया अपने हृदय के गहन अंधकार को। जिसने देख लिया कि मैं अपने जीवन को सिर्फ उलझा रहा हूं, सुलझा नहीं रहा, बल्कि जितना सुलझाने की कोशिश करता हूं, बात और उलझती चली जाती है। ऐसे पीड़ा

आषाढ़ मास में गुरु पूर्णिमा आती है, पर सवाल है कि आषाढ़ में तो चांद दिखाई ही नहीं देता, फिर उसे ही गुरु क्यों बनाया, जबकि बादल यानी शिष्य उसके समूचे उजाले को ढक देते हैं?

के क्षणों में, ऐसी संताप की अवस्था में अपनी परिस्थिति को पूरा-पूरा देखकर शिष्यत्व का जन्म होता है। गुरु तो हमेशा मौजूद है, सीखने वाले नहीं होते।

ओशो कहते हैं, 'भारत में बड़ी पुरानी लोकोक्ति है कि जब सतयुग था, तब गुरु की इतनी जरूरत न थी, लेकिन कलियुग में गुरु की बड़ी जरूरत होगी। आखिर इसका क्या कारण है!... हिंदू किस हिसाब से बांटते हैं संसार को? सतयुग वे कहते हैं उस समय को, जब लोग बड़े सचेत थे, सावधान थे। और कलियुग कहते हैं उस युग को, जब लोग बड़े सोए हुए हैं, मूर्च्छित हैं।'

अमृत साधना

ऋषि सुनक | नेता प्रतिपक्ष, ब्रिटेन

चौदह साल सत्ता में रहने के बाद यह महत्वपूर्ण है कि कंजर्वेटिव पार्टी का फिर से निर्माण हो। इसलिए अब हम महामहिम के आधिकारिक विपक्ष की अहम भूमिका पेशेवर, प्रभावी व विनम्र तरीके से निभाएंगे।

अनुलोम-विलोम
भारतीय लोकतंत्र

भारत में लोकतंत्र की जड़ें काफी गहरी

जो लोग भारत में लोकतंत्र के खत्म होने या संविधान के संकट में होने के गीत गाया करते थे, उनके लिए 'प्यू रिसर्च' की रिपोर्ट आंखें खोलने का काम करेगी। इस रिपोर्ट में 31 शक्तिशाली और विकसित देशों को शामिल किया गया, जिनमें से भारत दूसरा ऐसा देश बना, जहां की अधिकतर आबादी ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को संतोषजनक माना। सर्वेक्षण के मुताबिक, 77 फीसदी भारतीय अपने देश के लोकतंत्र से खुश हैं। हमसे ऊपर एकमात्र सिंगापुर है, जहां की 80 फीसदी आबादी ने लोकतंत्र को लेकर संतुष्टि का भाव जाहिर किया है। यह बताता है कि कुछ लोग बेशक लोकतंत्र के खत्म होने के दावे करें, पर जनता को यह पसंद नहीं है और उनकी नजरों में भारतीय लोकतंत्र आज भी काफी अच्छी तरह काम कर रहा है।

बहरहाल, इस रिपोर्ट में यह भी देखने वाली बात है कि सबसे ताकतवर देशों में शुमार अमेरिका में 68 प्रतिशत लोगों ने अपने यहां की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति नाखुशी जताई है। वहां लोकतंत्र को संतोषजनक मानने वालों का प्रतिशत महज 31 है। कमोबेश इसी तरह का हाल जर्मनी (45 फीसदी नाखुश, 55 फीसदी संतुष्ट), ब्रिटेन (60 फीसदी नाखुश और 39 फीसदी खुश), फ्रांस (65 फीसदी नाखुश, 35 फीसदी खुश) जैसे देशों का भी है, जबकि ये देश वक्त-वक्त पर भारत को ही लोकतंत्र की नसीहतें देते रहते हैं। जाहिर है, ये देश अपने गिरेबान में झांकना पसंद नहीं करते और 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' की तर्ज पर दूसरों को उपदेश देना पसंद करते हैं, लेकिन असलियत में इनको अपने उपदेशों पर पहले खुद अमल करना चाहिए और लोगों को यह एहसास दिलाना चाहिए कि उनके देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आम जन के हित में काम कर रही हैं। इससे लोगों का तंत्र पर भरोसा बढ़ेगा और लोकतंत्र से जुड़े ऐसे सर्वेक्षणों में उनके देश का कद ऊंचा होगा।

जाहिर है, यह रिपोर्ट फिर से स्पष्ट करती है कि भारत न सिर्फ सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि अपने लोगों की आकांक्षाओं को भी पूरा करने में सफल हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ी ताकत के रूप में इसका उभरना इसी की परिणति है। यहां के सियासतदां सही मायने में लोकतंत्र को जमीन पर उतार रहे हैं, जिसके कारण लोगों का उन पर भरोसा बना हुआ है। अब जरूरी यह है कि इसे और मजबूत किया जाए और देश को जल्द ही विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़ा किया जाए। इस काम में उन लोगों को भी आगे आना चाहिए, जो लोकतंत्र के खत्म होने का राग अलापते रहते हैं।

कमल प्रजापति, टिप्पणीकार

कुछ लोगों के कारण यह नेता-तंत्र बन रहा

हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां के लोगों का अपने लोकतंत्र पर विश्वास बना हुआ है। अगर लोगों को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं होता, तो वे लंबी-लंबी कतारें लगाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करते। उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि अपने मत द्वारा अपनी पसंद की ऐसी सरकार चुनना, जो उनके प्रति उत्तरदायी हो। यह लोकतंत्र ही है कि यहां लोग खुलकर आलोचना भी करते हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन जैसे सांविधानिक अधिकारों का इस्तेमाल भी करते हैं। इस लिहाज से अमेरिकी थिंक टैंक 'प्यू रिसर्च सेंटर' की रिपोर्ट भरोसा जगाती है, जिसके तहत 31 देशों में सर्वेक्षण करके यह जानने का प्रयास किया गया कि कितने लोग अपने-अपने देश के लोकतंत्र से खुश हैं? भारत में 77 फीसदी लोगों ने लोकतंत्र पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया, जबकि सिर्फ 20 फीसदी लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से खुश नजर नहीं आए। पर इस 20 फीसदी को भी कोई छोटा आंकड़ा नहीं मानना चाहिए। यह संकेत है कि कुछ गलत लोगों के राजनीति में आने के कारण यहां के तंत्र के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा होने लगा है। ये गलत लोग राजनीति में आकर सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। इस कारण वे आम लोगों को अनदेखा करते हैं। वास्तव में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कुछ स्वार्थी लोगों के कारण दिन-प्रतिदिन नेता-तंत्र बनता जा रहा है। स्वार्थ के इस दौर में सबको अपने पेट और तिजोरियों की चिंता है, लोकतंत्र की मानो किसी को परवाह ही नहीं? जबकि, गणतंत्र वह शासन प्रणाली है, जिसमें जनता पर शासन करने वाला कोई राजा या रानी नहीं, बल्कि जनता का ही चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। मगर आज कुछ राजनेताओं ने अपने कर्मों से इस परिभाषा को बदलकर रख दिया है। लिहाजा, यह आम लोगों के लिए चुनौती है कि वे इसको कैसे ठीक करें?

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

असल लोकतंत्र से दूर

हम चाहे, जितने भी दावे कर लें, लेकिन अब यहां लोकतंत्र का वह स्वरूप नहीं रहा, जो चार दशक पहले तक था। यहां तो नेताओं से नैतिकता की अपेक्षा करना ही गलत है। 'प्यू रिसर्च' के सर्वे में भले ही ज्यादातर लोगों ने लोकतंत्र को पसंद किया है, लेकिन असलियत में कई ऐसी गड़बड़ियां हैं, जिनको दूर किए बिना देश में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती।

दीपक, टिप्पणीकार

बेस्ट सेलर से सबक | क्रिस बेली

एक बार में एक काम पर हाइपरफोकस

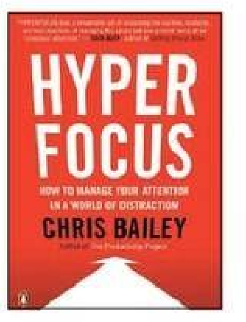

क्रिस बेली की यह किताब हमें बताती है कि खुद को अधिक तनावग्रस्त बनाए बिना या काम का बोझ बढ़ाए बिना पूरी तरह से फोकस कैसे करें। एक बार में एक टास्क पर हाइपरफोकस करने की यह बात डिस्ट्रैक्शंस से भरे मौजूदा दौर में बहुत जरूरी हो चुकी है।

पीछे हटें और स्पेस दें

फोकस क्यों मायने रखता है? क्योंकि किसी भी पल में, हम हमेशा किसी न किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं। यह ध्यान लगातार अनेक चीजों में बंटता रहता है। हाइपरफोकस को अर्जित करने के लिए कुछ लोग अपना फोन घर पर ही छोड़ देते हैं तो कुछ डिनर के समय वाई-फाई डिसकनेक्ट कर देते हैं। इसका कारण यह है कि लगातार कनेक्टिविटी हमारे ध्यान और उत्पादकता पर पड़ने वाले सबसे खराब व्यवधानों में से एक है। रचनात्मकता और उत्पादकता को बढ़ावा देने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है ध्यान हटाना सीखना- यानी पीछे हटना, खुद को थोड़ा स्पेस देना और किसी भी चीज से बाधित नहीं होना।

फोकस की सीमा है

आप कितनी चीजों पर फोकस कर सकते हैं, इसकी सीमा है। हमारा ब्रेन हर सेकंड में 1.1 करोड़ बिट्स रिसीव करता है, जिनमें से हमारा माइंड केवल 40 को प्रोसेस कर सकता है। हम हाइपर-फोकस्ड नहीं होंगे तो ग्रहणशीलता लगातार घटती रहेगी।

डिस्ट्रैक्शंस से बचें

अध्ययनों से पता चलता है कि काम करते समय हम औसतन 40 सेकंड्स में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या कोई व्यवधान आ जाता है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि व्यवधान बाहर से आते हैं, जबकि डिस्ट्रैक्शंस हम खुद ही अपने लिए क्रिएट करते हैं। इन डिस्ट्रैक्शंस को कम किए बिना हाइपरफोकस की स्थिति को अर्जित करना और काम में ज्यादा प्रोडक्टिव होना सम्भव नहीं है।

खुद से सवाल पूछें

हम ऑटो-पायलट मोड पर चलना पसंद करते हैं। हमारी 40% गतिविधियां वास्तव में हमारी आदतें होती हैं, जिनके लिए सचेत-प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। किताब पढ़ते समय खुद से पूछना चाहिए कि हम उस पर कितना अटेंशन दे पा रहे हैं। रिसर्च बताते हैं कि जब दिमाग विषय से भटक रहा हो तो आंखें अपने सामने खुले पेज को धीमी गति से स्कैन कर पाती हैं।

बेहतर फोकस करें

बेहतर तरीके से फोकस कैसे करें? फोन दूर रखें। जब हमारा दिमाग किसी काम को करने से बचना चाहता है और दिलचस्प चीजों पर फोकस करना चाहता है तो फोन उसे इसकी सुविधा मुहैया कराता है। स्मार्टफोन को हमारे डोपामाइन को ट्रिगर करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इससे बचने के लिए सजग होकर देखें कि आप दिन में कितनी बार फोन देखते हैं और क्यों?

बार-बार रीसेट-ब्रेक्स लें

अपने अन-प्रोडक्टिव कार्यों पर नजर बनाए रखें। पता करें कि आप बार-बार ईमेल क्यों चेक करते हैं या सोशल मीडिया पर क्यों चले जाते हैं? हम जितने ज्यादा ऑटो-पायलट मोड पर होते हैं, उतना ही अपना समय बरबाद कर रहे होते हैं। आपको अपना फोकस कहां पर रखना चाहिए, इसको लेकर इंटेंशनल रहें और इसके लिए बार-बार रीसेट-ब्रेक्स लेते रहें।

अनंत ऊर्जा | ज्ञानवत्सल स्वामी, प्रेरक वक्ता और विचारक

जीवन मूल्य हों तो संसार आपका है

वैल्यूज़ में वह ताकत होती है कि वह हजारों वैल्युएबल चीजें खड़ी कर सकती है। भौतिक चीजों को हमेशा वैल्यूज़ से जोड़कर देखना होगा, नहीं तो एक दिन उनकी चमक खो जाएगी। पैसों से अच्छा मकान तो खरीद सकते हैं, लेकिन उसे घर बनाने के लिए जीवन मूल्य चाहिए। आपके जीवन मूल्य ही अच्छे जीवन की बुनियाद हैं।

जीवन में बेशकीमती चीजें इकट्ठी करें, लेकिन ये चीजें जीवनमूल्यों से समझौता करके नहीं जुटानी चाहिए। आप अपने आप से पूछें कि आप रियल लाइफ जी रहे हैं या रील लाइफ।

वैल्यूज़ (जीवन मूल्य) और वैल्युएबल (कीमती चीजें) दोनों को हमें समझना होगा। अगर आप भौतिक चीजों को जीवन मूल्यों से जोड़ देंगे तो जीवन चमक उठेगा। वैल्यूज़ में वह ताकत होती है कि वह हजारों वैल्युएबल चीजें खड़ी कर सकती है। मैं यह नहीं कहता कि जीवन में वैल्युएबल चीजें इकट्ठी न करें, लेकिन ये चीजें जीवन मूल्यों से समझौता करके नहीं जुटानी चाहिए।

आपकी प्रतिभा और चेहरा-मोहरा ईश्वर का दिया हुआ है। अगर आप घमंड दिखाते हैं और वैल्यूज़ से नहीं जुड़े रहेंगे तो ये कोई भी बेशकीमती चीज ज्यादा समय तक आपके पास नहीं रहने वाली। अपने एटीट्यूड और ईगो को लेकर सतर्क नहीं रहे तो वो दिन दूर नहीं जब समाज, आसपास के लोग आपको भुला देंगे।

पैसों से आप अच्छा मकान तो खरीद सकते हैं, लेकिन पैसों में वो क्षमता नहीं कि वो मकान को घर में तब्दील कर दे। पैसों से अच्छा बिस्तर तो ले सकते हैं, लेकिन अच्छी नींद पैसों से नहीं आ सकती। पैसों से अच्छा हेल्थकेयर प्लान तो ले सकते हैं, लेकिन अच्छी हेल्थ नहीं ले सकते। कहने का तात्पर्य है कि दुनिया में सैकड़ों ऐसी चीजें होंगी, जो रुपयों-पैसों से खरीदी जा सकती हैं, लेकिन ऐसी चीजों की संख्या हजारों में होंगी, जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती।

पनीर, दही, बटर, बटरमिल्क, खोया...ये सब दूध से बने उत्पाद हैं। फिर भी बाजार में उनकी कीमत अलग-अलग है। इसी तरह हम भी ईश्वर की बनाई कृति हैं, लेकिन हमारी भी कीमत अलग है। मतलब दो चीजें कीमत तय कर रही हैं। पहली तो जीवन के आखिर में आपको जीवन से कितना संतोष मिला। दूसरा, आपने अपने और दूसरों के मन में अपनी छवि कैसी बनाई है। यह सब निर्भर करता है कि आपके जीवन मूल्य कैसे रहे हैं। एक अच्छे जीवन की यही बुनियाद हैं।

अमेरिका गायक एल्विस प्रेसली और भारत की चेतना में बसी मीराबाई के बीच एक तुलना करते हैं। इसे केस स्टडी भी मान सकते हैं। एल्विस के जीवनीकार का दावा है कि एल्विस दुनिया में दूसरे व्यक्ति हैं, जो अपने पहले नाम से ही प्रसिद्ध रहे। वह जब 21 साल के थे, तभी उनके नाम से बाजार में 78 उत्पाद थे। उनके पास 500 मिलियन डॉलर की संपत्ति थी।

अब मीराबाई, जिन्हें एक वक्त के भोजन के लिए भी मंदिर में इंतजार करना पड़ता था। कोई भौतिक संपत्ति नहीं थी। आपके मन में सवाल आ सकता है कि इन दोनों के बीच तुलना का क्या औचित्य है? जरा रुकिए। एल्विस जब प्रसिद्धि के चरम पर थे, तो उनकी सेक्रेटरी ने पूछा कि इस मुकाम पर पहुंचकर आपको कैसा लग रहा है। एल्विस का जवाब था कि मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। महज 42 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उनके पास सबकुछ था फेम, टैलेंट, मनी। वहीं, मीराबाई, जिनके भजनों पर 300 से ज्यादा शोध-अध्ययन हो चुके हैं। आज 500 सालों बाद भी मीराबाई हमारी चेतना में रची-बसी हैं क्योंकि मीराबाई के पास सबसे बड़ा जीवन मूल्य था- 'पायो जी मैंने राम रतन धन पायो...' ये ताकत है वैल्युएबल्स से ज्यादा वैल्यूज़ की।

एक फोटोग्राफर ने अपने स्टूडियो में एक बोर्ड लगाया और उस पर लिखा कि जैसे आप दिखते हैं, अगर वैसी ही तस्वीर चाहिए तो 20 रुपए लगेंगे। आपको लगता है कि जैसा आपको दिखना चाहिए, अगर वैसी तस्वीर चाहिए तो 30 रुपए लगेंगे और अगर अगर ऐसी तस्वीर क्लिक कराना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों की नजर में खुद को कैसे देखते हैं, तो उसके 50 रुपए लगेंगे। कई सालों बाद उस फोटोग्राफर ने अपने अनुभव को कागज पर उकेरा। उसने बताया कि स्टूडियो में आने वाले 90 फीसदी लोगों ने 50 रुपए देकर ऐसी तस्वीर खिंचाने की इच्छा जताई।

जब आप कोई टी-शर्ट, पैंट आदि खरीदने जाते हैं तो उसे हाथ में लेकर मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? मैं इसमें कैसा लगूंगा / लगूंगी या फिर ये सोचते हैं कि दूसरों को यह कितने अच्छे लगेंगे? यहां पहला विचार वैल्यू है तो दूसरा ख्याल वैल्युएबल है। आप खुद से पूछें कि आप रियल लाइफ जी रहे हैं या रील लाइफ।

प्रेरक पत्र

जीवन की हर कठिनाई एक नया अवसर है...

जर्मनी के प्रसिद्ध कवि रिल्के ने यह प्रेरक पत्र अपने एक युवा कवि-मित्र को लिखा था।

प्रिय मित्र,

एक बार मैं पेरिस में एक पुल पर खड़ा था। मेरे सामने एक सड़क थी, जो सीन नदी को चली जाती थी। मैंने देखा एक शव को कुछ लोग लेकर चले आ रहे हैं। उस व्यक्ति ने नदी में कूदकर जान दे दी थी। मैंने अपने करीब एक आवाज सुनी। एक गाड़ीवान कह रहा था- 'आप ही बतलाइए, अगर वो यह करने में सक्षम था, तब तो वो कुछ भी कर सकता था!'

मैं अचरज से उसे देखता रहा, जो यह कहते ही फिर अपनी गाड़ी की ओर चला गया था। सच ही तो था : जिस व्यक्ति में यह क्षमता हो कि जीवन के प्रति प्रबल लालसा को झुठलाकर उसे नष्ट कर दे, वह क्या कुछ नहीं कर सकता है?

उस दिन के बाद से मैंने हमेशा इस बात को जाना है कि हमारे साथ होने वाली बुरी से बुरी चीज और गहरी हताशा भी हमारे अस्तित्व पर ऐसा प्रहार है, जिसे हमारा हृदय बदलकर उसका रूपांतरण कर सकता है। जब चीजें कठिन और लगभग असह्य हो जाएं, ऐन तभी हम स्वयं को एक ऐसी स्थिति में पाते हैं, जब हम रूपांतरण के सबसे करीब हों।

जीवन की सबसे निराली बात यही तो है कि यहां हर कठिनाई अपने भीतर एक नया अनुक्रम और एक नई व्यवस्था खोज निकालने का मौका है।

जीवन-ऊर्जा की सबसे बड़ी बात यही है कि वह बुराई में भी ना केवल अच्छाई खोज लेती है, बल्कि उसे अच्छा बना भी देती है। अगर हम मनुष्यों को यह उपाय नहीं मालूम होता तो हम बुराई से बच नहीं सकते थे।

किसी भी मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह बुरा है, बुराई से जरा-सा आगे बढ़ने भर से वह बुरा नहीं रह जाता। बुराई से ज्यादा क्षणभंगुर कुछ भी नहीं।

तुम्हारा हितैषी,
राइनर मारिया रिल्के

देश-दुनिया की सकारात्मक परंपराएं

म्यांमार : दुनिया का इकलौता देश जहां लोग चाय खाते हैं

• पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय चाय है। दुनिया में चाय की खपत औसतन 6.7 अरब किलोग्राम है। वैसे दुनिया में छह तरीके की चाय लोकप्रिय हैं- ब्लैक, ग्रीन, ऊलॉन्ग, वाइट, पुएर और डार्क टी। लेकिन म्यांमार में लोग चाय पीते नहीं खाते हैं।

• दरअसल म्यांमार में फर्मेंट की हुई चाय की पत्तियां खाने की परंपरा है। यह म्यांमार का राष्ट्रीय प्राचीन फूड माना जाता है। यहां आप किसी के मेहमान बनकर जाएं या कोई सार्वजनिक आयोजन हो, यहां तक कि रोजमर्रा में भी लोग चाय की पत्तियां खाते हैं।

म्यांमार में कहा जाता है कि लाफे टो के दौरान हर चीज माफ कर दी जाती है।

• चाय की पत्तियों वाली डिश को लाफे टो (laphet thoke) कहते हैं। इसे बनाने के लिए इसे उबालने के बाद दो से तीन महीने तक फर्मेंट होने रख देते हैं। इसके बाद पत्तियां इस्तेमाल की जाती हैं। और इसे मूंगफली, कॉर्न या सलाद आदि के साथ मिलाकर खाते हैं।

• म्यांमार में कई अन्य डिश के साथ भी चाय की पत्तियां खाते हैं। इसका स्वाद पारंपरिक चाय से बिल्कुल अलग होता है। ये थोड़ी कड़वी और मीठी लगती हैं। यह कुछ-कुछ वाइन जैसा स्वाद होता है। यह डिश स्वागत-सत्कार में मुख्य तौर पर इस्तेमाल होती है।

दैनिक भास्कर
अब आप NYT के सभी आर्टिकल DB एप पर हर सोमवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

© The New York Times

दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

इजराइल-हमास जंग

गाजा के 80 प्रतिशत निवासी बेघर हो गए हैं

पैट्रिक किंग्सले, नाटन ओडेनहीमर, आरोन बॉक्सरमैन

गाजा में हमास ने इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई है। हमास के लड़ाके आसपास के रिहायशी इलाकों में छिपते हैं, मीलों लंबी सुरंगों, मकानों, मस्जिदों और बच्चों के बेडरूम में अपने हथियार रखते हैं। वे सादे कपड़ों में सेंडल या ट्रैकसूट पहनकर निकलते हैं और इजराइली सैनिकों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वे अपने वाहनों में बारूदी सुरंगें छिपाते हैं। नागरिक इलाकों से रॉकेट लॉन्चर छोड़ते हैं। हमास की लड़ाई गाजा के फिलिस्तीनियों पर भारी पड़ रही है। गाजा के 80 प्रतिशत निवासी बेघर हो गए हैं और अधिकतर बिल्डिंग नष्ट हो गई हैं। इसकी तुलना में इजराइल के कुल 350 सैनिक मारे गए हैं। मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 37-38 हजार बताई जाती है। हमास की युद्ध नीति ने उसका अस्तित्व बचाए रखा है।

© The New York Times

इस हफ्ते चर्चा में...

दो साल में माइक्रोसॉफ्ट का बाजार मूल्य 70% बढ़ा

1 लाख करोड़. रुपए का मुनाफा हुआ है अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन को पिछले वित्तीय वर्ष में। वैसे, बैंक को डूबते कर्ज बट्टे खाते में डालने पर 50 हजार करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है।

275 लाख करोड़ रुपए है माइक्रोसॉफ्ट का बाजार मूल्य। नए विश्लेषण के अनुसार कंपनी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर अधिक जोर लगाने से बीते दो साल में उसका बाजार मूल्य 70 प्रतिशत बढ़ा है।

8 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है चीन को जून में विदेश व्यापार में। चीन के कस्टम विभाग ने बताया कि निर्यात बढ़ने और आयात कम होने से ऐसा हुआ है।

एक्सपर्ट ओपिनियन • ट्रम्प पर हमले से देश की प्राथमिकताएं नहीं बदलनी चाहिए

अमेरिका में हिंसा बढ़ रही है; अब नेताओं को तीखी भाषा और दुष्प्रचार से बचना होगा

डेविड फायरस्टोन
न्यूयॉर्क टाइम्स की संपादकीय टीम के डिप्टी एडिटर

शनिवार को डोनाल्ड ट्रम्प पर गोली चलाने वाले शूटर का मकसद या पृष्ठभूमि हम फिलहाल नहीं जानते हैं। लेकिन, उसकी गन ने अमेरिका की राजनीतिक प्रक्रिया पर सीधा निशाना लगाया है। जैसा कि कुछ समय पहले ही राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था, हर किसी को गोलियों के भय के बिना राजनीतिक रैली में शामिल होने का अधिकार होना चाहिए। इस देश में ट्रम्प किसी हमले की चिंता किए बगैर कहीं भी जाकर अपने बात कह सकते हैं। लेकिन, चुनाव में एक-दूसरे से विचारों या व्यक्तित्वों की होड़ के बदले गोलियों ने अराजकता, दहशत की जगह ले ली है। यह गहरा संदेह भी उभरा कि क्या राजनीति का कोई मूल्य है।

दरअसल राजनीतिक हिंसा के कृत्यों का इरादा तो रक्तपात का होता है लेकिन अक्सर उनका लक्ष्य उससे कहीं ज्यादा रहता है। 1981 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर गोलीबारी जैसी घटनाएं गुस्से या नफरत का विस्फोट रहीं। वे मानसिक बीमारी के कारनामे भी होते हैं। आमतौर पर मुख्य उद्देश्य को कम याद रखा जाता है। इसकी बजाय सामूहिक धारणा रहती है कि सभ्यता के ताने-बाने को एक बार फिर तार-तार कर दिया गया है।

राजनीतिक जीवन पर हिंसा का प्रभाव बढ़ रहा है

अमेरिकी लोकतंत्र पर लंबे समय से हिंसक कृत्यों की छाया रही है लेकिन कुछ समय से इनका साया गहराया है। ट्रम्प के राजनीतिक एजेंडा का हिंसा से विरोध नहीं किया जाना चाहिए। शनिवार का हमला एक त्रासदी है। अमेरिकियों के सामने अब चुनौती है कि वे इस समय को बड़ी त्रासदी में बदलने से रोकें। चुनाव का फैसला जनता के वोटों से होना चाहिए।

हम लोगों में से जिन्होंने 1960 के दशक की राजनीतिक हत्याओं को देखा है और जिन्होंने उसके बाद के वर्षों में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का कवरेज किया है, वे हर गनशॉट और धमाके से उभरी हताशा भूल नहीं सकते हैं। चाहे उनका इरादा ऐसा रहा हो या न रहा हो। जिन लोगों ने ऐसे कारनामे किए हैं वे आगाह करते हैं कि कोई नेता सुरक्षित नहीं है, राजनीति बेकार है और असली सत्ता रक्तपात के निजी कारनामों में निहित है।

इसलिए जरूरी है कि सभी विचारधाराओं के निर्वाचित नेता अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के समर्थन में खड़े हों जो कि कमजोर नजर आ रही है। यह महत्वपूर्ण है कि सभी राजनीतिक उम्मीदवार वोटरों के बीच ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं। ट्रम्प पर हमले की घटना को एक व्यक्ति का कृत्य मानते हुए अहम है कि कोई भी रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक नेता दूसरी पार्टी, उसके नेताओं और सरकार को दोषी न ठहराए। यहां तक कि भयावह घटना के संबंध में तीखी भाषा का भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कई राजनेता पहले ही कह चुके हैं कि हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन, उन्हें यह कहने की भी जरूरत है कि झूठी और गलत जानकारी के जरिए किसी अन्य द्वारा की गई हिंसा का इस्तेमाल विभाजन बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लोगों पर झूठे दोष मढ़ने से बचा जाए।

ट्रम्प या बाइडेन या किसी अन्य उम्मीदवार की सामान्य राजनीतिक आलोचना हत्या के प्रयास का कारण नहीं है। किसी शूटर के कृत्य से अमेरिकी राजनीति या इस देश की प्राथमिकताओं के बारे में राष्ट्रीय चर्चा को बदलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

© The New York Times

टेक्नोलॉजी • नई इंडस्ट्री बनाने पर जोर

सऊदी ने वीडियो गेम इंडस्ट्री पर किया तीन लाख करोड़ रु. निवेश

एली टैन

सऊदी अरब में अर्थव्यवस्था के लिए नई इंडस्ट्री बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में सऊदी अब वीडियो गेम के बाजार पर भारी निवेश कर रहा है। अपनी अर्थव्यवस्था को तेल के अलावा दूसरे क्षेत्रों से जोड़ने की योजना के तहत सऊदी सरकार 2030 तक वीडियो गेम्स पर 3.17 लाख करोड़ रुपए लगाएगी। यह निवेश 58 लाख करोड़ रुपए के वेल्थ फंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (पीआईएफ) के जरिए किया जाएगा। इस समय भी सऊदी अरब के रियाद में ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चल रहा है।

हालांकि, यह साल वीडियो गेम इंडस्ट्री के लिए आय के हिसाब से मुश्किल रहा है। बड़े पैमाने पर वर्कर्स की छंटनी हुई है। दुनिया की बड़ी वीडियो गेम कंपनियां और इंफ्लुएंसर चुपचाप सऊदी अरब के साथ भागीदारी कर रहे हैं। पीआईएफ के फंड से चल रही कंपनी सेवी गेम्स ग्रुप की अब ई-स्पोर्ट्स के मार्केट में 40 फीसदी हिस्सेदारी है। पीआईएफ और सहायक कंपनियां गेम कंपनियों की खरीद पर 50 हजार करोड़ रुपए और शेयर्स पर निवेश में 1.16 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी हैं।

रियाद में आयोजन स्थल के बाहर ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप ट्राफी की 30 फुट ऊंची प्रतिकृति।

कुछ आलोचकों ने इन्वेस्टमेंट को मनोरंजन और टूरिज्म से देश की छवि चमकाने और मानव अधिकार उल्लंघनों को छिपाने की कोशिश बताया है। कुछ गेमर्स ने सऊदी अरब की हिस्सेदारी के विरोध में आयोजनों के बहिष्कार का निर्णय लिया है। आलीशान ई-स्पोर्ट्स की मेजबानी के साथ सऊदी राजशाही रियाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर अपना ई-स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट क्विद्दिया बना रही है। किसी समय सऊदी अरब में मूवी थिएटरों और टूरिज्म पर कड़ी रोक थी। 38 साल के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान गेमिंग में दिलचस्पी रखते हैं।

© The New York Times

बिजनेस • 50 एकड़ की जमीन में बन रहे आलीशान बंकर, जहां खाने-पीने के सामान का स्टॉक और अन्य सुविधाओं का इंतजाम

अमेरिका में भविष्य के संकट से निपटने के लिए नए इलाके बनाए जा रहे

एलवजेंडर नजरयान

अमेरिका में नए तरह का बिजनेस आकार ले रहा है। भविष्य के संबंध में अमेरिकियों की बढ़ती चिंता से फायदा उठाने के लिए कुछ कंपनियों ने रिहायशी इलाके बनाना शुरू किया है। इनमें कयामत के भावी दिन या प्रलय से बचने के इंतजाम होंगे। लोगों को यहां मनोरंजन के साधन भी मुहैया कराए जाएंगे। एयरफोर्स के रिटायर्ड कर्नल ड्रू मिलर ने फोर्टिट्यूड रॉन्च खोला है। वाशिंगटन से दो घंटे की दूरी पर पश्चिम वर्जीनिया में 50 एकड़ की जगह में ऐसा एक रॉन्च बना है। इसमें लकड़ियों से बना गेस्ट हाउस, दो बड़ी डोर्मिटरी और कुछ बंकर हैं। इन्हें 100 से अधिक व्यक्तियों के रहने लायक बनाया गया है।

फोर्टिट्यूड रॉन्च के सदस्य को हर साल 80 हजार रुपए देना होंगे। वहां ठहरने के लिए डेढ़ लाख से लेकर 16 लाख रुपए तक लगते हैं। मुसीबत से बचने के लिए कांक्रीट, स्टील और लकड़ी से अंडरग्राउंड कमरे बनाए गए हैं। इनका संबंध दो मुख्य इमारतों से है। भूमिगत जगह में खाने-पीने के पर्याप्त सामान का स्टॉक रहता है। बचाव के लिए राइफल और अन्य हथियार हैं। रेडिएशन डिटेक्टर भी है। पूरे इलाके की सुरक्षा हथियारबंद गार्ड करते हैं। रांच में मांस और अंडों के लिए चिकन, भेड़ और खरगोश पाले गए हैं।

फोर्टिट्यूड रांच के पांच कंपाउंड चल रहे हैं। मिलर अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं। मिलर के अलावा दर्जनों आंत्रप्रेन्योर इस कारोबार में आ चुके हैं। वे सब डूम्स डे (प्रलय का दिन) इकोनॉमी को आगे बढा रहे हैं।

दो करोड़ अमेरिकी बचाव की तैयारियां कर रहे

फेमा के ताजा विश्लेषण के अनुसार लगभग दो करोड़ अमेरिकियों को डूम्स डे की तैयारियां करने वाला प्रेपर्स माना गया है। अमेरिका में हुए पिछले साल के नेशनल हाउसहोल्ड सर्वे में बताया गया कि 57 प्रतिशत अमेरिकियों ने कयामत के दिन से बचाव के लिए तीन या अधिक कदम उठाए हैं।

अमेरिका में कई लोग डूम्स डे के लिए तैयारियां (प्रेपर्स) करने लगे हैं। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते राजनीतिक विभाजन और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के संबंध में चिंता ने प्रलय के दिन को अब काल्पनिक नहीं रहने दिया है। डूम्स डे की तैयारियों का पैकेज देने वाली कंपनियों में शामिल अमेरिकन रिजर्व्स एक साल तक खाने की सप्लाई, इमर्जेंसी रेडियो, लग्जरी बंकर, बचाव के नुस्खे सिखाने वाली क्लास चलाती है। उसकी सदस्यता के लिए 45 लाख रुपए लगते हैं।

सिलिकॉन वैली सहित अन्य इलाकों के कुछ अमीरों ने अपने स्वयं के आलीशान कंपाउंड बनाए तक बना लिए हैं। इसमें अमेरिका के कई रईस भी शामिल हैं। जैसे मार्क जकरबर्ग हवाई में 800 करोड़ रुपए से 1400 एकड़ में फैला एक कंपाउंड बना रहे हैं।

© The New York Times

6 | संपादकीय
जनसत्ता | 15 जुलाई, 2024

कल्पमेधा

ज्ञान इतना घमंडी बन जाए कि वह रो न सके, इतना गंभीर बन जाए कि हंस न सके और इतना आत्मकेंद्रित बन जाए कि अपने सिवा और किसी की चिंता न करे, तो वह ज्ञान, अज्ञान से भी खतरनाक है।
– खलील जिब्रान

महंगाई की मार

भारतीय रिजर्व बैंक की कोशिश है कि खुदरा महंगाई को चार फीसद से नीचे लाकर स्थिर किया जा सके, मगर तमाम कोशिशों के बावजूद इस पर काबू पाना कठिन बना हुआ है। महंगाई के रुख को देखते हुए ही रिजर्व बैंक रेपो दर में बदलाव का कोई फैसला नहीं कर पा रहा है। काफी समय से बैंक दरें स्थिर बनी हुई हैं, जबकि उद्योग समूह चाहता है कि रेपो दर घटाई जाए। जून महीने में खुदरा महंगाई 5.08 फीसद दर्ज की गई, जो कि पिछले चार महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। मई महीने में महंगाई का रुख कुछ नरम दिखा था, हालांकि रिजर्व बैंक को अंदाजा था कि जून और बरसात के महीनों में खुदरा महंगाई बढ़ेगी। रिजर्व बैंक का मानना है कि बरसात के बाद महंगाई उतार पर होगी और तब इसे स्थिर रख पाना संभव होगा। मगर यह दावा कितना सही होगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि पहले भी रिजर्व बैंक कई बार कह चुका है कि वह महंगाई को जल्दी ही काबू में ले आएगा। इस बार भी खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हुआ है।

दैनिक उपभोग की खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी पर अंकुश लगाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार खाद्य महंगाई बढ़ कर 9.36 फीसद पर पहुंच गई है, जो मई महीने में 8.69 फीसद थी। जून महीने में अनाज के दामों में 8.75 फीसद, फलों में 7.15 फीसद, सब्जियों के दामों में 29.32 और दालों की कीमतों में 16.07 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जमीनी स्तर पर आम उपभोक्ता को इससे कहीं अधिक बढ़ी हुई कीमतें चुकानी पड़ रही हैं। बरसात के मौसम में तो कुछ कारण समझ आते हैं कि बाढ़ और बारिश की वजह से माल ढुलाई में बाधा आने की वजह से कई जगहों पर उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाती। कई इलाकों में पानी भर जाने से फलों और सब्जियों की फसल चौपट हो जाने के कारण भी उनकी कीमतों में बढ़ोतरी देखी जाती है। मगर जून के महीने में ऐसी स्थिति नहीं होती। आमतौर पर बाजार में गेहूं और दालों की नई फसल की उपलब्धता रहती है, इसलिए भी इनकी किल्लत का तर्क नहीं रखा जा सकता। रोजी-रोजगार के मोर्चे पर संकट के दौर से गुजर रहे लोगों के सामने अनाज, फल और सब्जियों की बढ़ती कीमतों की कैसी मार पड़ रही होगी, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।

महंगाई पर काबू न पाए जा सकने के पीछे बाजार और विपणन के प्रबंधन में व्यवस्थागत कमजोरियां बड़ा कारण हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली जिन उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन अपने यहां भरपूर होता है, उन्हें सही ढंग से बाजार तक पहुंचाने की व्यावहारिक व्यवस्था अभी तक नहीं बन पाई है। उनकी जगह पर आयातित वस्तुएं बाजार में जगह बना लेती हैं, नहीं तो कोई कारण नहीं कि अक्सर किसानों को अपनी कच्ची फसलें सड़कों पर फेंकने को मजबूर होना पड़ता है। किसान मंडियों में महाजनों की मनमानी की शिकायत करते रहते हैं, पर फसलों की खरीद का व्यवस्थित इंतजाम करने पर ध्यान नहीं दिया जाता। पर्याप्त भंडारगृह और शीतगृहों के न होने से भी फसलें बाजार पहुंचने से पहले बर्बाद हो जाती हैं। जब तक खाद्य वस्तुओं के प्रबंधन पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक केवल बैंक दरों के जरिए महंगाई पर अंकुश लगाना कठिन बना रहेगा।

जनतांत्रिक तकाजा

राजनीति में दो विरोधी दलों का विचारधारा और मुद्दों के स्तर पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े होना स्वाभाविक है। मगर वे भाषा के स्तर पर इस हद तक चले जाएं कि उससे उपजी कड़वाहट सामान्य व्यवहार और बोली तक को बुरी तरह प्रभावित करने लगे, तो यह निश्चित रूप से लोकतांत्रिक माहौल को भी बाधित करेगा। पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश की राजनीति में ऐसा माहौल बन रहा है, जिसमें प्रतिद्वंद्वी दलों में मुद्दों पर उठी बात को उचित संदर्भ में देख-समझ कर एक परिपक्व राय या प्रतिक्रिया देने के बजाय दोनों पक्षों के समर्थक आपस में दुश्मन की तरह पेश आने लगते हैं। ऐसे में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक नई परिपाटी शुरू की है, जिसे कड़वाहट से भरी राजनीतिक दुनिया में एक नई बयार की तरह देखा जा सकता है। गौरतलब है कि अमेठी लोकसभा सीट पर चुनाव हारने के बाद से भाजपा नेता स्मृति ईरानी के लिए सोशल मीडिया पर कुछ अवांछित भाषा का प्रयोग हो रहा था। राहुल गांधी ने इसी संदर्भ में 'एक्स' पर लिखा कि जीवन में जीत और हार होती रहती है... मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि वे स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से बचें।

जाहिर है, मुद्दा आधारित राजनीति के बजाय आरोप-प्रत्यारोपों में घुलती असहिष्णुता जब विषैली भाषा के रूप में सामने आने लगे और संवाद तक की गुंजाइश खत्म होने लगे तो ऐसे में अपने राजनीतिक विरोधी नेताओं के प्रति इस तरह की उदारता वक्त की जरूरत है। मगर राहुल गांधी की इस टिप्पणी को सकारात्मक संदर्भ में लेने के बजाय भाजपा के एक नेता की ओर से जैसी नकारात्मक प्रतिक्रिया आई, उसे सद्भाव के विरुद्ध ही माना जाएगा। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि शीर्ष नेताओं की भाषा, उनके विचार और व्यवहार आम जनता के लिए एक स्तर पर सामाजिक-राजनीतिक प्रशिक्षण का काम करते हैं। नेता जैसा विचार जाहिर करते हैं, उनके समर्थकों का मानस भी वैसा ही बनता है। इस लिहाज से अपने राजनीतिक प्रतिपक्षी नेताओं के लिए शालीन भाषा का प्रयोग करने की राहुल गांधी की सलाह सद्भाव आधारित राजनीति और लोकतांत्रिक माहौल को मजबूत करने की कोशिश है।

भारत के युवाओं का डिगता भरोसा

इस पुरानी बीमारी का इलाज क्यों नहीं हो पाता? क्या इसलिए कि इसकी परीक्षा एजंसी को कोई नियमित सुदृढ़ ढांचा देने के बजाय 'जैसा है, उसे निभाओ' का नियम दे दिया गया।

सुरेश सेठ

हमें गर्व है कि हम एक युवा देश हैं, क्योंकि हमारी आधी से अधिक आबादी छत्तीस वर्ष तक की उम्र के युवाओं की है। उसमें से भी तीन-चौथाई आबादी ऐसे नौजवानों की है, जो सोलह से छब्बीस वर्ष की उम्र के हैं और अपने लिए इस नए भारत में जिंदगी की सार्थकता तलाश रहे हैं। इस नाराप्रेमी और उत्सवधर्मी देश में नौजवान अपने लिए अपनी जमीन और थोड़े से आत्मगौरव की तलाश करते हैं। उन्हें अनुकंपाओं की बरसात से भीगी धरती की जगह धूप से तपती मेहनत मांगती वह धरती चाहिए, जो उनकी योग्यता के अनुसार रोजी-रोजगार दे सके और वे अपनी मेहनत से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए, बिना किसी बैसाखी के जी सकें। मगर ऐसा नहीं है।

नवनिर्माण और नवजागरण के लिए सबसे पहले तो शिक्षा और सम्माजनक पेशे चाहिए। इनके लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होती हैं, जो उनकी योग्यता का उचित मूल्यांकन करके उन्हें सम्मानजनक रोजगार दे सकें। मगर रोजगार की गारंटी इस देश में नहीं है। जो नौजवान जय जवान, जय किसान और जय अनुसंधान के देश को दिए मूलमंत्र का अनुसरण करते हुए अपनी जमीन की तलाश करना चाहते हैं, उन्हें उचित प्रशिक्षण के लिए दाखिला परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। पिछले दशकों में ऐसे शिक्षण संस्थान निजी क्षेत्र में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए हैं। शिक्षा दुकान न बने, उसके दाखिले चोर-दरवाजे न बनें, इसके लिए देश में एक राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी यानी एनटीए की स्थापना की गई। फैसला किया गया कि नौजवान अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रतिष्ठानों की परीक्षाएं देने को न भटकते फिरें। उन्हें एक देश, एक परीक्षा का मूलमंत्र एनटीए द्वारा दे दिया गया। अब चिकित्सक बनना है या उसमें विशिष्टता हासिल करनी है, इंजीनियर या प्राध्यापक बनना है या शोध छात्र, इन सबके लिए परीक्षाएं एनटीए के झंडे तले आयोजित होती हैं। वर्ष में ऐसी लगभग पंद्रह परीक्षाएं एनटीए आयोजित करता है और उनमें अलग-अलग पाठ्यक्रमों के लिए करीब दो करोड़ विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठते हैं।

मगर इस प्रक्रिया में हर वर्ष पर्चाफोड़ होते हैं। इस वर्ष भी यही हुआ। इस पुरानी बीमारी का इलाज क्यों नहीं हो पाता? क्या इसलिए कि इसकी परीक्षा एजंसी को कोई नियमित सुदृढ़ ढांचा देने के बजाय 'जैसा है, उसे निभाओ' का नियम दे दिया गया। एजंसी में पंद्रह शीर्ष लोग तो अलग-अलग प्रतिनियुक्ति से आ गए, पर परीक्षाएं अंततः निजी एजंसियों को ठेके पर दी जाने लगीं। जाहिर है, ऐसे माहौल में पर्चाफोड़ से लेकर अन्य भ्रष्ट तरीकों की कितनी संभावनाएं रहेंगी। इसकी चरम सीमा शायद इस बार हो गई, जब 571 शहरों के 4750 परीक्षा केंद्रों में 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने एमबीबीएस दाखिले के लिए 'नीट' परीक्षा दी। नतीजा निकला तो 67 छात्र प्रथम श्रेणी थे, उन्हें 720 में से 720 अंक मिले। स्पष्ट हुआ कि नंबरों का बंटवारा तर्कहीन तरीक से हुआ है। शोर-शराबा हो गया। जांच में पता चला कि सीमित ढंग से अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया गया। पकड़-धकड़ होने लगी। बिहार से बहुत-सी

खबरें आईं, लेकिन परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले।

इस बार की गड़बड़ी से परीक्षार्थियों का विश्वास परीक्षा लेने वाली एजंसियों पर से डिग गया है। योग्यता का मूल्यांकन अगर इसी तरीके से होना है कि परीक्षा के ढांचे में चोर गलियां निकल आएंगी और

> **इस बार की गड़बड़ी से परीक्षार्थियों का विश्वास परीक्षा लेने वाली एजंसियों पर से डिग गया है। योग्यता का मूल्यांकन अगर इसी तरीके से होना है कि परीक्षा के ढांचे में चोर गलियां निकल आएंगी और अयोग्य छात्र उन्हें धक्का देकर निकल जाएंगे, तो इससे बड़ा अन्याय उन मेहनती छात्रों के लिए क्या हो सकता था, जो वर्षों से घर छोड़कर कोटा जैसी जगहों में परीक्षाओं की तैयारी करने में दिन-रात एक कर रहे थे। परीक्षाएं तो सही मूल्यांकन के विश्वास के आधार पर चलती हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट ने भी 18 जून को नीट मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि 0.001 फीसद भी गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच करो।**

अयोग्य छात्र उन्हें धक्का देकर निकल जाएंगे, तो इससे बड़ा अन्याय उन मेहनती छात्रों के लिए क्या हो सकता था, जो वर्षों से घर छोड़कर कोटा जैसी जगहों में परीक्षाओं की तैयारी करने में दिन-रात एक कर रहे थे। परीक्षाएं तो सही मूल्यांकन के विश्वास के आधार पर चलती हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट ने भी 18 जून को नीट मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि 0.001 फीसद भी गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच करो। सीबीआइ की जांच में यहां-वहां दोषी भी पकड़े जाने लगे। संसद में इस पर बहस की मांग उठी।

नौजवान ही किसी देश का भविष्य होते हैं और जब वही अंधेरे में भटकने लगें, तो देश का भविष्य भला कैसा होगा? सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं पर विचार हुआ कि क्या 'नीट' की दुबारा परीक्षा ली जाए? परीक्षा में भ्रष्ट तरीकों और पर्चाफोड़ की पुष्टि हो गई। मगर जवाबी याचिका भी आ गई कि उन लाखों विद्यार्थियों का क्या दोष, जिन्होंने पूरी मेहनत से इम्तिहान दिए और अब उन्हें फिर उसी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए कहा जा रहा है। जबकि हर पढ़ने वाला जानता है कि उसी उत्साह के साथ बार-बार परीक्षाओं की तैयारी नहीं हो सकती। खैर, मामला सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में है। केंद्र सरकार और एनटीए के हलफनामे भी सुप्रीम कोर्ट में आए हैं कि 'नीट' परीक्षा दुबारा करने की जरूरत नहीं। लाखों मेहनती छात्रों को दुबारा बेवजह परीक्षा की भट्ठी में न झोंका जाए। दोषी तो पकड़े जाएं, लेकिन 'नीट' के यही परीक्षा परिणाम सफल छात्रों के साथ रहेंगे, देशभर की चिकित्सा संस्थाओं में दाखिले के लिए।

इन इम्तिहानों के आधार पर अलग-अलग मेडिकल कालेजों में काउंसिलिंग शुरू होने लगी थी, जो अब जुलाई के अंत तक टल गई और सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसले का इंतजार हो रहा है। फैसला जो भी हो, सवाल इस समस्या के फौरी हल का नहीं है। वह तो हो ही जाएगा। सवाल यह है कि मेहनती युवा पीढ़ी को उनकी मेहनत का उचित मूल्यांकन कैसे होना है, इसका स्थायी हल कैसे निकाला जाए? कुछ बातें बहुत स्पष्ट हैं। योग्य व्यक्तियों का स्थायी ढांचा बनना चाहिए, जो ये परीक्षाएं करवाएं और देशभर में इतने महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए स्थायी परीक्षा मशीनरी बने, जिसकी कार्यशीलता और इमानदारी पर कोई भी व्यक्ति अंगुली न उठा सके। जब तक यह नहीं होगा, तब तक नौजवानों का विश्वास, जो अपने भविष्य के प्रति पहले ही शंकालु है, अपनी परीक्षाओं के प्रति भी अनिश्चय के भंवर में फंसा रहेगा।

हम शिक्षा की खामियों को दूर करने की बात कहते हैं। नए-नए शिक्षा माडल दे रहे हैं, लेकिन इसके एक जरूरी हिस्से यानी छात्र ने जो पढ़ा, उसका सही मूल्यांकन करके उसे रोजी-रोजगार देने के बारे में अभी तक सही फैसले नहीं हो सके। ये फैसले तत्काल होने चाहिए। देश के नव-निर्माण की बात करने वाले पहले देश की युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा के नए ढांचे के निर्माण को तुरंत बनाना शुरू करें। तदर्थ उपायों से काम नहीं चलेगा। शिक्षा आपके अंतस को जगाती है। छात्र की योग्यता का तटस्थ मूल्यांकन करने के लिए शिक्षा विशारदों को तैयार रहना चाहिए। यह ठेका परीक्षा प्रणाली नहीं चलेगी। देश के शिक्षा प्रवीण सिर जोड़कर बैठें और ऐसा वैकल्पिक ढांचा बनाएं, जिसमें देश के युवा छात्र अपने विश्वास और सहज माहौल के साथ यहां अपनी योग्यता को प्रस्तुत कर सकें। इस योग्यता का सही मूल्यांकन होगा, इसका विश्वास उन्हें रहे। तभी देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना उनमें जागेगी।

संतोष का सुख

वंदना सेन

इंसान के मन में अगर संतोष है, तो वह सबसे ज्यादा अमीर है। इसी सिरे से यह भी कहा जा सकता है कि अगर व्यक्ति के मन में शांति है तो वह सबसे ज्यादा सुखी है। इसी तरह अगर किसी के मन में दया है तो वह श्रेष्ठ है और अगर वह स्वस्थ है तो भाग्यशाली है। ये सब बातें केवल कहने या पढ़ने मात्र के लिए नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने का एक ऐसा मंत्र हैं, जो व्यक्ति की निराशा में आशा का संचार करती हैं। इन विचारों की व्याख्या की जाए तो यही कहा जा सकता कि व्यक्ति अगर दूसरे के जैसा होने का प्रयास करेगा, तो उसके जीवन में असंतोष का भाव निर्मित होगा। यह असंतोष का भाव ही अभाव का कारण बनता है, क्योंकि अपने मन में उपजी हर इच्छा को कई सीमाओं की वजह से पूरा करना संभव नहीं हो पाता है। इसके बाद जब अभाव का प्रभाव जीवन पर होता है, तब निराशा आती है। कहते हैं, जितनी बड़ी चादर होती है, उतना ही पैर पसारना चाहिए। यानी व्यक्ति की जितनी आय है, उतने में ही काम चलाना चाहिए। अगर हम अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं, तो जीवन में कई प्रकार की समस्याएं बिना बुलाए ही आ जाएंगी। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबके काम अलग-अलग प्रकार के हैं। मसलन, एक कक्षा के सभी विद्यार्थी आगे चलकर एक जैसे अधिकारी या कर्मचारी नहीं बनते। उनमें से कोई कलेक्टर या जिलाधिकारी बनता है, तो उन्हीं में से कोई चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी भी बनता है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि युवा पढ़ाई के समय परिश्रम करता है, उसे बाद में आराम मिलता है और जो पढ़ाई के समय लापरवाही करता या मौज-मस्ती करता है, उसे बाद में परिश्रम करना पड़ता है।

दुनिया मेरे आगे

> **जीवन में जितने भी तनाव आते हैं, उसके पीछे का मुख्य कारण मन की अशांति ही है। हमारे मन के किसी कोने में सुख और दुख दोनों ही विद्यमान रहते हैं जो अलग-अलग परिस्थितियों के मुताबिक उभरते हैं। किसी वस्तु के प्रति बेलगाम आसक्ति अशांति लाती है। खासतौर पर तब, जब वह अप्राप्य हो।**

माना जाता है कि जीवन में दो अवस्थाएं होती हैं। व्यक्ति के जीवन में अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिनों का भी सामना करना होता है। बुरे दिन यानी अभाव का दौर, जिसमें खुद को बचाने के लिए केवल परिश्रम करना पड़ता है। यों युवा अवस्था परिश्रम करने के दौर के रूप में देखी जाती है। इस दौर में परिश्रम नहीं किया तो भविष्य में उसे परिश्रम करने के लिए तैयार रहना ही होगा। अगर हमारा पेट दस रुपए में भर जाता है तो उसके लिए पचास रुपए व्यय करने की इच्छा करना उचित नहीं। इसलिए कहा जाता है, संतोष जीवन का सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है, वह सबसे बड़ा अमीर है, क्योंकि व्यक्ति की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। यह सही है कि किसी चीज की इच्छा करने से ही वह प्राप्त होती है। मगर क्या उसकी कोई सीमा होगी? आज एक इच्छा पूरी हुई तो कल दूसरी इच्छाएं पैदा हो जाएंगी। एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कुदरत का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। हमारी इच्छाएं उसे अल्प बना देती हैं।

इसी प्रकार अशांत मन दुख को बढ़ावा देता है। जीवन में जितने भी तनाव आते हैं, उसके पीछे का मुख्य कारण मन की अशांति ही है। हमारे मन के किसी कोने में सुख और दुख दोनों ही विद्यमान रहते हैं, जो अलग-अलग परिस्थितियों के मुताबिक उभरते हैं। किसी वस्तु के प्रति बेलगाम आसक्ति अशांति लाती है। खासतौर पर तब, जब वह अप्राप्य हो। वर्तमान में अशांत मन को शांत करने के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहा है, लेकिन उसे शांति नहीं मिल रही। दरअसल, ज्यादातर लोगों के जीवन में भटकाव है। लोगों ने स्थिरता को एक तरह से भुला दिया है या उन्हें भूलना पड़ा है। इससे निवृत्ति के लिए योग का सहारा लेना पड़ रहा है।

अगर मन की शांति चाहिए तो सबसे पहले अपने विचारों को सात्विक करना होगा। ऐसा करने से सकारात्मक दिशा का बोध होगा, जो जीवन को सार्थकता प्रदान करेगा। ऐसा करने के लिए हमको सबसे पहले अपनी दिनचर्या को ठीक करना होगा। यह जीवन को व्यवस्थित करेगा। इस दिनचर्या में स्वकेंद्रित जीवन के मुकाबले सबके हित के बारे में सोचना और अपनी बनाई चारदीवारी से बाहर आना होगा। मन को शांत रखने के लिए संतोष को माध्यम बनाने से लेकर एकांत और विचार का रास्ता अपनाया जा सकता है। कुछ रास्तों से मिली शांति ही सुख का जरिया बनेगी।

अपने मन को निर्मल बनाने के लिए हमें दूसरों के दुख को महसूस करने की जरूरत है। हमारे अंदर दया का भाव होगा तो हम एक गरीब व्यक्ति का हौसला बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। आज व्यक्ति को 'मैं' में घिरे भाव ने बुरी तरह घेर लिया है। यह 'मैं' अहंकार लाता है। हमको व्यक्ति-केंद्रित सोच के मुकाबले सामूहिकता की तरफ कदम बढ़ाना होगा। जब 'हम' का बोध होगा, तो यहीं से हमको समाज भी अपना दिखाई देगा। यह वास्तविकता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम एक बड़े समाज के हिस्सा हैं। हमारी पहचान समाज ही कराता है, लेकिन आज का व्यक्ति समूह में जीना नहीं चाहता। अगर समूह में जिएगा तो उसे हमेशा यह अहसास होगा कि संगठन में शक्ति है। अकेलापन व्यक्ति को भय से ग्रस्त कर दे सकता है। अपने दायरे से बाहर निकल कर जीकर देखने से एक ऐसी सुखद अनुभूति हो सकती है, जिसकी हमें तलाश रहती है।

पानी का प्रबंध

हर साल की तरह मानसून देश में दस्तक देता है और पहली ही बारिश में हर शहर कस्बे की हालत दयनीय हो जाती है। ऐसा नहीं कि बरसात से पहले नाले साफ नहीं किए जाते या फिर दूसरे उपाय अमल में नहीं लाए जाते, लेकिन ये बारिश पता नहीं, हर बार कैसे सारे किए गए इंतजाम को धता बता देती है। इस बार भी पानी को तरस रहा उत्तर भारत और राजधानी दिल्ली पहली ही बारिश में जाम हो गए। बारिश का उचित प्रबंधन किया जाए तो देश में पानी की कमी न रहे। इस प्रबंधन के लिए बस थोड़ी-सी मेहनत और त्याग की जरूरत है। पुराने तालाब, बावड़ी और खेतों की मेढ़ों को साफ करने और मजबूत करने की आवश्यकता भर से भी बहुत-सा पानी और भविष्य बचाया जा सकता है। 'नदी जोड़ो' नामक योजना पर अगर गंभीरता से काम किया जाए तो देश को पानी की कमी नहीं रहेगी। अगर हम अपने पुरखों के ज्ञान का उपयोग करके जीर्ण शीर्ण पड़े तालाबों को ही साफ करके पानी सहेज लें तो न सिर्फ बाढ़ का खतरा घटेगा, बल्कि बारिश का पानी लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सकेगा। इससे भूजल का स्तर भी सुधरेगा, जो आखिर किसानों को लाभ देगा।

– मुनीश कुमार, रेवाड़ी, हरियाणा

अमेरिका की कुर्सी

दो भीषण युद्धों से परेशान दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव बहुत ही अहम है। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल को देखते हुए जाहिर है कि अगर वे राष्ट्रपति चुने गए तो अपनी स्वच्छंदता को बरकरार रखते हुए सिर्फ अमेरिकी हितों की बात करेंगे और कई अंतरराष्ट्रीय संधियों के खराब होने का भय बना रहेगा। नाटो भी अपनी स्थिति को लेकर चिंतित है। बाइडेन की जीत की राह में उनकी उम्र सबसे बड़ी समस्या है। पार्टी को समय रहते किसी युवा जोशीले उम्मीदवार को आगे करना चाहिए, ताकि ट्रंप को सत्ता में आने से रोका जा सके। अगर बाइडेन की पार्टी ऐसा नहीं करती है तो अमेरिकी मतदाता न चाहते हुए भी ट्रंप को ही वोट देंगे। अब वक्त आ गया है कि अधिक समय न बिगाड़ते हुए अमेरिका में नई पीढ़ी के नेता को आगे किया जाए। उसके जीतने के अवसर ज्यादा रहेंगे। अगर हार होती है तो वैसे भी बाइडेन के जीतने की संभावना मात्र पच्चीस फीसद है।

– विभूति बुपक्या, खाचरोद, मप्र

अदालत से उम्मीद

'स्वीकार का साहस' (संपादकीय, 9 जुलाई) पढ़ा। अदालत में राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी यानी एनटीए और सरकार की दलीलों के बीच बच्चों के भविष्य की झूलती वास्तविकता है, जिसे जब तक अदालत में शुचिता की कसौटी पर नहीं कसा जाएगा, न्याय की उम्मीद कम है। सीमित छात्रों के बीच पर्चाफोड़ की बात कह कर सरकार और एनटीए भले ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो लें, पर वास्तविकता अदालत ही जांचेगी। सोशल मीडिया पर पर्चे के फैलने की बात की अगर ईमानदारी से जांच की जाए तो निश्चित रूप से इसके कर्ताधर्ता और उनके आका गिरफ्त में आ जाएंगे। अगर इसमें बड़े पैमाने पर धांधली नहीं होती तो बड़ी संख्या में छात्रों का शत-प्रतिशत नंबर लाना और फिर कृपांक पाने वाले छात्रों की फिर से ली गई परीक्षा में अधिकांश का उपस्थित नहीं रहना संदेह को जन्म देता है। अगर अदालत इस मामले पर निगाह रखेगी, तब छात्रों के साथ न्याय होने की उम्मीद है।

– अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

जिम्मेदारी जरूरी

आधुनिक भारत के डिजिटल इंडिया और कंप्यूटर के युग में रहने के बावजूद कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंडवाद, आडंबर, जादू-टोने और तांत्रिकों के चक्कर में समाज जकड़ा हुआ प्रतीत होता है। हम आस्थावान और निष्ठावान रहें, मगर भीड़तंत्र और भेड़ चाल से तो बचना होगा, अन्यथा ऐसे हादसे होते रहेंगे, लेकिन हादसों से आखिर हम क्या सबक ले रहे हैं। सरकारी तंत्र, सत्संग और धार्मिक आयोजन करने वालों के बीच समन्वय और संवाद में भारी कमी दिखाई देती है। कड़वा सच है कि देश के नामी-गिरामी लोग इन बाबाओं के दरबार में जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। राजनेता भी आसानी से देखे जाते हैं और चुनाव के दौरान यह संख्या बढ़ जाती हैं। इससे जनता भी भ्रमित होती है और उसकी आस्था भी इन बाबाओं के प्रति बढ़ जाती है।

– वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

जो बाइडेन

क्षमता पर सवाल

जो बाइडेन की क्षमता पर सवालों के साथ उन पर हमले तेज हो रहे हैं। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी को कठोर निर्णय लेना होगा कि जो बाइडेन उसके राष्ट्रपति उम्मीदवार बने रहें या उनका विकल्प पेश किया जाए। दोनों स्थितियां कठिन हैं और उनके सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष हैं। बाइडेन की आयु व उनकी क्षमताओं के प्रदर्शन से पार्टी को 'प्लान बी' पर विचार करना होगा। लेकिन डेमोक्रेटों के लिए समय तेजी से बीतता जा रहा है और यही स्थिति विकल्पों की है। हालांकि, इस प्रकरण की शुरुआत काफी पहले हो गई थी, पर 'राष्ट्रपति बहस' एक प्रकार से 'ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका' सिद्ध हुई जिसमें बाइडेन का प्रदर्शन बहुत खराब था। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद बाइडेन के पक्ष में मजबूत तर्क हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण विधायी उपलब्धियों का लंबा समय देखा है जिनमें व्यापक ढांचागत संरचना विधेयक, महत्वाकांक्षी जलवायु परिवर्तन पहलें तथा जीवन्त कोविड-19 टीकाकरण अभियान शामिल हैं। बाइडेन प्रशासन जटिल अंतरराष्ट्रीय संबंधों से निपटने में सफल हुआ है। उसने अंतरराष्ट्रीय खतरों से निपटने में सफलता पाई है तथा खासकर चीन और रूस के खिलाफ गठबंधनों को मजबूत किया है। उनके मध्यमार्गी दृष्टिकोण का लक्ष्य अत्यधिक विभाजित राष्ट्र को एकजुट करना था। इसके लिए उन्होंने प्रगतिशील व मध्यमार्गी डेमोक्रेटों तथा निर्दलीयों व रिपब्लिकनों से भी अपील की। लेकिन बाइडेन की आयु और उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिन्ता बनी हुई है। 81 साल की आयु में वे अमेरिकी इतिहास के सबसे वयोवृद्ध राष्ट्रपति हैं। उनकी क्षमताओं तथा मानसिक सतर्कता पर राजनीतिक विरोधी तथा मीडिया अनुमान लगाते रहे हैं। जनमत सर्वेक्षणों से स्पष्ट है कि मतदाताओं का बड़ा हिस्सा उनकी क्षमताओं से असहज तथा चार वर्ष का एक और कार्यकाल देने पर दुविधाग्रस्त है। इसके साथ ही कुछ मुद्दों से निपटने के उनके तरीकों पर भी सवाल उठ रहे हैं जिनमें अफगानिस्तान से वापसी तथा वर्तमान आर्थिक चुनौतियां शामिल हैं। इसके लिए उनको दोनों पक्षों के राजनेताओं की आलोचना झेलनी पड़ी है।

इन विवादों से अफवाहों को बल मिला है कि क्या डेमोक्रेटों को 2024 में विजय दिलाने के लिए बाइडेन सर्वोत्तम उम्मीदवार हैं। लेकिन चुनाव को अब केवल चार महीने बचे हैं और डेमोक्रेटों द्वारा उनका विकल्प तलाशना कठिन है। ऐसे में 25वां संशोधन लागू करना भी आत्यन्तिक व असंभव लगता है जो सेवा करने में अक्षम राष्ट्रपति को हटाने का प्राविधान करता है। इसके संभावित राजनीतिक नतीजों के साथ ही 'अक्षमता' के स्पष्ट व अविवादित प्रमाण होने चाहिए। इस प्रकार यह रास्ता जोखिम भरा है। यदि डेमोक्रेट विकल्प तलाशने का निर्णय करें तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में अनेक हाई-प्रोफाइल नेता सामने आएंगे। वर्तमान उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस सर्वाधिक संभावित पसंद हो सकती हैं। पहली महिला, पहली अश्वेत व पहली दक्षिण एशियाई उप-राष्ट्रपति के रूप में उनका प्रस्ताव बहुत मजबूत है, पर उनके नेतृत्व तथा नीतिगत प्रभावशीलता पर गहरे सवाल हैं। परिवहन सचिव व साउथ बेंड, इंडियाना के पूर्व मेयर पीट बुटीगेग एक और उम्मीदवार हो सकते हैं। वे युवा, स्पष्ट वक्ता तथा नीतिगत समझदारी वाले व्यक्ति हैं। इसके साथ ही प्रगतिशील नीतियों के पैरोकार व कैलीफोर्निया के गवर्नर गाविन न्यूसन ने भी राजनीतिक चुनौतियों का दृढ़ता से सामना किया है। इस प्रकार वर्तमान समय में डेमोक्रेट भारी दुविधा के शिकार हैं। अंततः निर्णय बाइडेन की प्रभावी नेतृत्व क्षमता तथा पुनः चुनाव जीतने की संभावना पर होगा।

तालिबानों से महिलाओं का संघर्ष

तालिबान अधिकारियों के इनकार के बावजूद अफगान महिलायें अपने प्रति गंभीर व अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ उठ कर खड़ी हो रही हैं। विडंबना है कि विश्व जनमत इस उत्पीड़न पर खामोश है।

हिरण्यमय कार्लेकर
(लेखक, द पायनियर के सलाहकार संपादक हैं)

तालिबान अधिकारियों के इनकार के बावजूद अफगान महिलायें अपने प्रति गंभीर व अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ उठ कर खड़ी हो रही हैं। इसके अनेक प्रमाण भी सामने आ रहे हैं। 'द गार्जियन' में जाहरा जोया, क्रिस मैक्ग्रील, खुदाबाद पोलादी, एन्नी केली व टाम लेविट की रिपोर्ट 6 जुलाई, 2024 को प्रकाशित हुई। इसका शीर्षक 'वीडियो एपियर्स टु शो गैंग-रेप आफ अफगान वीमेन इन तालिबानी जेल' है, यानी इस वीडियो में संभवतः तालिबानी जेल में अफगान महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। इससे अफगानिस्तान में जघन्य स्थिति का पता चलता है। रिपोर्ट के अनुसार, यह वीडियो 'द गार्जियन' तथा अफगानिस्तान में महिला संबंधी मुद्दों पर खबरें देने वाले आनलाइन मीडिया 'रुखसाना मीडिया' द्वारा यह वीडियो देखा गया।

इसमें एक युवा महिला और मानवाधिकार कार्यकर्ता से तालिबान जेल में सशस्त्र लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार व अत्याचार दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि महिला से अपने कपड़े उतारने को कहा गया और उसके बाद दो लोगों द्वारा उससे कई बार बलात्कार किया गया। उसे नंगी खड़े देखा गया, उसकी आवाज लड़खड़ा रही है और हमलों के दौरान उसे पहचाना जा सकता है। 'द गार्जियन' और 'रुखसाना मीडिया' में महिला को यह कहते दिखाया गया है कि उसे तालिबान के खिलाफ सार्वजनिक रूप से विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया तथा तालिबानों की जेल में उससे कई बार सामूहिक बलात्कार किया गया। यह वीडियो उसे अफगानिस्तान से भाग जाने के बाद भेजा गया। उसे धमकी दी गई कि यदि उसने सार्वजनिक रूप से 'इस्लामी अमीरात' के खिलाफ कुछ बोला तो यह वीडियो उसके परिवार को दिखाया जाएगा तथा इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा। रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न, पिटाई तथा अत्याचारों के अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। इनमें न केवल तालिबानों द्वारा महिला-अधिकारों के दमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों को बिजली के झटके देने, बल्कि युवा महिलाओं और किशोरियों द्वारा हिजाब नियमों के उल्लंघन की बात भी कही गई है। 'द गार्जियन' की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामी अमीरात अफगानिस्तान के सूचना एवं संस्कृति उप-मंत्री तथा मुख्य प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने गिरफ्तार महिलाओं के व्यापक यौन उत्पीड़न के आरोपों का खंडन किया है। हालांकि, वे इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते थे, पर महिलाओं के आरोपों पर संदेह नहीं किया जा सकता है। अफगानिस्तान जैसे देशों में यौन हिंसा की शिकार महिलाओं के प्रति व्याप्त पूर्वाग्रहों को देखते हुए ये सही लगते हैं।

ऐसे में महिला और उसके रिश्तेदारों के लिए यह कहना बड़ी हिम्मत और प्रतिबद्धता का काम है कि हिरासत में उसके साथ बलात्कार या यौन उत्पीड़न हुआ है। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने भी गिरफ्तारियों व हिरासतों पर टिप्पणी की है। अजीत कुमार सिंह ने 11 मार्च, 2024 को 'साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल' पर लिखा था कि अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन-यूएनएएमए ने 'इस्लामी ड्रेस कोड' के कथित उल्लंघन पर महिलाओं और लड़कियों की गिरफ्तारी और हिरासत पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की है।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष प्रतिनिधि तथा यूएनएएमए की प्रमुख रोज़ा ओटुनबायेवा के हवाले से लिखा है कि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई तथा शारीरिक हिंसा 'खासकर अफगान महिलाओं के लिए अत्यधिक अपमानजनक व खतरनाक है।' उन्होंने कहा है कि हिरासत से 'अफगान महिलाओं पर बहुत भारी दाग लग जाता है जिससे उन पर खतरा और बढ़ जाता है।' महिलाओं के खिलाफ तालिबान के हमले 1996-2001 के बीच चले उनके पहले शासनकाल की याद दिलाते हैं जो उनके वर्तमान दूसरे शासनकाल में भी जारी हैं। बलात्कार और यौन उत्पीड़न ऐसे अत्याचारों का हिस्सा हैं।

इसकी शुरुआत सितंबर, 2021 में उस समय हुई जब तालिबान ने काबुल में महिला मामलों के मंत्रालय का बोर्ड हटा दिया और उसके स्थान पर 'मिनिस्ट्री फार द प्रमोशन आफ वर्चू एंड प्रिवेंशन आफ वाइस' का बोर्ड लगा दिया। अफगानिस्तान की सत्ता में पहली बार आए तालिबानों के शासनकाल में मनमाने व कठोर उत्पीड़न के लिए उनको काफी बदनामी झेलनी पड़ी थी। सरकार की आदिमकालीन सोच वाली घोषणाओं के चलते उन्होंने महिलाओं के प्रति अत्यधिक कठोरता बरती थी। वर्तमान समय में भी महिलाओं के खिलाफ अनेक कठोर कदम उठाए गए हैं। महिलाओं को एक पुरुष संरक्षक के बिना 70 किलोमीटर से अधिक यात्रा पर प्रतिबंध है जो उनका पति या 'महरम' हो। 'महरम' का अर्थ नजदीकी रक्त संबंधी है, जैसे पिता, बेटा, भाई, बाबा, परबाबा, ऐसा भतीजा जिससे विवाह प्रतिबंधित हो और जिसकी उपस्थिति में उसे हिजाब पहनने की जरूरत न हो। महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर 'समुचित' हिजाब तथा ऐसे ढीलेढाले काले कपड़े पहनने चाहिए जिनसे उनका शरीर और चेहरे पूरी तरह ढक जांए। इसके लिए उनके पुरुष रिश्तेदारों को जिम्मेदार ठहराया गया है जिनको अपना कर्तव्य पालन न करने पर दंड भुगतना पड़ता है। महिलाओं को प्राथमिक स्तर के बाद शिक्षा तथा हर प्रकार के रोजगार से वंचित किया गया है। सबसे बुरी बात है कि 23 मार्च, 2024 को अफगानिस्तान के राज्य टेलीविजन पर प्रसारित एक मौखिक संदेश में तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबातुल्ला अखुंदजादा ने कहा था कि 'हम महिलाओं को कोड़े लगाएंगे और हम व्याभिचार के लिए उनको पत्थर मार-मार कर मार डालेंगे।' तालिबान ने इस घोषणा के पहले ही महिलाओं को कोड़े लगाना शुरू कर दिया था। उनको सेलफोन प्रयोग करने तथा अपने प्रेमियों या रिश्तेदारों से बात करने के 'अपराध' में कम से कम 30 कोड़े लगाने की सजा दी जाती थी। तालिबानों की आदिमकालीन सोच को देखते हुए यह आश्चर्यजनक नहीं था। 1996 से 2001 में सत्ता में पहली बार आने के समय उन्होंने यही सब किया था।

ऐसे में यह देख कर अत्यधिक आश्चर्य होता है कि बाकी दुनिया अफगान महिलाओं के साथ हो रहे इस घोर उत्पीड़न व मानवाधिकार उल्लंघन पर एकदम चुप है। दुनिया के अनेक जिम्मेदार देश और उनके राजनेता तालिबानों द्वारा अफगान महिलाओं पर ढाए जाने वाले ऐसे अत्याचारों के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे हैं। इस सबंध में सारी दुनिया में स्वयं को लोकतंत्र के रक्षक की तरह पेश करने वाले पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों की चुप्पी और अधिक चिन्ताजनक हैं। लोकतांत्रिक देश तालिबानों के खिलाफ इस मामले में किसी प्रभावी कार्रवाई के मामले पर भी पूरी तरह खामोश हैं। विडंबना है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा उससे जुड़ी संस्थायें भी अफगान महिलाओं और लड़कियों के उत्पीड़न पर सक्रिय नहीं दिख रही हैं, जबकि इस बारे में 'द गार्जियन' तथा 'रुखसाना मीडिया' की स्पष्ट वीडियो आधारित प्रमाणित रिपोर्ट के अलावा अन्य अनेकानेक प्रमाण सारी दुनिया के समक्ष मौजूद हैं।

हाल ही में दोहा और कतर में 25 देशों के राजदूतों का वैश्विक सम्मेलन हुआ। इसमें अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि शामिल थे। इस सम्मेलन में अनेक मुद्दों पर तालिबान के साथ संपर्क को प्रोत्साहित करने की बात कही गई। यह अपने किस्म का तीसरा वैश्विक सम्मेलन था। हालांकि, तालिबान ने पहले दो सम्मेलनों में भाग नहीं लिया था, पर इस सम्मेलन में भी वह इस शर्त पर भाग लेने को तैयार हुआ था कि आयोजकों की ओर से कोई महिला सम्मेलन में भाग नहीं लेगी। संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा तालिबानों की यह शर्त मान लेने की मानवाधिकार संगठनों से व्यापक रूप से निन्दा की थी। उनका यह आरोप था कि संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य देशों द्वारा तालिबानों की यह शर्त मान लेने का अर्थ उनको महिला-अधिकारों को और कुचलने का अवसर देना होगा।

मानवाधिकार संगठनों की यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा लगता है कि मानवाधिकारों और महिला अधिकारों की बड़ी-बड़ी बातें करने वालों को अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा महिलाओं व लड़कियों पर किए जा रहे अमानवीय अत्याचारों और दमन की जरा भी चिन्ता नहीं है।

मोदी-पुतिन मुलाकात से रिश्तों में आई नई जान

पारुल चंद्रा
(लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

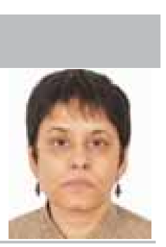

जब यह धारणा बढ़ रही थी कि भारत और रूस के बीच संबंधों में गति कम हो रही है, यहां तक कि ठहराव आ रहा है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर-स्तरीय बैठक द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान करने में मदद करेगी।

भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच दो वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद आयोजित 22वें शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी की पूरी क्षमता को अनलॉक करने का संकल्प लिया। शिखर सम्मेलन के परिणामों ने मॉस्को के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए नई दिल्ली के इरादे को व्यक्त किया, भले ही रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने और उसके बाद उसके देश पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद पुतिन को पश्चिमी देशों द्वारा व्यापक रूप से बदनाम किया गया हो। पुतिन के रूस-यूक्रेन युद्ध में व्यस्त होने के कारण, जो अब अपने तीसरे वर्ष में है, शिखर-स्तरीय बैठकें पीछे छूट गई थीं। पिछली शिखर वार्ता दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में हुई थी। शिखर वार्ता में दोनों पक्षों की ओर से न केवल 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' को पुनर्जीवित करने की उत्सुकता दिखाई गई, बल्कि आर्थिक सहयोग को भी संबंधों का आधार बनाया गया। यह एक अलग संयुक्त वक्तव्य में परिलक्षित हुआ, जिसमें आर्थिक सहयोग के लिए नौ प्रमुख क्षेत्रों की रूपरेखा बताई गई, जिसमें 2030 के लिए 100 बिलियन डॉलर का नया द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया गया। मोदी-पुतिन शिखर वार्ता में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाते हुए देखकर निराशा और शांति प्रयासों के लिए विनाशकारी झटका व्यक्त किया, लेकिन इससे नई दिल्ली के कीव के साथ घनिष्ठ संबंधों को नुकसान पहुंचने की संभावना नहीं है। भारत ने भले ही आक्रमण की निंदा न की हो, लेकिन मोदी ने पुतिन से कहा कि युद्ध के मैदान में शांति नहीं है जबकि उन्होंने बातचीत की आवश्यकता पर भारत की स्थिति को दोहराया। वाशिंगटन ने मोदी-पुतिन की मुलाकात पर अपनी नाराजगी भी जताई है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इससे मॉस्को के साथ उसके संबंधों पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि भारत की रणनीतिक ज़रूरतें इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। बेशक, इनमें से एक रूस-चीन के बीच बढ़ती नज़दीकियां हैं। रूस के साथ नज़दीकी संबंधों पर ज़ोर देने से मॉस्को की वाशिंगटन के प्रति नई दिल्ली के झुकाव को लेकर चिंताएं भी दूर होंगी। भारत अब तक दो भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच संतुलन बनाने में कामयाब रहा है और उसे ऐसा करना जारी रखना चाहिए। भारत रूस को समय-परीक्षित भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखता है। पश्चिमी दुनिया प्रतिबंधों से प्रभावित रूस को यूक्रेन युद्ध के मामले में अलग-थलग रखना चाहेगी, लेकिन भारत का व्यापक और गहरे आर्थिक संबंधों के लिए प्रयास उसकी अपनी रणनीतिक ज़रूरतों को दर्शाता है। प्रतिबंधों के बावजूद भारत की रूसी तेल खरीद न सिर्फ़ जारी रहेगी बल्कि इसमें और वृद्धि होने की उम्मीद है। रूस से कच्चे तेल का आयात 2021 में 2.5 मिलियन टन से बढ़कर 2023 में 90 मिलियन टन हो गया है, भारत को यह स्पष्ट है कि यह उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों पक्षों द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में निवेश भी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। रूस से उर्वरक आयात भी भारत के कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। रूसी तेल आयात ने द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़ों को 65.70 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने में मदद की है। लेकिन जबकि भारतीय आयात 61.44 बिलियन डॉलर का था, इसके निर्यात का हिस्सा मात्र 4.26 बिलियन डॉलर था। रियायती दरों पर रूसी तेल आयात करने में खुश होने के बावजूद, नई दिल्ली को रूस के साथ व्यापार की टोकरी को चौड़ा करके इस व्यापार असंतुलन को दूर करने की आवश्यकता होगी। भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक रसायन, लोहा और इस्पात और विद्युत मशीनरी शामिल हैं।

दोनों पक्षों ने गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं को खत्म करने और यूरेशियन आर्थिक संघ -भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की संभावना पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की, जो द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के इरादे की गंभीरता को दर्शाता है। भारत और ईएईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए पूर्ण वार्ता शुरू करने की प्रेरणा से भी व्यापार संबंधों को बढ़ावा मिलना चाहिए।

कनेक्टिविटी भी दोनों पक्षों के लिए प्राथमिकता बनी हुई है। इसका मतलब होगा भारतीय सामानों के लिए यूरेशियाई बाजारों तक पहुंच। हालांकि, प्रस्तावित (अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन) गलियारा अभी भी वास्तविकता बनने से बहुत दूर है। जबकि चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा स्थापित करने के लिए दोनों पक्षों के बीच फिर से रुचि है, जिसे पहली बार 2019 में पेश किया गया था, यह भी देखा जाना बाकी है कि यह फलीभूत होगा या नहीं। शिखर सम्मेलन ने निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र में मजबूत सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया, जो भारत के सुरक्षा प्रतिमान का एक महत्वपूर्ण तत्व है।

रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, भले ही नई दिल्ली अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अमेरिका, फ्रांस और इज़राइल जैसे अन्य देशों की ओर रुख करके विविधता लाने के निरंतर प्रयास कर रहा हो। भारत निस्संदेह यूक्रेन युद्ध के कारण रूसी सैन्य हार्डवेयर और पुर्जों की आपूर्ति में देरी पर अपनी चिंताओं को दूर करने की कोशिश करेगा।

मोदी-पुतिन शिखर सम्मेलन ने भले ही पश्चिम को नाराज़ कर दिया हो, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि नई दिल्ली तब तक अपना काम जारी रखेगी जब तक कि यह उसकी रणनीतिक प्राथमिकताओं को पूरा करता रहे।

आप की बात

बिगड़ैल नाबालिग

देश में रसूखदारों के बिगड़ैल शहजादों के ही अधिकतर हिट एन रन मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे बिगड़ैल नाबालिग कहीं फुटपाथ पर सोये लोगों पर नशे में गाड़ी चढ़ा देते हैं तो कहीं अन्य दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। ऐसी दर्दनाक घटनाएं अक्सर मीडिया व सोशल मीडिया में आने लगी हैं। दूसरी ओर लव जिहाद के गंभीर व दर्दनाक किस्से भी मीडिया की सुर्खी बन रहे हैं। कभी किसी लड़की के टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए जाते हैं तो कहीं बोरियों में भरकर नदी में बहा दिए जाते हैं। समाज और सरकार को ऐसे मामले रोकने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। देश के कानूनविदों व पुलिस को मिलकर नाबालिगों द्वारा किए अपराधों को रोकने पर विचार करना चाहिए। यह सच है कि नाबालिगों व पहली बार अपराध करने वालों को वयस्कों व आदतन अपराधियों जितनी सजा नहीं दी जा सकती है। लेकिन बचपन से ही बच्चों में समाज के प्रति जिम्मेदारी तथा अपराध और दंड से भय करना सिखाया जाना चाहिए। गंभीर अपराधों में नाबालिग को वयस्क की तरह सजा देने का अधिकार भी यथासंभव न्यायालय के विवेकाधिकार तथा स्थितियों के विश्लेषण पर छोड़ने से नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों पर लगाम लगाई जा सकती है। यह कदम जरूरी हो गया है।

– **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

शूटिंग में दुर्घटनायें

फिल्म व टेलीविजन के इतिहास में शूटिंग के दौरान दुर्घटनाओं के कारण मौतें होती रही हैं। 1980 से 1990 तक स्टंट के दौरान 37 मौतें हुईं। इनमें से 24 मौतें हेलीकॉप्टर उपयोग संबंधी थीं। भारतीय फिल्म उद्योग में भी ऐसी दुर्घटनाएं होतीं रहतीं हैं। इंडियन 2 की शूटिंग में एक विशाल क्रेन गिरने से तीन तकनीशियनों की मौत हो गई, जबकि अभिनेता कमल हासन, काजल अग्रवाल और निर्देशक शनमुगम शंकर बच गए। 2004 में खाकी के सेट पर ऐश्वर्या राय बच्चन के पैर में जीप की टक्कर से फ्रैक्चर हो गया था। 1980 के दशक में कुली के फिल्मांकन के दौरान अमिताभ बच्चन बुरी तरह घायल हो गए थे। इसी तरह की एक दुर्घटना में 2021 में न्यू मेक्सिको में फिल्म शूटिंग के दौरान हेलिना हैचिन्स की गोली लगने से मौत हो गयी थी। गोली अभिनेता एलेक बाल्डविन के हाथों से चली थी। जबकि शूटिंग के दौरान नियम ये है कि बन्दूक असली होती है मगर उसके अंदर गोली नकली होनी चाहिए। अब सबूतों के अभाव में बाल्डविन को बरी कर दिया गया है। फिल्मों व टेलीवीजन शूटिंगों में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए समुचित उपाय किए जाते हैं और खतरनाक मामलों में प्रशिक्षित लोगों का प्रयोग होता है।

– **जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

प्रशासन की जिम्मेदारी

प्रशिक्षु आईएएस को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे लोगो को सर्वश्रेष्ठ सुशासन देने का निर्देश दिया। मोदी ने उनसे अपने कार्य के प्रति सक्रियता दिखाते हुए कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुचाने का अनुरोध किया। देश में जनता द्वारा चुनी सरकार का कर्तव्य है कि वह नीतियां बनाने के साथ ही उनके क्रियान्वयन में अधिकारियों और प्रशासनतन्त्र की जवाबदेही तय करे। अधिकारियों को भी जमीनी स्तर पर विकास कार्यों का निरीक्षण करने के साथ ही आम जनता की समस्याओं को समझना चाहिए। विडंबना है कि केन्द्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों और निर्देशों के बावजूद केन्द्र व राज्य की अनेक जन-कल्याणकारी योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तथा उनमें भ्रष्टाचार की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। गांवों में शौचालय निर्माण व पीएम आवास बनाने की अगली किश्तों तथा मनरेगा की बकाया धनराशि न मिलने की शिकायतें भी आ रहीं हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी जनता की शिकायतें दूर करना भी है। जनता तथा सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं के बीच नियमित संवाद से भी प्रशासन की जिम्मेदारी व जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती है।

कुलदीप मोहन त्रिवेदी, उन्नाव

स्वागत योग्य फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को भी अब गुजारा भत्ता उनके पति से सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत दिलाने का फैसला दिया है। यह निर्णय निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस को याद रखते हुए ये निर्णय दिया है जिसमें इसका प्रावधान था। लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में बनाए कानून से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला निष्प्रभावी कर दिया था। अब 1986 का वह कानून धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगने के अधिकार पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना भी स्वागत योग्य है कि गुजारा भत्ता कोई खैरात नहीं है बल्कि तलाकशुदा महिला का मौलिक अधिकार है। विडंबना है कि अनेक कट्टरपंथी मौलाना इसे शरीयत में दखलंदाजी कह रहे हैं, जबकि दुनिया के अनेक मुस्लिम-बहुल देशों में महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त है। कई मुस्लिम देशों में पुरुषों को बिना अदालती फैसले तलाक देने पर प्रतिबंध है तथा वे एक से अधिक महिलाओं से विवाह नहीं कर सकते हैं। भारतीय मुसलमानों को भी अब दकियानूसी सोच छोड़ कर आगे बढ़ना चाहिए।

–**भगवानदास छारिया,** इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 128

विकास का सूचकांक

सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने अपने ताजा सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) भारत सूचकांक में एक उम्मीद भरी तस्वीर पेश की है। सूचकांक में भारत को 100 में से समग्र रूप से 71 अंक मिले हैं जबकि 2021 में उसे 66 तथा आधार वर्ष 2018 में 57 अंक प्राप्त हुए थे। यह रिपोर्ट 113 अलग-अलग संकेतक पर आधारित होती है जो संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के तहत निर्धारित हैं और ये दिखाते हैं कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के एसडीजी में सुधार हुआ है तथा उनके अंक 57 से 79 के बीच हैं। इन्हें 2018 में 42 से 69 के बीच अंक मिले थे। व्यापक राष्ट्रीय रैंकिंग की बात करें तो 32 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों ने 65 से 95 तक अंक हासिल किए और इनमें 10 राज्य पहली बार शामिल हुए। अगर किसी राज्य को 49 से कम अंक नहीं मिले हैं तो अधिकतम अंक यानी 100 भी किसी राज्य को नहीं मिले। 16 में से 12 लक्ष्यों पर उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। सबसे चिंताजनक मुद्दा महिला-पुरुष समानता का है जहां 2019-20 से अब तक हालात में शायद ही कोई सुधार हुआ है। भारत एसडीजी में अभी भी मजबूती राज्यों की श्रेणी में है।

रिपोर्ट में बेहतर समग्र अंकों को सरकार की कल्याण योजनाओं तथा पहलों से जोड़ा गया है। अगर ऐसा है तो आंकड़ों को अलग-अलग करके देखने पर पता चलता है कि यह सहायता सभी को बांटी गई है। भूख के मामलों को समाप्त करना इसका उदाहरण है। हालांकि कुल अंक 48 से सुधरकर 52 हुए हैं लेकिन 'आकांक्षी' राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर बिहार और उत्तर पूर्व के कुछ इलाकों तक बंटे हुए हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करें तो मध्य, पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत के कुछ हिस्से अभी 'आकांक्षी' स्तर पर हैं। इन सभी बातों से संकेत मिलता है कि भोजन अथवा स्कूलों तथा शैक्षणिक संस्थाओं तक पहुंच का अर्थ आवश्यक रूप से संतोषजनक नतीजों वाला नहीं है। इन दोनों मानकों का देश की भविष्य की आबादी की गुणवत्ता पर सीधा असर होना है। उद्योगों में नवाचार और अधोसंरचना क्षेत्र पर भी यही बात लागू होती है।

कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो वास्तविक हकीकत से मेल खाते नहीं नजर आते हैं। टिकाऊ शहरों और समुदायों के मामले में भारत को 2018 के 29 की तुलना में इस बार 83 अंक मिले हैं। देश के शहरों में अधिकांश लोग जिन खराब परिस्थितियों में रह रहे हैं उन्हें देखते हुए इसे हजम करना मुश्किल है। यह मानक इस बात पर निर्भर करता है कि जैविक-मेडिकल कचरे तथा अन्य जैविक कचरों का निपटान किस प्रकार किया जाता है। यह शहरों की बेहतरी का केवल एक पहलू होना चाहिए। इसी प्रकार किफायती और स्वच्छ ऊर्जा के मामले में भारी उछाल दर्ज की गई। देश के अधिकांश राज्यों को 100 फीसदी अंक दिए गए हैं जबकि भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भी आगे है। साथ ही हमारे बिजली उत्पादन में कोयले की काफी अहम भूमिका है।

नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट निस्संदेह सहकारी संघवाद की दिशा में एक अनमोल कवायद है और बहुआयामी गरीबी में कमी आने के प्रमाण सुखद हैं। परंतु यह कवायद अनिवार्य तौर पर अंदर की ओर झांकने वाली है और देश के भीतर की सामाजिक और विकास संबंधी प्रगति की तुलनात्मक तस्वीर पेश करती है। वैश्विक स्तर से, यहां तक कि एशियाई देशों से भी तुलना करें तो भारत लगभग सभी मानकों पर पीछे नजर आता है। संयुक्त राष्ट्र की टिकाऊ विकास संबंधी ताजा रिपोर्ट में भारत को 193 देशों में 109वां स्थान दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल 30 फीसदी एसडीजी लक्ष्य ही हासिल हुए हैं या पटरी पर हैं, 40 फीसदी में सीमित प्रगति हुई है जबकि शेष 30 फीसदी के मामले में हालात बेहद खराब हैं। इन हालात को बदलने के लिए उन मानकों में बदलाव लाना होगा जिनके आधार पर राज्यों का आकलन किया जाता है। उन्हें हकीकत के और करीब लाना होगा।

अजय मोहंती

मोदी के तीसरे कार्यकाल की अहम चुनौतियां

मोदी सरकार को आने वाले दिनों में बड़ी चुनौतियों का सामना बिना उस संपूर्णसत्ता के करना होगा जो उसके पास हुआ करती थी। इस दौरान उसका सामना एक के बाद एक चुनावी चुनौतियों से भी होगा।

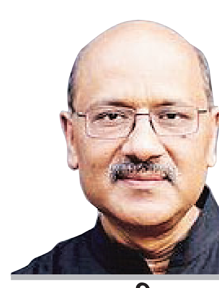

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल आरंभ हो चुका है। उनका यह कार्यकाल पिछले दो कार्यकाल से काफी अलग है और यह बात वह किसी और से बेहतर जानते हैं।

उनका राजनीतिक प्रशिक्षण और अनुभव ऐसा नहीं रहा है कि वे मिलीजुली सरकार चला सकें। वास्तविक मुद्दा बहुमत का न होना नहीं है। उनके पास 240 सीट हैं जो काफी हैं, कोई साझेदार भी ऐसा नहीं है जो उनकी सरकार को गिरा सके। शायद यही वजह है कि उन्होंने इस कार्यकाल की शुरुआत भी पिछले दो की तरह ही की। उनके लिए यह दिखाना महत्त्वपूर्ण है।

मोदी के तीसरे कार्यकाल में अंतर आंकड़ों का नहीं बल्कि उस नए माहौल का है जिसका अनुमान मैंने चुनाव नतीजों के दिन लगाया था। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम विभिन्न खेलों के रूपकों को मिलाकर इस्तेमाल करेंगे। पहले वे खेल जिनमें सीधी टक्कर और शारीरिक संपर्क होता है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके साझेदारों को बॉक्सिंग मैच में अंकों के आधार पर मिली जीत के समान विजय हासिल हुई। जीत का अंतर बहुत कम नहीं था लेकिन यह पिछले दो चुनावों की तरह नॉकआउट और एकतरफा भी नहीं थी। उसके प्रतिद्वंद्वी भी कुछ पंच लगाने में कामयाब रहे और वे अभी भी रिंग में लड़ने के लिए मौजूद हैं।

वे यह भी मानते हैं कि वर्तमान विजेता को हराया जा सकता है। यही बदलाव है। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी और 'इंडिया" गठबंधन के अन्य नेता किस प्रकार राजनीतिक मुद्दों को उठा रहे हैं। वर्ष 2014 और 2019 के चुनावों के बाद वे अपने जख्म सहलाने लगे थे या किसी आध्यात्मिक चिंतन में लिप्त हो गए थे। अब हम कहीं अधिक लोकप्रिय खेल क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं।

वर्ष 2024 के चुनाव नतीजों की तुलना एक ऐसे क्वालिफायर से कीजिए जिसकी बदौलत विपक्ष को टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में विजेता को चुनौती देने का मौका मिला हो। टेस्ट क्रिकेट में एक-एक सत्र के हिसाब से खेला जाता है। इस टेस्ट में पहला सत्र होगा इस वर्ष के अंत में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव। इनमें से हर जगह प्रतिद्वंद्वी मजबूत हैं। हम जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं कर रहे हैं। वहां अलग तरह की चुनौतियां हैं।

इस सत्र के समाप्त होते ही अगले सत्र की तैयारी शुरू हो जाएगी। अगले वर्ष की शुरुआत दिल्ली से होगी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल की सजा ने इस संघर्ष को अलग धार दी है। उसके बाद सितंबर में बिहार विधानसभा चुनाव के साथ दिन का अंतिम सत्र होगा। इन तीन सत्रों में कम से कम दो जीतने वाले को 2029 के चुनाव की दिशा में बढ़त हासिल होगी।

मोदी ने इस कार्यकाल में कई चुनौतियों के साथ प्रवेश किया है जो चुनाव अभियान के दौरान ही उभरने लगी थीं। कानून बनाने को लेकर अब तक के रवैये में कई बदलाव लाने होंगे। अहम कानूनों को एक झटके में पारित करने का समय अब नहीं रहा। जरूरी संविधान संशोधनों के लिए भी प्रतीक्षा करनी होगी।

'अबकी बार 400 पार' के नारे ने संविधान को लेकर व्यापक असुरक्षा को जन्म दिया। सरकार को कुछ समय तक किसी संशोधन का प्रस्ताव रखने से भी गुरेज करना होगा। निश्चित तौर पर एक हल यह होगा कि विपक्ष से बातचीत करके इन संशोधनों को पेश किया जाए। इसके लिए मोदी युग में भाजपा की राजनीति में आमूलचूल बदलाव लाना होगा।

पहले संसदीय सत्र में तो किसी तरह की राहत मिलती नहीं नजर आई। इससे तो यही अंदाजा लगा कि दोनों पक्ष एक दूसरे से उलझे हुए हैं और उनके बीच पूरी तरह अविश्वास का माहौल है। नई सरकार के सामने जो राजनीतिक चुनौतियां हैं उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है 'जय जवान/जय किसान' का जाल। दो दशकों में मोदी ने अपनी छवि किसानों और सशस्त्र बलों के हिमायती के रूप में गढ़ी है। इन चुनावों में इस छवि को झटका लगा क्योंकि पार्टी को कृषि और सैनिकों की अधिकता वाले राज्यों मसलन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में झटका लगा। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का शुरुआती वादा बुरी तरह विफल रहा और कृषि सुधारों को लेकर होने वाली बहस को उन कानूनों ने बरबाद कर दिया जिन्हें अध्यादेशों के माध्यम से लाया गया और फिर संसद द्वारा पारित किया गया। अब क्या मोदी उन पर पुनर्विचार कर सकते हैं और विपक्ष को साथ ला सकते हैं? अगर वह ऐसा करते हैं तो उनका बुनियादी विचार क्या होगा?

इस बात की संभावना भी कम है कि नए सिरे से उत्साहित विपक्ष रचनात्मक प्रतिक्रिया देगा। खासकर तब जबकि एक अंतराल के बाद मैच का एक और सत्र होने वाला हो। दूसरी ओर अगर अब सरकार कृषि को लेकर और लोकप्रिय कदम उठाती है तो यह निराश करने वाली बात होगी। यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का दायरा और उसकी दरें बढ़ाना और कृषि माफी करना तथा साथ ही जैव प्रौद्योगिकी एवं जीएम बीजों पर स्वदेशी के तहत रोक लगाना।

भारतीय स्टेट बैंक की आर्थिक शोध शाखा की ओर से आई साहसिक रिपोर्ट कृषि क्षेत्र में राह दिखाती है। स्टेट बैंक इस बात को रेखांकित करता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था कैसे चंद किसानों के लिए काम करती है और कुल कृषि उत्पादन का छह फीसदी ही इसमें आता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य में अधिक साहसिक सुधारों की आवश्यकता है जिसके तहत बाजार और एमएसपी से दूरी बनानी होगी।

क्या भाजपा की राजनीति में ऐसे मसलों पर कदम उठाने की कोई गुंजाइश बची है। शिवराज सिंह चौहान के रूप में पार्टी ने कृषि मंत्री के रूप में बढ़िया चयन किया है। बीते करीब दो दशक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने खेती में बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। उन्हें एक मिलनसार, समझौते करने वाला और राजनीतिक रूप से कुशल राजनेता माना जाता है। वह भाजपा के वाजपेयी युग के गिनेचुने नेताओं में शामिल हैं। हालांकि कठिन होगा लेकिन अगर इन विषयों पर उन्हें समर्थन मिल पाता है तो यह सुखद होगा।

अगर किसान मुद्दे पर लगा झटका विफल कृषि सुधारों से उत्पन्न हुआ है तो जवानों के मुद्दे पर नकारात्मकता भी ऐसे ही दंभ की वजह से उत्पन्न हुई। सेना में छोटी अवधि वाले कार्यकाल खासकर अन्य रैंक के लिए ऐसे कार्यकाल का विचार तीन दशक पहले आया था।

इससे पेंशन का बढ़ता बोझ कम होता है और आधुनिकीकरण के लिए अधिक गुंजाइश बनती है। परंतु इसका बड़ा लाभ यह भी है कि सेना के जवान युवा रहते हैं। फिलहाल उनकी औसत आयु 33 वर्ष जो बहुत अधिक है। यह बदलती तकनीक के लिहाज से भी उपयुक्त होता है। यह युवा भारतीयों को अवसर देता है कि वे सशस्त्र बलों में सेवाएं दें और अधिक कुशल तथा रोजगार क्षमता के साथ सेना से निकलें।

कृषि कानूनों की तरह यह भी चर्चा के बिना लागू की गई योजना थी। अब अग्निपथ में कई बदलाव किए जाएंगे। उदाहरण के लिए आप एक ही यूनिट के और एक ही बंकर के और एक ही बम से हताहत होने वाले दो सैनिकों के लिए अलग-अलग हर्जाने की व्यवस्था को कैसे उचित ठहराएंगे? क्या दोनों को अलग बिल्ला पहनाना और दो वर्ग तैयार करना जरूरी है?

आपात काल और अधिकारियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के रूप में मॉडल पहले से तैयार थे जिनके तहत सेवा में रहने के दौरान सभी समान थे लेकिन सेवा अवधि की लंबाई के मुताबिक उनके कार्यकाल तथा क्षतिपूर्ति अलग-अलग थे। ऐसा बड़ा बदलाव हमेशा चुनौती लाता है लेकिन अधिक धैर्य तथा अंशधारकों से बातचीत से मुश्किलें कम होतीं।

मोदी सरकार को इन चुनौतियों का सामना उस ताकत के बिना करना होगा जिसकी उसे आदत थी। इस दौरान उसे एक के बाद एक लगातार हमले भी झेलने होंगे। हम जानते हैं कि समय के साथ अक्सर पिच भी खराब होती जाती है। यही वजह है कि तीसरा कार्यकाल पहले दो कार्यकाल की तरह नहीं होगा।

बजट में रोजगार, हुनर, नवाचार पर होगा जोर!

सामयिक सवाल
निवेदिता मुखर्जी

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश होने में दो सप्ताह से भी कम समय शेष रह गया है। अब तक जो संकेत मिले हैं वे सभी महत्त्वपूर्ण एवं विचारणीय हैं। उदाहरण के लिए जब सरकार ने हाल ही में रोजगार एवं कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति का नाम बदलकर कौशल, रोजगार एवं आजीविका पर मंत्रिमंडलीय समिति रखा तो यह घोषणा बजट को लेकर एक संकेत दे गया। कौशल या हुनर को रोजगार से पहले रखकर क्या सरकार यह संदेश दे रही है कि संयंत्रों एवं विनिर्माण केंद्रों में श्रमिकों की कमी से पड़ने वाले असर को देखते हुए लोगों को हुनरमंद बनाना उसका अब मुख्य मकसद हो गया है? क्या आजीविका को समिति के अंतर्गत लाकर सरकार नौकरियों एवं रोजगार का दायरा मौजूदा हालात को देखते हुए बढ़ा रही है? शायद, ऐसा हो सकता है।

मंत्रिमंडलीय समितियों के पुनर्गठन के अलावा संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण, इस पर प्रधानमंत्री का जवाब और 18वीं लोकसभा की पहली मंत्रिमंडल की बैठक से भी बजट को लेकर कई संकेत सामने आए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि बजट में ऐतिहासिक कदमों की घोषणा की जाएगी, जिनके दायरे में आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दे आएंगे और सुधारों पर विशेष ध्यान रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकास के नए चरण में ले जाने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर कहा है कि उनकी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में तीन गुना गति से काम करेगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में उन व्यापक योजनाओं की तरफ भी इशारा किया गया है, जो बजट में कल्याणकारी योजनाओं के रूप में सामने आ सकते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत घर बनाने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को सहायता दी जाएगी। ये सभी कदम रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं, मगर बेशक हम इन रोजगारों की गुणवत्ता एवं इसके टिकाऊ होने के बारे में निश्चित रूप से फिलहाल कुछ नहीं कह सकते।

वित्त वर्ष 2025 पूरा होने में लगभग आठ महीने शेष रह गए हैं। इसे देखते हुए यह बजट आंकड़ों में कोई खास बदलाव किए बिना उन योजनाओं पर अधिक दांव खेल सकता है, जो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए माहौल तैयार कर सकता है। यह संभव है कि चुनाव नतीजों के बाद अलग हालात सामने आने से सरकार ने योजनाओं पर अधिक गहराई से काम करने के लिए बजट जुलाई के अंतिम सप्ताह में लाने का निर्णय किया हो। चुनाव से पहले अधिकारी जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई की शुरुआत में बजट लाने का लक्ष्य रख रहे थे। उस समय न ही गठबंधन सरकार और न ही मजबूत विपक्ष उभरने की कोई तस्वीर दिख रही थी।

अगर यह वास्तव में बड़े बदलाव एवं लक्ष्यों वाला बजट है तो गुणवत्तापूर्ण रोजगार एवं कौशल विकास सभी मंत्रालयों एवं विभागों के लिए मुख्य बिंदु होने चाहिए। इसके लिए उद्योग जगत और अकादमिक संस्थानों (देश के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर) के बीच सहयोग बजट तैयार करने की प्रक्रिया में प्रमुखता से आना चाहिए। इसका मतलब यह होगा कि सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स खंड में भारत विशेष जोर देने के लिए अन्य देशों सहित ताइवान और चीन के संगठनों, कारोबारों एवं संस्थानों के साथ सहयोग करेगा। भारत ने अब तक इस दिशा में छोटे कदम उठाए हैं मगर विनिर्माण क्षेत्र में बड़ी बढ़त हासिल करने के लिए इसे वैश्विक ताकतों के साथ सहयोग करने की जरूरत होगी। इस प्रक्रिया में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में उद्योग-शिक्षा क्षेत्र के बीच सहयोग की जरूरत का जिक्र किया था। पूर्ण बजट में इस पहल को प्रमुखता दी जा सकती है। मगर यह सब करने के लिए शोध एवं विकास (आरऐंडडी) पर खर्च करना होगा।

फरवरी में अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने तकनीकी खंड में शोध आगे बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के कोष की घोषणा की थी और तकनीक में नवाचार के लिए एक योजना का भी प्रस्ताव दिया था। शोध एवं विकास पर भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1 प्रतिशत से भी कम खर्च करता है। अमेरिका, जर्मनी, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश इस मामले में भारत से कहीं आगे हैं। भारत में आरऐंडडी पर निजी क्षेत्र का सकल घरेलू व्यय उसके कुल व्यय का 40 प्रतिशत से नीचे रहा है। तकनीक से जुड़े नवाचारों पर अधिक ध्यान देने वाले देशों जापान, अमेरिका, जर्मनी और दक्षिण कोरिया में आरऐंडडी पर होने वाले खर्च का एक बड़ा हिस्सा (65 से 70 प्रतिशत तक) निजी उद्यमों से आता है।

रोजगार, नवाचार एवं ऐसी ही अन्य चीजें बजट में ध्यान खींच सकती हैं, मगर कर प्रस्तावों पर सबका विशेष ध्यान रहता है। इस लिहाज से बजट तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़े रहे एवं बजट पर विशेष नजर रखने वाले एक व्यक्ति की राय में सरकार को वित्तीय बजट को बढ़ावा देने और पूंजी बाजारों का दायरा व्यापक बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा सीमा शुल्क घटाने के साथ उद्योग जगत को वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निर्यात बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 'उत्पादकता आयोग' की स्थापना की जानी चाहिए।

वित्त मंत्री एवं उनकी टीम को सभी संबंधित पक्षों से प्रतिक्रियाएं एवं सुझाव मिल चुके हैं, इसलिए हालात और चारों तरफ से मिल रहे संकेतों को देखते-समझते हुए बड़े लक्ष्यों एवं योजनाओं पर गंभीरता से विचार शुरू हो जाना चाहिए।

आपका पक्ष

नई कर व्यवस्था से आसान हुआ कारोबार

जीएसटी लागू हुए सात वर्ष हो गए। इस नई कर व्यवस्था ने न केवल अनुपालन को सरल बनाया है, बल्कि कर संग्रह में तेज वृद्धि दर्ज की गई। राज्यों के राजस्व में तेज वृद्धि हुई है। हालांकि, कर चोरी को रोकने की कोशिश अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हुई है। फर्जी चालान और फर्जी जीएसटी पंजीकरण चुनौती बने हुए हैं। जीएसटी के तहत 17 करों और 13 तरह के उपकरों को पांच स्तरीय टैक्स व्यवस्था में समाहित कर दिया गया। जीएसटी पंजीकरण के लिए टर्नओवर की सीमा वस्तुओं के लिए 40 लाख रुपये और सेवाओं के लिए 20 लाख रुपये है। जीएसटी ने कई आवश्यक वस्तुओं पर करों को जीएसटी से पहले की दरों की तुलना में कम कर दिया है। बालों में लगाने वाले तेल और साबुन जैसी आम वस्तुओं पर कर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया। बिजली के उपकरणों पर कर 31.5 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया। जीएसटी ने कई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को कर से छूट भी प्रदान की है। इसमें बिना ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ, कुछ जीवन रक्षक दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन, सैनिटरी नैपकिन, श्रवण यंत्र के पुर्जे, कृषि सेवाएं आदि। वर्ष 2023 में जीएसटी खुफिया निदेशालय (डीजीजीआई) ने 1.98 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी का पता लगाया और सरकारी खजाने को चूना लगाने में शामिल 140 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, बीमा और मैनपावर सेवाओं का आयात जैसे विविध क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण जीएसटी चोरी का पता चला है। जीएसटी अपील न्यायाधिकरण की स्थापना से विवाद समाधान प्रक्रिया के तेज होने की उम्मीद है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

जीएसटी ने कई आवश्यक वस्तुओं पर करों को जीएसटी से पहले की दरों की तुलना में कम कर दिया है

मेडिकल की पढ़ाई में बड़ी चुनौतियां

जनसंख्या के मामले में भारत दुनियाभर में शीर्ष स्थान पर है। इसलिए मेडिकल की पढ़ाई को सुदृढ़ करना सरकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने से युवाओं को विदेशों का रुख नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यह शायद संभव नहीं है। देश में मेडिकल पढ़ाई के प्रति जो सरकारों का ढुलमुल रवैया है, इस कारण युवाओं को अपना करियर बनाने के लिए विदेशों का रुख करना पड़ता है। बहुत से भारतीय मूल के चिकित्सक दूसरे देशों में जाकर अद्भुत कारनामे कर रहे हैं। हमारे देश में चिकित्सा के बहुत से प्रतिभाशाली युवा आर्थिक तंगी के कारण मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाते। कुछ युवा विज्ञान की पढ़ाई करने में रुचि, जिसमें मुख्यतः नॉन मेडिकल की, नहीं दिखाते हैं क्योंकि उन्हें यह उम्मीद नहीं होती कि मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद उन्हें आगे बढ़ने या फिर इस क्षेत्र में कुछ नया कर दिखाने का मौका मिलेगा। सरकार को मेडिकल की पढ़ाई की तरफ गंभीरता दिखाना चाहिए और जो इस क्षेत्र में कुछ कर दिखाना चाहते हैं उनकी हरसंभव मदद करनी चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने रविवार को पेरिस में कमांड कार पर सवार होकर 'बास्टिल डे परेड' समारोह के अवसर पर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। ओलिंपिक शुरू होने से 12 दिन पहले ओलिंपिक मशाल की लौ ने भव्य बास्टिल डे में सैन्य परेड को रोशन किया।

दैनिक जागरण

कष्ट सहने पर ही अनुभव होता है

विषाक्त वातावरण का नतीजा

अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला एक बेहद गंभीर घटना है। वह बाल-बाल बचे, लेकिन उन्हें निशाना बनाने वाला जिस तरह उन पर गोलियां बरसाने में सक्षम रहा, वह सुरक्षा में गंभीर चूक का नतीजा है। यह इससे स्पष्ट होता है कि हमलावर की गतिविधि के बारे में ट्रंप की रैली में आए लोगों ने सुरक्षाकर्मियों को बताया भी था, लेकिन उन्होंने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। चूंकि हमलावर मारा गया है इसलिए यह जानना कठिन हो सकता है कि ट्रंप को निशाना बनाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था, लेकिन इससे इन्कार नहीं कि यह घटना उस विषाक्त राजनीतिक वातावरण का परिणाम जान पड़ती है जो अमेरिका में पिछले कुछ समय से व्याप्त है। चिंता की बात यह है कि यह विषाक्त राजनीतिक वातावरण दिन-प्रतिदिन गहराता जा रहा है। अमेरिका इस समय राजनीतिक और वैचारिक रूप से इतना अधिक विभाजित है कि उसका दुष्प्रभाव पूरे समाज पर पड़ रहा है। किसी भी लोकतंत्र के लिए यह स्थिति ठीक नहीं, लेकिन इसमें संदेह है कि अमेरिका में वैचारिक विभाजन थमेगा।

अमेरिका में राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपतियों और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर हमले का एक इतिहास रहा है। इस हमले में कई नेताओं की जान भी जा चुकी है। अमेरिका में सार्वजनिक स्थानों में गोलीबारी की घटनाएं नई नहीं हैं। ये घटनाएं अमेरिका में व्याप्त बंदूक संस्कृति का नतीजा हैं। इस बंदूक संस्कृति को लेकर विभिन्न स्तरों पर चिंता जताई जा चुकी है, लेकिन कोई भी उस पर रोक लगाने के लिए तैयार नहीं। यह संस्कृति एक तरह से विश्व में सबसे घातक आंतरिक आतंक का पर्याय बन चुकी है। वैसे तो अमेरिका दुनिया भर को उपदेश देता रहता है, लेकिन वह यह देखने-समझने को तैयार नहीं कि स्वयं उसके अपने यहां क्या स्थिति है। डोनाल्ड ट्रंप पर एक ऐसे समय हमला हुआ है जब राष्ट्रपति पद के लिए उनकी दावेदारी पर मुहर लगने वाली है। इसके भरे-पूरे आसार हैं कि इस हमले के बाद ट्रंप को सहानुभूति का लाभ मिलेगा। इससे वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन की कठिनाई बढ़ सकती है। इसलिए और भी, क्योंकि उन पर पहले ही यह दबाव है कि वह अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पीछे हट जाएं। चूंकि अमेरिका विश्व का सबसे सशक्त लोकतंत्र है और वैश्विक राजनीति को कहीं गहराई से प्रभावित करता है इसलिए यह स्वाभाविक है कि भारत समेत दुनिया भर के नेताओं ने ट्रंप पर हमले की निंदा करते हुए चिंता जताई है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि जैसा विषैला राजनीतिक वातावरण अमेरिका में है वैसा दुनिया के अन्य देशों में भी बन रहा है। दुर्भाग्य से इनमें भारत भी है। राजनीतिक विरोध और असहमति का भाव जिस तरह शत्रुता में परिवर्तित होती जा रही है वह शुभ संकेत नहीं। उचित यह होगा कि अपने देश के नेता यह समझें कि जब राजनीतिक मतभेद एक-दूसरे के प्रति विद्वेष में बदल जाते हैं तो इसके कैसे नतीजे होते हैं।

समान कानून से समरसता

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को कानून का रूप दिया जा चुका है। अब उसे आगामी माह अक्टूबर से क्रियान्वित करने की तैयारी है। इसके लिए नियमावली बनाई जा रही है। कानून का क्रियान्वयन किस प्रकार होता है, स्वाभाविक रूप से इस पर प्रदेशवासियों की ही नहीं, बल्कि पूरे देश की टकटकी लगी है। देश में समान नागरिक संहिता की पहल उत्तराखंड ने की है। अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि विभिन्न धर्मों, पंथों, समुदायों और वर्गों वाले विविधता से युक्त हमारे समाज में कानूनी समानता का समर्थन करने वाली समान नागरिक संहिता को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए। प्रदेश सरकार ने इसी चुनौती को समझकर नियमावली तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति कानून के क्रियान्वयन से जुड़ी तमाम प्रक्रियाओं को सहज और सरल तरीके से नियमावली के रूप में ढाल रही है, ताकि पारदर्शिता और बगैर झंझट के इसे लागू किया जा सके। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित नियमावली समिति के अधिकतर सदस्य समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति में भी सम्मिलित रहे हैं। विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप, गुजारा भत्ता, विरासत एवं उत्तराधिकार जैसे परिवार से संबंधित नए कानून की प्रक्रियाओं को इस प्रकार सरलीकृत किया जा रहा है कि इसे मोबाइल अथवा कंप्यूटर पर बैठकर ही पूरा किया जा सके। प्रक्रियाओं को आनलाइन किए जाने का बड़ा लाभ आमजन को ही होना है। संहिता के अनुपालन से जुड़े कार्मिकों के लिए संहिता के कानूनी पहलुओं और प्रक्रियाओं की जानकारी के लिए सघन प्रशिक्षण होना चाहिए। अच्छा यह भी है कि नियमावली समिति इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर नियमों को अंतिम रूप देने में जुटी है।

संसद की गरिमा पर संकट

हृदयनारायण दीक्षित

संसद हुल्लड़ की जगह नहीं, बल्कि लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। वहां लगातार अव्यवस्था का बढ़ना राष्ट्रीय चिंता का विषय है

संसद राजनीतिक कलह का मंच नहीं है, लेकिन काफी समय से संसदीय मर्यादा का जबरदस्त ह्रास हुआ है। अध्यक्ष का आसन सर्वोपरि होता है। संविधान की दुहाई सब देते हैं, लेकिन पीठासीन अधिकारी के निर्देशों की प्रायः धज्जियां उड़ाई जाती हैं। 18वीं लोकसभा के शपथ ग्रहण के दौरान कुछ सदस्यों ने संवैधानिक शपथ के साथ अपने वाक्य भी जोड़े। यहां न मर्यादा बची है और न ही संयम एवं अनुशासन। संसदीय व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष का पद और दायित्व सम्माननीय है, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा। उनके वक्तव्य से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। अध्यक्ष ने आपत्तिजनक अंश कार्यवाही से निकाल दिए हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष वही बातें दोहरा कर फिर से जोड़े जाने की मांग कर रहे हैं।

भारत के लोग संविधान और संसद के प्रति आदरभाव रखते हैं। भारतीय संसद की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा रही है। अनेक सदस्य संसद के लिए पवित्र सदन, आदरणीय सदन या आगस्ट हाउस कहते हैं। संसद सदस्यों पर विधि निर्माण और संविधान संशोधन की जिम्मेदारी है। आश्चर्य है कि अनेक सदस्य कार्यवाही में बाधा डालते हैं। नियमावली की भी उपेक्षा करते हैं। इससे आहत पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने सदन की नियमावली को ही जला देने की बात कही थी। विधायी संस्थाओं में विधि और नियम का उल्लंघन साधारण घटना नहीं है। सदनों में कार्यवाही की गुणवत्ता की चिंता पुरानी है। ब्रिटिश राज में गठित केंद्रीय विधानसभा के समय (1921) अध्यक्ष फ्रेडरिक वाइट की अध्यक्षता में पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन शिमला में हुआ था। तब से हर साल पीठासीन अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन होते हैं। लोकसभा के प्रकाशन 'संसदीय पद्धति और प्रक्रिया' के अनुसार सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि शासन की संसदीय प्रणाली का समुचित विकास हो। सदस्यों के संयम और आचरण भी महत्वपूर्ण हैं।

संप्रति, संसदीय कार्यवाही निस्तेज हो रही है। संसदीय गतिरोध एवं अव्यवस्था ने निराश किया है। माननीयों के सम्यक आचरण पर जनता की निगाह रहती है। सांसदों के लिए कोई निश्चित आचार संहिता नहीं है। अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने का मुद्दा बार-बार चर्चा में आता है। मई 1992 में गुजरात में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था। सुझाव आया था कि अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने पर विचार के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया जाए। इसके अनुसरण में 23 और 24 सितंबर, 1992 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पीठासीन अधिकारियों, सदनों के दलीय नेताओं, संसदीय कार्य मंत्रियों और सांसदों आदि की भागीदारी में सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में गंभीर विचार विमर्श के बाद संसदीय परंपराओं और नियमों के आधार पर आचार संहिता का एक प्रारूप तैयार किया गया और उसे संसद तथा विधानमंडलों में 'अनुशासन तथा शिष्टाचार' शीर्षक पत्र में शामिल किया गया। इसे लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित किया गया। सम्मेलन में सदस्यों के दायित्व और कर्तव्य के लिए सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया। सुझाव दिया गया कि सभी राजनीतिक दल अपने जनप्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता तैयार करें। अनुपालन सुनिश्चित करें। यह काम राजनीतिक दलों को करना था। दलतंत्र ने उसकी उपेक्षा की। लोकसभा के स्वर्ण जयंती सत्र के अंतर्गत 26 अगस्त, 1997 से एक सितंबर, 1997 के दौरान यह विषय फिर विमर्श के लिए सामने आया। सभा ने एकमत से संकल्प पारित किया। संकल्प के अनुसार, 'सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों, व्यवस्थित कार्य संचालन संबंधी पीठासीन अधिकारियों के निर्देशों के गरिमापूर्ण अनुपालन द्वारा संसद की प्रतिष्ठा का परिरक्षण और संवर्धन किया जाए।' संकल्प बहुत अच्छा था, लेकिन परिणाम शून्य रहा। संकल्प में अन्य बातों के अलावा प्रश्न काल की महत्ता और नारेबाजी पर रोक तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण में व्यवधान न करना भी शामिल था। 2001 में नियमों में संशोधन हुआ कि अध्यक्ष के आसन के सामने नारेबाजी करने वाले स्वतः निलंबित होंगे। निलंबन भी थोक के भाव हुए, मगर कोई लाभ नहीं हुआ।

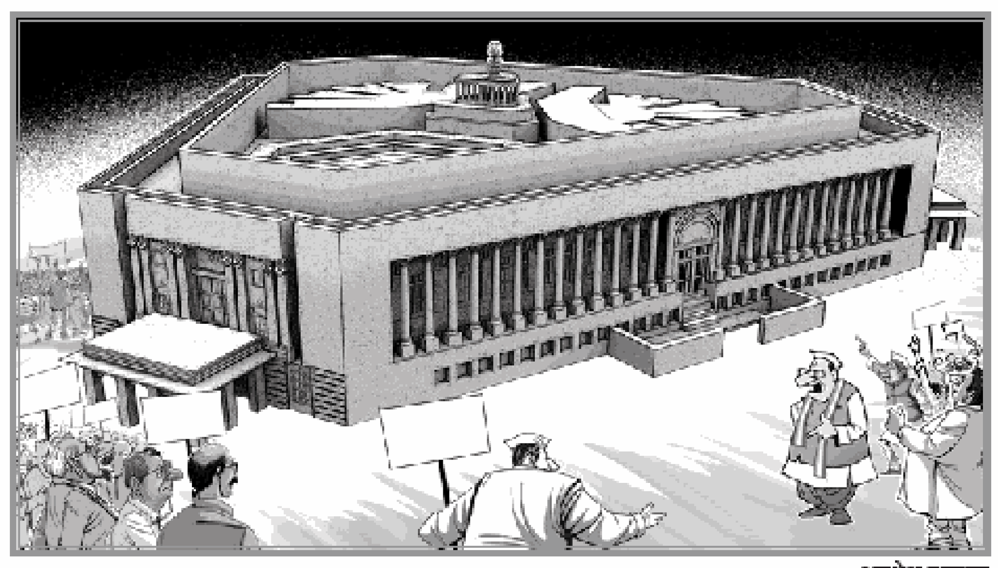

अवधेश राजपूत

इसी क्रम में 13वीं लोकसभा के दौरान अध्यक्ष ने 16 मई, 2000 को लोकसभा में 15 सदस्यीय आचार समिति का गठन किया था। समिति को सदस्यों की नैतिकता और आचरण पर ध्यान रखना, सदस्य के संसदीय व्यवहार से संबंधित अनैतिक आचरण की शिकायत की जांच करना था। इसने पहला प्रतिवेदन 31 अगस्त, 2001 को प्रस्तुत किया। इसे 16 मई, 2002 को सभा ने स्वीकृत कर दिया। व्यवस्था, अनुशासन और संयम और वाक् संयम जैसे सामान्य विषयों पर लगातार बैठकें चलती रहीं, लेकिन ऐसे सम्मेलनों और बैठकों के भी अपेक्षित परिणाम नहीं आए।

सदनों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण काफी लोकप्रिय हुआ है। उम्मीद की जाती थी कि सदन के भीतर अपशब्द बोलने, नियम तोड़ने, अध्यक्ष की बात न मानने जैसे व्यवहार को आम जनता देखेगी और अपने जनप्रतिनिधि के अनुचित आचरण का संज्ञान लेगी। यह संभावना गलत निकली। सदनों में हंगामा करने वाले सदस्यों के क्षेत्र में निर्वाचकगण हुल्लड़ देखकर संभवतः दुखी नहीं होते। संसद हुल्लड़ की जगह नहीं है। लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। जनप्रतिनिधि सदनों में अव्यवस्था का लगातार बढ़ना राष्ट्रीय चिंता का विषय है। बेशक जनप्रतिनिधि जनता से चुने जाते हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक दल ही उम्मीदवार बनाते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों पर दलों का नियंत्रण रहता है। संसदीय समिति ने ठीक ही सिफारिश की थी कि राजनीतिक दल अपने-अपने प्रतिनिधियों के आचरण और व्यवहार पर ध्यान दें। संसद के सभी दलों के संसदीय पदाधिकारी परस्पर संवाद बनाएं। संसद में मर्यादा बनाए रखने के विषय पर संसद का विशेष सत्र आहूत करने पर विचार करें। भारतीय संसद विश्व की सभी जनप्रतिनिधि संस्थाओं से बड़ी है। पवित्र सदन में संवाद के स्थान पर अव्यवस्था उचित नहीं।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

आइएनडीआइए के जटिल समीकरण

राज कुमार सिंह

लोकसभा चुनाव के बाद से संकेत मिलने लगे हैं कि कांग्रेस और आप दिल्ली विधानसभा चुनाव अलग-अलग लड़ेंगी

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रिश्ते लोकसभा चुनाव के बाद फिर बदल रहे हैं। आइएनडीआइए में शामिल इन दोनों दलों ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात और गोवा में लोकसभा चुनाव मिल कर लड़ा था, पर परिणाम अपेक्षित नहीं आए। चंडीगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी की जीत के अलावा दोनों दलों की दोस्ती कहीं करिश्मा नहीं दिखा सकी। चार जून को लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही आप की ओर से संकेत आने लगे थे कि अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव दोनों दल अलग-अलग लड़ सकते हैं। अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दो टूक कह दिया है कि दोनों दलों में गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था, जो विधानसभा चुनावों में संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने हरियाणा में भी गठबंधन से स्पष्ट इन्कार कर दिया, जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आप के लिए कुरुक्षेत्र सीट छोड़ी थी।

हरियाणा में नौ लोकसभा सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस अप्रत्याशित रूप से पांच सीटें जीत गई। ऐसा मानने वालों की कमी नहीं कि अगर कुरुक्षेत्र सीट आप को नहीं दी गई होती तो शायद कांग्रेस उसे भी जीत लेती। गठबंधन कमाल तो गुजरात में भी नहीं कर पाया, जहां कांग्रेस ने लंबे समय तक पार्टी के लिए चाणक्य की भूमिका निभाने वाले अहमद पटेल की भरूच के साथ ही भावनगर लोकसभा सीट भी आप को दे दी थी, लेकिन सबसे निराशाजनक परिणाम दिल्ली ने दिए। वर्ष 2017 में लगातार तीसरी बार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा चुनाव में जबरदस्त बहुमत से आप की सरकार बनी, लेकिन लोकसभा चुनाव में आप का कभी खाता नहीं खुला। आप के उभार का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है, लेकिन दोनों ने सोचा कि शायद मिल कर लोकसभा चुनाव में भाजपा को रोका जा सकता है। भाजपा ने सात में से छह सीटों पर उम्मीदवार बदले, तो लगा भी कि शायद पार्टी आशंकित है, लेकिन परिणाम फिर शत-प्रतिशत रहा। दिल्ली में एक भी सीट पर ऐसा नजदीकी मुकाबला नहीं हुआ कि लगता बाजी पलट भी सकती थी। लगता है कि दोनों ही न तो दिल से मिल कर चुनाव लड़ पाए और न ही अपने वोट एक-दूसरे को ट्रांसफर करा पाए। दिल्ली के संदर्भ में एक कोण और भी है। यहां आप की लगातार तीसरी सरकार है। इसलिए उसके विरुद्ध भी सत्ता विरोधी भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। तब क्या कांग्रेस-आप गठबंधन के चलते सत्ता विरोधी वोट बिना विभाजित हुए भाजपा के लिए मददगार साबित हुए? इस सवाल का सटीक उत्तर संभव नहीं, लेकिन पंजाब के लोकसभा चुनाव परिणाम इसी ओर संकेत करते हैं।

आम चुनाव में प्रभावी नहीं रहा कांग्रेस-आप गठजोड़। फाइल

दिल्ली की तरह पंजाब की सत्ता भी आप ने कांग्रेस से छीनी। फर्क इतना रहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ जैसे प्रमुख नेताओं के पार्टी छोड़ जाने के बावजूद कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल बनने में सफल रही। सत्ता विरोधी वोटों का विभाजन रोकने के मकसद से दोनों दल पंजाब में अलग-अलग चुनाव लड़े और प्रदर्शन अच्छा रहा। लोकसभा चुनाव से पहले आप के एकमात्र सांसद सुशील कुमार रिंकू तथा कांग्रेस के दो सांसद परनीत कौर एवं रवनीत सिंह बिट्टू भी भाजपा में शामिल हो गए। फिर भी पिछली बार आठ लोकसभा सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार सात और मात्र एक सीट जीतने वाली आप तीन सीटें जीतने में सफल रहीं। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस और आप के अलग-अलग लड़ने की रणनीति ने पंजाब में भाजपा का खाता नहीं खुलने दिया।

अब कांग्रेस-आप गठबंधन टूटने से संभावित परिदृश्य की बात करते हैं। हरियाणा में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछली बार 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा बहुमत के आंकड़े से छह सीटें पीछे रह गई थी और उसे 10 विधायकों वाली जजपा से गठबंधन कर दुष्यंत चौटाला को उपमुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई कांग्रेस ने उसी साल हुए विधानसभा चुनावों में 31 सीटों के साथ चौंकाने वाला प्रदर्शन किया था। अब पांच लोकसभा सीटें जीतने से उत्साहित कांग्रेस विधानसभा में किसी के साथ सीटें नहीं बांटना चाहती। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह अन्य दलों के नेताओं को शामिल कर रहे हैं, उससे कांग्रेस में ही टिकट वितरण बड़ी चुनौती साबित होगा, पर क्या बहुकोणीय मुकाबला होने पर पिछले चुनाव जैसे नतीजों की आशंका नहीं रहेगी? शायद दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस-आप के अलग-अलग चुनाव लड़ने से अलग-अलग परिदृश्य भी होगा, क्योंकि दोनों राज्यों की चुनौतियां भी अलग हैं। दिल्ली में सत्ता विरोधी मतों का विभाजन करना है, जबकि हरियाणा में वही विभाजन रोकना है। हां, आप को हरियाणा में जो भी वोट मिलेंगे, वे होंगे कांग्रेस के ही संभावित वोट। इसलिए उसकी मौजूदगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हुए भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ ही पहुंचाएगी, जैसे कि गुजरात और गोआ विधानसभा चुनावों में हुआ था। वैसे हरियाणा में आप की जो जमीनी हालत है, दिल्ली में कांग्रेस उससे तो ज्यादा ही मजबूत है। इसलिए सत्ता विरोधी वोटों में हिस्सा बांट कर वह भाजपा को नुकसान और आप को फायदा पहुंचा सकती है। यानी राज्य-दर-राज्य विपक्ष को अलग चुनावी रणनीति की जरूरत होगी। जाहिर है, ऐसा जटिल संतुलन साधते हुए राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी आइएनडीआइए की एकजुटता और आक्रामकता को बनाए रखना विपक्ष के लिए बड़ी और कड़ी परीक्षा साबित होने जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में भी विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

शब्दों का प्रभाव

शब्दों को हमारे विचारों की मुद्रा कहा गया है। शब्दों में अतुलनीय शक्ति होती है। इनका अपना कोई आकार नहीं होता। फिर भी मनुष्य के मन पर शब्दों का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। शब्द हमारे मानसिक पटल का दर्पण माने गए हैं। जिस प्रकार एक वाद्य यंत्र की पहचान उसके स्वर से होती है, ठीक उसी तरह व्यक्ति की पहचान वाणी के माध्यम से बोले गए शब्दों द्वारा होती है।

शब्दों के प्रयोग में मनुष्य के आचरण की शुचिता झलकती है। शब्द अदृश्य होते हुए भी बड़ी सशक्तता के साथ श्रोता को प्रभावित करते हैं। शब्दों में ही मनुष्य के पारिवारिक, सामाजिक संबंधों का निर्माण तथा विध्वंस निहित है। स्नेहिल शब्दों का प्रभाव औषधि के समान कल्याणकारी होता है। जिस प्रकार औषधि रोगी को शांति प्रदान करती है उसी प्रकार शालीनता से प्रयोग किए गए शब्द सुनने वाले के मन में शांति और उल्लास का संचार करते हैं। क्रोधित अवस्था में बोले गए शब्द विष के समान मनुष्य के अंतःकरण को उद्विग्न बना देते हैं। वाणी द्वारा शब्दों का प्रयोग करते हुए विवेक का प्रयोग आवश्यक है। विवेकहीन होकर प्रयोग किए गए शब्द मधुर संबंधों को भी नष्ट कर देते हैं। मनुष्य के मन में उतरना तथा मन से उतरना शब्दों के प्रयोग पर ही निर्भर करता है। कटु एवं असभ्य शब्दों का प्रयोग शस्त्र के घाव से भी भयंकर होता है। शस्त्र का घाव तो कुछ समय पश्चात भर जाता है, परंतु शब्दों द्वारा घायल किया गया मनुष्य का मानसिक पटल जीवन भर नहीं भरता। शब्दों का प्रभाव बड़ा त्वरित और प्रबल होता है। शब्द विष भी हैं और अमृत भी। शब्दों के सांचे में ही मानवीय संबंधों का ताना-बाना निर्मित होता है। माधुर्य एवं सौम्यता से परिपूर्ण शब्दावली में शत्रु को भी मित्र बनाने की क्षमता होती है। शब्द वरदान भी बन जाते हैं और अभिशाप भी। शब्दों से ही मनुष्य का व्यक्तित्व परिलक्षित होता है।

आचार्य दीप चंद भारद्वाज

हुनरमंद भारत समय की मांग

देवेंद्रराज सुथार

अगर हमें भारत को विकास की राह पर आगे ले जाना है, तो हुनरमंद भारत हमारा पहला मिशन होना चाहिए

किसी भी देश को उन्नत बनाने में युवाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा महत्व रखती है। अगर युवा दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तो देश का तरक्की करना मुमकिन नहीं है। 15 जुलाई, 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तरक्की में युवाओं के योगदान और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पहली बार विश्व युवा कौशल दिवस मनाने की घोषणा की थी। तब से हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों में कुशल कार्यबल का प्रतिशत काफी कम है। विकसित देशों में कुल कुशल कार्यबल 60 से 90 प्रतिशत है, जबकि भारत में 20-24 वर्ष की उम्र के सिर्फ पांच प्रतिशत लोग ही ऐसे हैं जिनमें औपचारिक व्यावसायिक कौशल देखने को मिलता है। युवा वर्ग किसी भी देश का भविष्य होता है। भारत अन्य देशों को पछाड़ सकता है, क्योंकि देश की 65 प्रतिशत आबादी 35 आयु वर्ग से नीचे की है तथा 50 प्रतिशत की आबादी 25 आयु वर्ग से नीचे की है।

समय की मांग युवाओं में कौशल बढ़ाने की है, ताकि रोजगार की जरूरतों को पूरा किया जा सके। हमने यह समझने में बहुत देर कर दी कि अकादमिक शिक्षा की तरह अपनी नई पीढ़ी को बाजार की मांग के मुताबिक उच्च गुणवत्ता वाली कौशल शिक्षा देना भी हमारे लिए जरूरी है। दक्षिण कोरिया ने विकास के मामले में चमत्कार कर दिया है। साल 1950 तक विकास के मामले में दक्षिण कोरिया हमारे मुकाबले कहीं नहीं था, लेकिन आज उसकी गिनती भारत के एक पायदान आगे वाले देशों में होती है और विकास के कुछ पैमाने पर वह जर्मनी को पीछे छोड़ चुका है, तो इसमें बड़ी भूमिका कौशल से जुड़ी शिक्षा की है। निश्चित रूप से कौशल विकास को बढ़ावा दिए बिना देश विकसित एवं आत्मनिर्भर नहीं हो सकता।

मशीनीकरण के इस दौर में करोड़ों हाथों को तभी काम दिया जा सकता है, जब उन हाथों में हुनर हो। तभी वे उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि हुनर के विकास से देश के विकास को मजबूती मिलेगी, अगर हमें भारत को विकास की राह पर आगे ले जाना है, तो हुनरमंद भारत हमारा पहला मिशन होना चाहिए। निष्कर्षतः भारत में बड़ी संख्या में युवा शक्ति है। अगर इसके कौशल विकास पर ध्यान दिया जाए, तो हमारा देश निश्चित रूप से विकास के मामले में सफलता के झंडे गाड़ सकता है। चीन, जर्मनी या दक्षिण कोरिया की तरह हम भी आर्थिक महाशक्ति बन सकते हैं। आज के युग में विकास के लिए जितने संसाधन, पूंजी आदि आवश्यक हैं, उतने ही कुशल मानव संसाधन भी। इसके लिए जरूरी है कि देशभर में कौशल विकास केंद्रों का जाल हो, साथ ही इन केंद्रों को उद्योगों के साथ जोड़ा जाए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

समाज की अखंडता पर हमला

डा. ऋतु सारस्वत ने 'मतांतरण की खतरनाक चुनौती' शीर्षक से जो लेख लिखा है, वह आज के समय की एक गंभीर समस्या को सामने लाता है। मतांतरण सिर्फ एक धार्मिक परिवर्तन नहीं है, यह समाज की जड़ों को हिला देने वाली प्रक्रिया है। यह सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाता है, जो हमारे देश की पहचान है। हमारे देश की विशेषता इसकी विविधता में है। विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का संगम हमारे समाज को मजबूत बनाता है। मतांतरण के कारण यह संगम टूटता है और समाज में विभाजन की स्थिति पैदा होती है। यह सिर्फ धार्मिक असंतुलन नहीं, बल्कि सामाजिक असंतुलन भी लाता है। यह ध्यान देना जरूरी है कि कई बार मतांतरण के पीछे आर्थिक और राजनीतिक कारण भी होते हैं। कुछ संगठन अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बहकाते हैं, जो कि समाज के लिए घातक है। हमें इस प्रकार के प्रयासों से सावधान रहना चाहिए और इन्हें रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। शिक्षा और जागरूकता ही इसका सबसे प्रभावी समाधान है। अगर लोग अपने धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक होंगे, तो वे किसी भी प्रकार के दबाव या प्रलोभन में नहीं आएंगे। समाज में हर व्यक्ति को अपने धर्म और संस्कृति का सही ज्ञान होना चाहिए, ताकि वे अपने मूल्यों को समझ सकें और उन्हें संरक्षित कर सकें। भारत की धार्मिक विविधता उसकी ताकत है, और इसे बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें सतर्क और जागरूक रहना होगा। धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता को बनाए रखने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज को इस प्रकार की चुनौतियों से बचाएं और उसकी समृद्धि और शांति को बनाए रखें।

awanishg30@gmail.com

माता-पिता का भरण-पोषण आवश्यक

किसी की आकस्मिक या अकाल मृत्यु पर उसके परिवार को अक्सर अनेक स्रोतों से राहत की पेशकश की जाती है। उस समय इस बात को विस्मृत कर दिया जाता है कि मृतक के मां-बाप को कितनी बड़ी हानि हुई है। पुत्र की अकाल मृत्यु से मां-बाप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। बेटे के बाद अक्सर बहू एवं पौत्र-पौत्रियां भी उनसे दूर हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त वे आर्थिक सहारे से भी वंचित रह जाते हैं। इन परिस्थितियों के दृष्टिगत मृतक के परिवार को मिलने वाली राशि को पत्नी एवं मां-बाप के मध्य बराबर से बांटना चाहिए। पुत्र ने अपने जीवित रहते मां-बाप की देखभाल के दायित्व का निर्वहन किया ही होता।

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

कौशल विकास पर दें ध्यान

'रोजगार के सवाल का समाधान' शीर्षक आलेख में संजय गुप्त ने सरकार को अच्छी सलाह दी है कि शिक्षा को कौशल विकास से जोड़कर छात्रों को हुनरमंद बनाया जाए ताकि वह जब शिक्षण संस्थानों से निकलें तो उन्हें रोजगार के लिए दर-दर नहीं भटकना पड़े। याद रहे, आज हर क्षेत्र में हुनरमंद युवाओं की ही मांग है। आज के छात्रों को कार्य क्षेत्र में प्रवेश करते समय अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रोजगार योग्यता कौशल को परिभाषित करने, मापने और निर्माण करने के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रोजगार कौशल वे योग्यताएं हैं, जो अकादमिक ज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञता से परे हैं। वे मूलभूत कौशल हैं, जो व्यक्तियों को कार्यस्थल में प्रभावी ढंग से संलग्न होने, बदलते वातावरण के अनुकूल होने और सहकर्मियों व ग्राहकों के साथ सकारात्मक रूप से बातचीत करने में सक्षम बनाते हैं। रोजगार कौशल में संचार, टीम वर्क, समस्या-समाधान, नैतिकता, व्यावसायिकता और संसाधनों के प्रबंधन सहित कई तरह की क्षमताएं शामिल हैं। छात्रों के लिए शैक्षणिक ज्ञान और रोजगार कौशल का मिश्रण विकसित करना बहुत जरूरी है। बेरोजगारी तब पैदा होती है, जब कामगारों के कौशल और बाजार में नौकरियों की उपलब्धता के बीच कोई मेल नहीं होता।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

संपादकीय जागरण

कष्ट सहने पर ही अनुभव होता है

विषाक्त वातावरण का नतीजा

अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला एक बेहद गंभीर घटना है। वह बाल-बाल बचे, लेकिन उन्हें निशाना बनाने वाला जिस तरह उन पर गोलियां बरसाने में सक्षम रहा, वह सुरक्षा में गंभीर चूक का नतीजा है। यह इससे स्पष्ट होता है कि हमलावर की गतिविधि के बारे में ट्रंप की रैली में आए लोगों ने सुरक्षाकर्मियों को बताया भी था, लेकिन उन्होंने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। चूंकि हमलावर मारा गया है इसलिए यह जानना कठिन हो सकता है कि ट्रंप को निशाना बनाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था, लेकिन इससे इन्कार नहीं कि यह घटना उस विषाक्त राजनीतिक वातावरण का परिणाम जान पड़ती है जो अमेरिका में पिछले कुछ समय से व्याप्त है। चिंता की बात यह है कि यह विषाक्त राजनीतिक वातावरण दिन-प्रतिदिन गहराता जा रहा है। अमेरिका इस समय राजनीतिक और वैचारिक रूप से इतना अधिक विभाजित है कि उसका दुष्प्रभाव पूरे समाज पर पड़ रहा है। किसी भी लोकतंत्र के लिए यह स्थिति ठीक नहीं, लेकिन इसमें संदेह है कि अमेरिका में वैचारिक विभाजन थमेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपतियों और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर हमले का एक इतिहास रहा है। इस हमले में कई नेताओं की जान भी जा चुकी है। अमेरिका में सार्वजनिक स्थानों में गोलीबारी की घटनाएं नई नहीं हैं। ये घटनाएं अमेरिका में व्याप्त बंदूक संस्कृति का नतीजा हैं। इस बंदूक संस्कृति को लेकर विभिन्न स्तरों पर चिंता जताई जा चुकी है, लेकिन कोई भी उस पर रोक लगाने के लिए तैयार नहीं। यह संस्कृति एक तरह से विश्व में सबसे घातक आंतरिक आतंक का पर्याय बन चुकी है। वैसे तो अमेरिका दुनिया भर को उपदेश देता रहता है, लेकिन वह यह देखने-समझने को तैयार नहीं कि स्वयं उसके अपने यहां क्या स्थिति है। डोनाल्ड ट्रंप पर एक ऐसे समय हमला हुआ है जब राष्ट्रपति पद के लिए उनकी दावेदारी पर मुहर लगने वाली है। इसके भरे-पूरे आसार हैं कि इस हमले के बाद ट्रंप को सहानुभूति का लाभ मिलेगा। इससे वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन की कठिनाई बढ़ सकती है। इसलिए और भी, क्योंकि उन पर पहले ही यह दबाव है कि वह अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पीछे हट जाएं। चूंकि अमेरिका विश्व का सबसे सशक्त लोकतंत्र है और वैश्विक राजनीति को कहीं गहराई से प्रभावित करता है इसलिए यह स्वाभाविक है कि भारत समेत दुनिया भर के नेताओं ने ट्रंप पर हमले की निंदा करते हुए चिंता जताई है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि जैसा विषैला राजनीतिक वातावरण अमेरिका में है वैसा दुनिया के अन्य देशों में भी बन रहा है। दुर्भाग्य से इनमें भारत भी है। राजनीतिक विरोध और असहमति का भाव जिस तरह शत्रुता में परिवर्तित होती जा रही है वह शुभ संकेत नहीं। उचित यह होगा कि अपने देश के नेता यह समझें कि जब राजनीतिक मतभेद एक-दूसरे के प्रति विद्वेष में बदल जाते हैं तो इसके कैसे नतीजे होते हैं।

पुराने वाहनों की हो जांच

परिवहन विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाया तो उसमें 45 प्रतिशत से अधिक बसें नियमों के मानक पर फेल मिलीं। फिटनेस प्रमाण पत्र अपडेट न होने, बिना परमिट के बस चलाने समेत अन्य नियमों के उल्लंघन पर 252 बसों पर 47 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया। 26 बसें जब्त कर ली गईं। चिंता की बात है कि प्रदूषण के मानक पर 72 बसें फेल थीं। फिटनेस फेल बसों को चलाना न सिर्फ मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिहाज से भी खतरनाक है। आए दिन इसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। परिवहन विभाग को इसी तरह ट्रक, हाइवा, डंफर व अन्य निजी वाहनों की जांच के लिए अभियान चलाना चाहिए। टैक्सी के तौर पर चलने वाले वाहनों की भी रैंडम जांच की जानी चाहिए। प्रदेश में हर दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। सामान्यतः तो अनियंत्रित रफ्तार हादसों का प्रमुख कारण बताया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं वाहनों का फिट नहीं होना भी कारण बनता है। सड़क पर दौड़ते ट्रक व अन्य वाहन धुआं उलगते हैं, जो प्रदूषण के लिए खतरनाक है। जिस तरह राजधानी पटना में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सीसी कैमरों से नजर रखी जाती है। नियमों के उल्लंघन पर वाहन चालक को उसके मोबाइल पर चालान पहुंच जाता है, उसी तरह धुआं उगलने वाले वाहनों को भी चिह्नित करने के लिए तकनीक या अन्य व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए। फिटनेस में फेल वाहन आमजन व पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक हैं। जिस तरह बसों को लेकर प्रदेशस्तरीय अभियान चलाया गया है, वैसे ही दूसरे बड़े वाहनों की औचक जांच के लिए भी अभियान चलाया जाना चाहिए।

> बसों की तरह प्रदेश में चल रहे ट्रक, हाइवा समेत अन्य निजी वाहनों के लिए भी औचक जांच अभियान की जरूरत है।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या विभिन्न राज्यों में विधानसभा उपचुनावों के नतीजे भाजपा के लिए चिंता का विषय है?

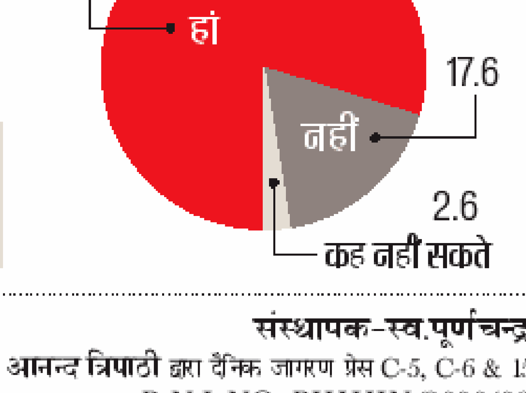

आज का सवाल
क्या हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राजनीतिक रूप से और मजबूत होकर उभरेंगे?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

संसद की गरिमा पर संकट

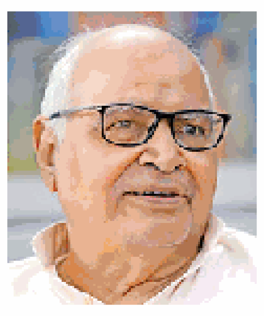

हृदयनारायण दीक्षित

संसद हुल्लड़ की जगह नहीं, बल्कि लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। वहां लगातार अव्यवस्था का बढ़ना राष्ट्रीय चिंता का विषय है

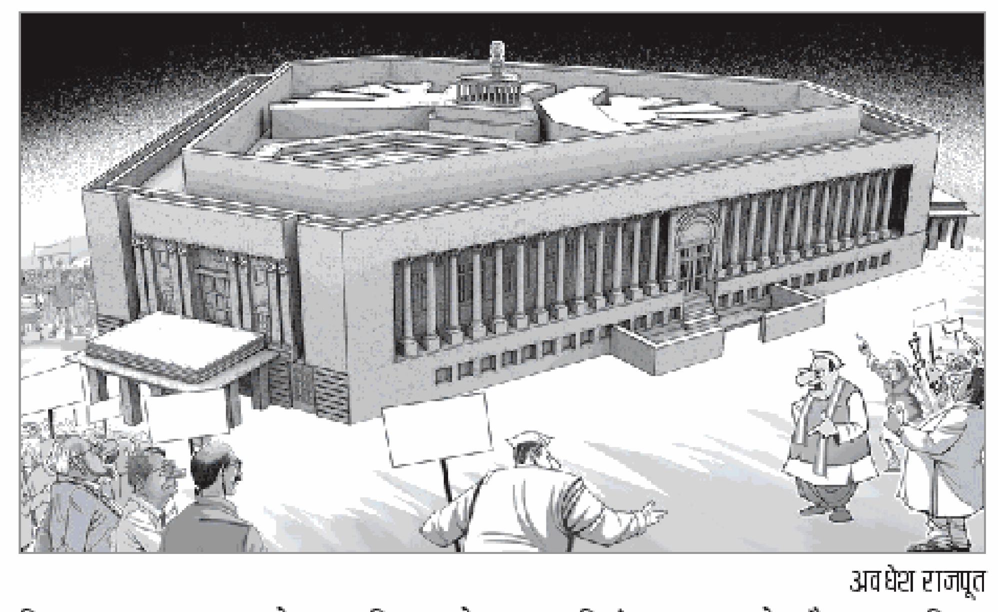

अवधेश राजपूत

संसद राजनीतिक कलह का मंच नहीं है, लेकिन काफी समय से संसदीय मर्यादा का जबरदस्त ह्रास हुआ है। अध्यक्ष का आसन सर्वोपरि होता है। संविधान की दुहाई सब देते हैं, लेकिन पीठासीन अधिकारी के निर्देशों की प्रायः धज्जियां उड़ाई जाती हैं। 18वीं लोकसभा के शपथ ग्रहण के दौरान कुछ सदस्यों ने संवैधानिक शपथ के साथ अपने वाक्य भी जोड़े। यहां न मर्यादा बची है और न ही संयम एवं अनुशासन। संसदीय व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष का पद और दायित्व सम्माननीय है, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा। उनके वक्तव्य से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। अध्यक्ष ने आपत्तिजनक अंश कार्यवाही से निकाल दिए हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष वही बातें दोहरा कर फिर से जोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। वैसे अब कार्यवाही से किसी अंश को निकाले जाने का कोई लाभ नहीं होता। संसद की कार्यवाही का सजीव प्रसारण होता है। इसलिए सभी शब्द बोले जाते समय ही सार्वजनिक जानकारी में आ जाते हैं।

भारत के लोग संविधान और संसद के प्रति आदरभाव रखते हैं। भारतीय संसद की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा रही है। अनेक सदस्य संसद के लिए पवित्र सदन, आदरणीय सदन या आगस्ट हाउस कहते हैं। संसद सदस्यों पर विधि निर्माण और संविधान संशोधन की जिम्मेदारी है। आश्चर्य है कि अनेक सदस्य कार्यवाही में बाधा डालते हैं। नियमावली की भी उपेक्षा करते हैं। इससे आहत पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने सदन की नियमावली को ही जला देने की बात कही थी। विधायी संस्थाओं में विधि और नियम का उल्लंघन साधारण घटना नहीं है। सदनों में कार्यवाही की गुणवत्ता की चिंता पुरानी है। ब्रिटिश राज में गठित केंद्रीय विधानसभा के समय (1921) अध्यक्ष फ्रेडरिक वाइट की अध्यक्षता में पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन शिमला में हुआ था। तब से हर साल पीठासीन अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन होते हैं। लोकसभा के प्रकाशन 'संसदीय पद्धति और प्रक्रिया' के अनुसार सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि शासन की संसदीय प्रणाली का समुचित विकास हो। सदस्यों के संयम और आचरण भी महत्वपूर्ण हैं।

संप्रति, संसदीय कार्यवाही निस्तेज हो रही है। संसदीय गतिरोध एवं अव्यवस्था ने निराश किया है। माननीयों के सम्यक आचरण पर जनता की निगाह रहती है। सांसदों के लिए कोई निश्चित आचार संहिता नहीं है। अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने का मुद्दा बार-बार चर्चा में आता है। मई 1992 में गुजरात में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था। सुझाव आया था कि अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने पर विचार के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया जाए। इसके अनुसरण में 23 और 24 सितंबर, 1992 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पीठासीन अधिकारियों, सदनों के दलीय नेताओं, संसदीय कार्य मंत्रियों और सांसदों आदि की भागीदारी में सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में गंभीर विचार विमर्श के बाद संसदीय परंपराओं और नियमों के आधार पर आचार संहिता का एक प्रारूप तैयार किया गया और उसे संसद तथा विधानमंडलों में 'अनुशासन तथा शिष्टाचार' शीर्षक पत्र में शामिल किया गया। इसे लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित किया गया। सम्मेलन में सदस्यों के दायित्व और कर्तव्य के लिए सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया। सुझाव दिया गया कि सभी राजनीतिक दल अपने जनप्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता तैयार करें। अनुपालन सुनिश्चित करें। यह काम राजनीतिक दलों को करना था। दलतंत्र ने उसकी उपेक्षा की। लोकसभा के स्वर्ण जयंती सत्र के अंतर्गत 26 अगस्त, 1997 से एक सितंबर, 1997 के दौरान यह विषय फिर विमर्श के लिए सामने आया। सभा ने एकमत से संकल्प पारित किया। संकल्प के अनुसार, 'सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों, व्यवस्थित कार्य संचालन संबंधी पीठासीन अधिकारियों के निर्देशों के गरिमापूर्ण अनुपालन द्वारा संसद की प्रतिष्ठा का परिरक्षण और संवर्धन किया जाए।' संकल्प बहुत अच्छा था, लेकिन परिणाम शून्य रहा। संकल्प में अन्य बातों के अलावा प्रश्न काल की महत्ता और नारेबाजी पर रोक तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण में व्यवधान न करना भी शामिल था। 2001 में नियमों में संशोधन हुआ कि अध्यक्ष के आसन के सामने नारेबाजी करने वाले स्वतः निलंबित होंगे। निलंबन भी थोक के भाव हुए, मगर कोई लाभ नहीं हुआ।

इसी क्रम में 13वीं लोकसभा के दौरान अध्यक्ष ने 16 मई, 2000 को लोकसभा में 15 सदस्यीय आचार समिति का गठन किया था। समिति को सदस्यों की नैतिकता और आचरण पर ध्यान रखना, सदस्य के संसदीय व्यवहार से संबंधित अनैतिक आचरण की शिकायत की जांच करना था। इसने पहला प्रतिवेदन 31 अगस्त, 2001 को प्रस्तुत किया। इसे 16 मई, 2002 को सभा ने स्वीकृत कर दिया। व्यवस्था, अनुशासन और संयम और वाक् संयम जैसे सामान्य विषयों पर लगातार बैठकें चलती रहीं, लेकिन ऐसे सम्मेलनों और बैठकों के भी अपेक्षित परिणाम नहीं आए।

सदनों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण काफी लोकप्रिय हुआ है। उम्मीद की जाती थी कि सदन के भीतर अपशब्द बोलने, नियम तोड़ने, अध्यक्ष की बात न मानने जैसे व्यवहार को आम जनता देखेगी और अपने जनप्रतिनिधि के अनुचित आचरण का संज्ञान लेगी। यह संभावना गलत निकली। सदनों में हंगामा करने वाले सदस्यों के क्षेत्र में निर्वाचकगण हुल्लड़ देखकर संभवतः दुखी नहीं होते। संसद हुल्लड़ की जगह नहीं है। लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। जनप्रतिनिधि सदनों में अव्यवस्था का लगातार बढ़ना राष्ट्रीय चिंता का विषय है। बेशक जनप्रतिनिधि जनता से चुने जाते हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक दल ही उम्मीदवार बनाते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों पर दलों का नियंत्रण रहता है। संसदीय समिति ने ठीक ही सिफारिश की थी कि राजनीतिक दल अपने-अपने प्रतिनिधियों के आचरण और व्यवहार पर ध्यान दें। संसद के सभी दलों के संसदीय पदाधिकारी परस्पर संवाद बनाएं। संसद में मर्यादा बनाए रखने के विषय पर संसद का विशेष सत्र आहूत करने पर विचार करें। भारतीय संसद विश्व की सभी जनप्रतिनिधि संस्थाओं से बड़ी है। पवित्र सदन में संवाद के स्थान पर अव्यवस्था उचित नहीं।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

आइएनडीआइए के जटिल समीकरण

राज कुमार सिंह

लोकसभा चुनाव के बाद से संकेत मिलने लगे हैं कि कांग्रेस और आप दिल्ली विधानसभा चुनाव अलग-अलग लड़ेंगी

आम चुनाव में प्रभावी नहीं रहा कांग्रेस- आप गठजोड़ ● फाइल

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रिश्ते लोकसभा चुनाव के बाद फिर बदल रहे हैं। आइएनडीआइए में शामिल इन दोनों दलों ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात और गोवा में लोकसभा चुनाव मिल कर लड़ा था, पर परिणाम अपेक्षित नहीं आए। चंडीगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी की जीत के अलावा दोनों दलों की दोस्ती कहीं करिश्मा नहीं दिखा सकी। चार जून को लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही आप की ओर से संकेत आने लगे थे कि अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव दोनों दल अलग-अलग लड़ सकते हैं। अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दो टूक कह दिया है कि दोनों दलों में गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था, जो विधानसभा चुनावों में संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने हरियाणा में भी गठबंधन से स्पष्ट इन्कार कर दिया, जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आप के लिए कुरुक्षेत्र सीट छोड़ी थी।

हरियाणा में नौ लोकसभा सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस अप्रत्याशित रूप से पांच सीटें जीत गई। ऐसा मानने वालों की कमी नहीं कि अगर कुरुक्षेत्र सीट आप को नहीं दी गई होती तो शायद कांग्रेस उसे भी जीत लेती। गठबंधन कमाल तो गुजरात में भी नहीं कर पाया, जहां कांग्रेस ने लंबे समय तक पार्टी के लिए चाणक्य की भूमिका निभाने वाले अहमद पटेल की भरूच के साथ ही भावनगर लोकसभा सीट भी आप को दे दी थी, लेकिन सबसे निराशाजनक परिणाम दिल्ली ने दिए। वर्ष 2017 में लगातार तीसरी बार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा चुनाव में जबरदस्त बहुमत से आप की सरकार बनी, लेकिन लोकसभा चुनाव में आप का कभी खाता नहीं खुला। आप के उभार का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है, लेकिन दोनों ने सोचा कि शायद मिल कर लोकसभा चुनाव में भाजपा को रोका जा सकता है। भाजपा ने सात में से छह सीटों पर उम्मीदवार बदले, तो लगा भी कि शायद पार्टी आशंकित है, लेकिन परिणाम फिर शत-प्रतिशत रहा। दिल्ली में एक भी सीट पर ऐसा नजदीकी मुकाबला नहीं हुआ कि लगता बाजी पलट भी सकती थी। ऐसा क्यों? उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम के मद्देनजर देखें तो लगता है कि दोनों ही न तो दिल से मिल कर चुनाव लड़ पाए और न ही अपने वोट एक-दूसरे को ट्रांसफर करा पाए। आप के साथ गठबंधन के विरोध में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली समेत कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस भी छोड़ गए। दिल्ली के संदर्भ में एक कोण और भी है। यहां आप की लगातार तीसरी सरकार है। इसलिए उसके विरुद्ध भी सत्ता विरोधी भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। तब क्या कांग्रेस-आप गठबंधन के चलते सत्ता विरोधी वोट बिना विभाजित हुए भाजपा के लिए मददगार साबित हुए? इस सवाल का सटीक उत्तर संभव नहीं, लेकिन पंजाब के लोकसभा चुनाव परिणाम इसी ओर संकेत करते हैं।

दिल्ली की तरह पंजाब की सत्ता भी आप ने कांग्रेस से छीनी। फर्क इतना रहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ जैसे प्रमुख नेताओं के पार्टी छोड़ जाने के बावजूद कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल बनने में सफल रही। सत्ता विरोधी वोटों का विभाजन रोकने के मकसद से दोनों दल पंजाब में अलग-अलग चुनाव लड़े और प्रदर्शन अच्छा रहा। लोकसभा चुनाव से पहले आप के एकमात्र सांसद सुशील कुमार रिंकू तथा कांग्रेस के दो सांसद परनीत कौर एवं रवनीत सिंह बिट्टू भी भाजपा में शामिल हो गए। फिर भी पिछली बार आठ लोकसभा सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार सात और मात्र एक सीट जीतने वाली आप तीन सीटें जीतने में सफल रहीं। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस और आप के अलग-अलग लड़ने की रणनीति ने पंजाब में भाजपा का खाता नहीं खुलने दिया।

अब कांग्रेस-आप गठबंधन टूटने से संभावित परिदृश्य की बात करते हैं। हरियाणा में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछली बार 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा बहुमत के आंकड़े से छह सीटें पीछे रह गई थी और उसे 10 विधायकों वाली जजपा से गठबंधन कर दुष्यंत चौटाला को उपमुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई कांग्रेस ने उसी साल हुए विधानसभा चुनावों में 31 सीटों के साथ चौंकाने वाला प्रदर्शन किया था। अब पांच लोकसभा सीटें जीतने से उत्साहित कांग्रेस विधानसभा में किसी के साथ सीटें नहीं बांटना चाहती। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह अन्य दलों के नेताओं को शामिल कर रहे हैं, उससे कांग्रेस में ही टिकट वितरण बड़ी चुनौती साबित होगा, पर क्या बहुकोणीय मुकाबला होने पर पिछले चुनाव जैसे नतीजों की आशंका नहीं रहेगी? शायद दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस-आप के अलग-अलग चुनाव लड़ने से अलग-अलग परिदृश्य भी होगा, क्योंकि दोनों राज्यों की चुनौतियां भी अलग हैं। दिल्ली में सत्ता विरोधी मतों का विभाजन करना है, जबकि हरियाणा में वही विभाजन रोकना है। हां, आप को हरियाणा में जो भी वोट मिलेंगे, वे होंगे कांग्रेस के ही संभावित वोट। इसलिए उसकी मौजूदगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हुए भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ ही पहुंचाएगी, जैसे कि गुजरात और गोआ विधानसभा चुनावों में हुआ था। वैसे हरियाणा में आप की जो जमीनी हालत है, दिल्ली में कांग्रेस उससे तो ज्यादा ही मजबूत है। इसलिए सत्ता विरोधी वोटों में हिस्सा बांट कर वह भाजपा को नुकसान और आप को फायदा पहुंचा सकती है। यानी राज्य-दर-राज्य विपक्ष को अलग चुनावी रणनीति की जरूरत होगी। जाहिर है, ऐसा जटिल संतुलन साधते हुए राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी आइएनडीआइए की एकजुटता और आक्रामकता को बनाए रखना विपक्ष के लिए बड़ी और कड़ी परीक्षा साबित होने जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में भी विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

शब्दों का प्रभाव

शब्दों को हमारे विचारों की मुद्रा कहा गया है। शब्दों में अतुलनीय शक्ति होती है। इनका अपना कोई आकार नहीं होता। फिर भी मनुष्य के मन पर शब्दों का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। शब्द हमारे मानसिक पटल का दर्पण माने गए हैं। जिस प्रकार एक वाद्य यंत्र की पहचान उसके स्वर से होती है, ठीक उसी तरह व्यक्ति की पहचान वाणी के माध्यम से बोले गए शब्दों द्वारा होती है।

शब्दों के प्रयोग में मनुष्य के आचरण की शुचिता झलकती है। शब्द अदृश्य होते हुए भी बड़ी सशक्तता के साथ श्रोता को प्रभावित करते हैं। शब्दों में ही मनुष्य के पारिवारिक, सामाजिक संबंधों का निर्माण तथा विध्वंस निहित है। स्नेहिल शब्दों का प्रभाव औषधि के समान कल्याणकारी होता है। जिस प्रकार औषधि रोगी व्यक्ति को शांति प्रदान करती है उसी प्रकार शालीनता से प्रयोग किए गए शब्द सुनने वाले के मन में शांति और उल्लास का संचार करते हैं। क्रोधित अवस्था में बोले गए शब्द विष के समान मनुष्य के अंतःकरण को उद्विग्न बना देते हैं। वाणी द्वारा शब्दों का प्रयोग करते हुए विवेक का प्रयोग परम आवश्यक है। विवेकहीन होकर प्रयोग किए गए शब्द मधुर संबंधों को भी नष्ट कर देते हैं।

मनुष्य के मन में उतरना तथा मन से उतरना शब्दों के प्रयोग पर ही निर्भर करता है। कटु एवं असभ्य शब्दों का प्रयोग शस्त्र के घाव से भी भयंकर होता है। शस्त्र का घाव तो कुछ समय पश्चात भर जाता है, परंतु शब्दों द्वारा घायल किया गया मनुष्य का मानसिक पटल जीवन भर नहीं भरता। शब्दों का प्रभाव बड़ा त्वरित और प्रबल होता है। शब्द विष भी हैं और अमृत भी। शब्दों के सांचे में ही मानवीय संबंधों का ताना-बाना निर्मित होता है। माधुर्य एवं सौम्यता से परिपूर्ण शब्दावली में शत्रु को भी मित्र बनाने की क्षमता होती है। शब्द वरदान भी बन जाते हैं और अभिशाप भी। शब्दों से ही मनुष्य का व्यक्तित्व परिलक्षित होता है।

आचार्य दीप चंद भारद्वाज

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

समाज की अखंडता पर हमला

डा. ऋतु सारस्वत ने 'मतांतरण की खतरनाक चुनौती' शीर्षक से जो लेख लिखा है, वह आज के समय की एक गंभीर समस्या को सामने लाता है। मतांतरण सिर्फ एक धार्मिक परिवर्तन नहीं है, यह समाज की जड़ों को हिला देने वाली प्रक्रिया है। यह सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाता है, जो हमारे देश की पहचान है। हमारे देश की विशेषता इसकी विविधता में है। विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का संगम हमारे समाज को मजबूत बनाता है। मतांतरण के कारण यह संगम टूटता है और समाज में विभाजन की स्थिति पैदा होती है। यह सिर्फ धार्मिक असंतुलन नहीं, बल्कि सामाजिक असंतुलन भी लाता है। यह ध्यान देना जरूरी है कि कई बार मतांतरण के पीछे आर्थिक और राजनीतिक कारण भी होते हैं। कुछ संगठन अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बहकाते हैं, जो कि समाज के लिए घातक है। हमें इस प्रकार के प्रयासों से सावधान रहना चाहिए और इन्हें रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। शिक्षा और जागरूकता ही इसका सबसे प्रभावी समाधान है। अगर लोग अपने धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक होंगे, तो वे किसी भी प्रकार के दबाव या प्रलोभन में नहीं आएंगे। समाज में हर व्यक्ति को अपने धर्म और संस्कृति का सही ज्ञान होना चाहिए, ताकि वे अपने मूल्यों को समझ सकें और उन्हें संरक्षित कर सकें। भारत की धार्मिक विविधता उसकी ताकत है, और इसे बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें सतर्क और जागरूक रहना होगा। धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता को बनाए रखने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज को इस प्रकार की चुनौतियों से बचाएं और उसकी समृद्धि और शांति को बनाए रखें।

awanishg30@gmail.com

बुद्ध व महावीर की आवश्यकता

एक इंच के फासले से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान बच गई। अमेरिका जैसे देश में इतने ताकतवर नेता असुरक्षित हैं तो अन्य लोगों की बिसात क्या है। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। यह वहशीपन से ज्यादा कुछ नहीं है। विश्व में हिंसा व युद्ध में ना जाने कितने लोग खेत रहे, लेकिन परिणाम क्या मिला? विश्व को बुद्ध व महावीर के अहिंसा के मार्ग पर ही आना पड़ा। आज भी उनके सिद्धांतों पर अमल की आवश्यकता है। अब किसी देश में इतनी ताकत नहीं है कि वह किसी देश को गुलाम बना लें, यह व्यक्तियों के लिए भी लागू है। इसके बावजूद हिंसा समझ के परे है। एफबीआइ के बयान में कहा गया है कि ट्रंप पर गोली चलाने वाले हमलावर की पहचान 20 वर्ष के थामस मैथ्यू क्रुक्स के तौर पर हुई है। क्रुक्स पेंसिल्वेनिया के बेथल पार्क का निवासी था। एफबीआइ के बयान में कहा गया है कि रैली स्थल क्रुक्स बटलर से उसका निवास 70 किलोमीटर दूर था। शीर्ष जांच एजेंसी ने कहा कि ट्रंप पर हमले की विस्तृत जांच जारी है। उसने इस संबंध में लोगों से जानकारी देने की भी अपील की है। जांच एजेंसी ने कहा कि लोगों के पास अगर कोई फोटो या आनलाइन वीडियो है तो वो उससे ये साझा कर सकते हैं। हमले का उद्देश्य क्या था, ये अभी तक साफ नहीं है। यह घटना बेहद चिंताजनक है।

प्रसिद्ध यादव, बाबूचक, पटना

कौशल व उपलब्ध रोजगार में हो मेल

'रोजगार के सवाल का समाधान' शीर्षक आलेख में संजय गुप्त ने सरकार को अच्छी सलाह दी है कि शिक्षा को कौशल विकास से जोड़कर छात्रों को हुनरमंद बनाया जाए, ताकि वह जब शिक्षण संस्थानों से निकलें तो उन्हें रोजगार के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़े। याद रहे आज हर क्षेत्र में हुनरमंद युवाओं की ही मांग है। आज के छात्रों को कार्यबल में प्रवेश करते समय अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में रोजगार योग्यता कौशल को परिभाषित करने, मापने और निर्माण करने के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रोजगार कौशल वे योग्यताएं हैं, जो अकादमिक ज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञता के परे हैं। यह मूलभूत कौशल हैं, जो व्यक्तियों को कार्यस्थल में प्रभावी ढंग से संलग्न होने, बदलते वातावरण के अनुकूल होने और सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ सकारात्मक रूप से बातचीत करने में सक्षम बनाते हैं। रोजगार कौशल में संचार, टीम वर्क, समस्या-समाधान, नैतिकता, व्यावसायिकता और संसाधनों के प्रबंधन सहित कई तरह की क्षमताएं शामिल हैं। छात्रों के लिए शैक्षणिक ज्ञान और रोजगार कौशल, जैसे संचार, समस्या-समाधान और टीम वर्क का मिश्रण विकसित करना बहुत जरूरी है। बेरोजगारी तब पैदा होती है, जब कामगारों के कौशल और बाजार में नौकरियों की उपलब्धता के बीच कोई मेल नहीं होता। अधिकतर लोगों को उनके कौशल के अनुरूप नौकरी नहीं मिलती।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

X पोस्ट

अंबानी के घर शादी में किसी के भी जाने पर एतराज क्यों? जिसको भी बुलावा आएगा वह जाएगा ही और जाना भी चाहिए। अंबानी या अदाणी देश के दुश्मन तो नहीं? रही बात राहुल गांधी की तो उनकी हर कांग्रेस सरकार इन उद्यमियों के साथ चहलकदमी करती नजर आई, फिर न जाने का दिखावा करने की जरूरत क्यों?

अभिषेक उपाध्याय@upadhyayaabhi

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप बाल-बाल बचे। भारत में जब किसी सिरफिरे ने पीएम के काफिले पर चप्पल उछाल दी तो एक गैर-जिम्मेदार नेता ने कहा कि लोगों ने डरना बंद कर दिया है। एक सांसद को सुरक्षा बल की एक महिला सिपाही ने थप्पड़ मार दिया तो लोगों ने कहा कि वह चार साल पुराने एक ट्वीट से नाराज थी, जो असल में डिलीट भी कर दिया गया था।

रंगनाथ सिंह@rangnathsingh_

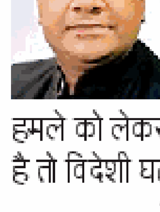

जो हमला टेलीविजन कैमरों के सामने लाइव प्रसारण में हुआ, उसे अमेरिकी मीडिया एक लाइन में स्पष्ट रूप से नहीं बता सका। सोचिए, जब अपनी धरती पर अपने ही पूर्व राष्ट्रपति पर हमले को लेकर अमेरिकी मीडिया इस कदर असंतुलित है तो विदेशी घटनाओं पर उसका रुख कैसा रहता होगा।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

जनपथ

भारत माता के लिए हो जवान बलिदान,
पर अपनी मां हो रही रो-रोकर हलकान।
रो-रोकर हलकान पुत्र को पाले-पोसे,
फिर निज माथा पीट स्वयं की किस्मत कोसे।
रहे बना बैलेंस बीच पत्नी अरु माता,
तो होंगी संतुष्ट हमारी भारत माता।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्मादन हेतु पी.आर बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 94

प्रवाह
महोत्सव विश्वास का 75
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

जीवन की चुनौतियों से निपटने की हमारी क्षमता हमारे चरित्र से निर्धारित होती है। -लेस ब्राउन

डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को अलग मोड़ पर ला खड़ा किया है। अंदरूनी राजनीति के तनाव और वैश्विक प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि असहमति और हिंसा का मसला कितने रूप अख्तियार कर सकता है।

हमला और सियासत

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले ने न केवल अमेरिकी राजनीति में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चिंताओं को तो बढ़ाया ही है, इस हमले से अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी अलग मोड़ पर पहुंच गए हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन पेंसिल्वेनिया रैली में एक बीस वर्षीय बंदूकधारी द्वारा पूर्व राष्ट्रपति की हत्या के प्रयास के साथ अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के खतरे ने एक बार फिर सिर उठाया है। इससे पहले भी 1865 में 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और 1963 में 35वें अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी सहित चार राष्ट्रपतियों की पद पर रहते हुए हत्या कर दी गई, और रोनाल्ड रीगन और थियोडोर रूजवेल्ट हत्या के प्रयासों से बच गए। हालांकि ट्रंप पर हुआ ताजा हमला अमेरिका में राजनीतिक विभाजन के बदलते रूप को ही दर्शाता है। ऐसे में, अगर रूस इस हमले के पीछे बाइडन प्रशासन को सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन उसके द्वारा निर्मित माहौल को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो इसे पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। एक तरफ बाइडन अपनी चुनावी रैलियों में ट्रंप को किसी भी तरह से रोकने का आह्वान करते दिखे हैं, तो दूसरी तरफ, अमेरिकी मीडिया का एक बड़ा वर्ग भी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को खलनायक की तरह पेश कर रहा है, वह इस हमले की प्रत्यक्ष वजह बेशक न हो, लेकिन यह हमला उसके द्वारा किए जा रहे आम लोगों, खासकर युवाओं के 'ब्रेन-वॉश' का परिणाम भी हो सकता है। इस हमले की एक वजह अमेरिका में बढ़ते 'गन कल्चर' को भी बताया जा रहा है, जिसकी पुष्टि आंकड़े भी करते हैं। *यूएस टुडे* की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में वर्तमान वर्ष के पहले चार महीनों में करीब 55 लाख हथियार खरीदे गए। वहीं प्यू रिसर्च के अनुसार करीब एक-तिहाई अमेरिकी अपने घर पर हथियार रखते हैं। ट्रंप पर हुए हमले के बाद उठ रहे सवालों के बीच

ऐसी खबरें कि ट्रंप ने सहानुभूति की चाह में खुद ही यह हमला करवाया हो, तार्किक नहीं लगतीं, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए इसकी जरूरत हो, ऐसा नहीं दिखता। दरअसल, अमेरिका में राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो बाइडन बढ़ती उम्र के चलते गलतियां दोहरा रहे हैं, उससे खुद उनकी ही पार्टी के नेता असंतुष्ट हैं। ऐसे में, डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने की संभावनाएं पहले से ही प्रबल हैं, लेकिन अब उन पर हुआ यह हमला बाइडन के मुकाबिल उन्हें और मजबूत स्थिति में खड़ा करे, तो हैरत नहीं।

बेमेल गठबंधन की चुनौतियां

नेपाल में कम्युनिस्टों (चीन समर्थक) और नेपाली कांग्रेस (भारत समर्थक) की विरोधी विचारधाराओं वाली गठबंधन सरकार का अस्तित्व पूरी तरह से साझेदारों के आपसी विश्वास व संतुलित कूटनीतिक रणनीति के कार्यान्वयन और दो क्षेत्रीय दिग्गजों को नाराज करने से बचने पर निर्भर करेगा, जिसका अतीत में अभाव रहा है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो साधनों, नैतिकता और मूल्यों का पूरी तरह से अनादर कर अंत तक अड़े रहने के मैकियावैली सिद्धांत के अनुपालन की राजनेताओं की प्रवृत्ति नेपाल के निवर्तमान प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के मामले में सटीकता से दिखती है, जो नेपाली संसद में विश्वासमत हासिल करने के दौरान अपमानजनक ढंग से हारकर अपना पद गंवा बैठे हैं। प्रचंड को मात्र 63 वोट ही मिले, जबकि उनके खिलाफ नेपाली कांग्रेस और नेपाल (यूएमएल) के नए गठबंधन को कुल 194 वोट मिले। नए गठबंधन को राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी एवं जनता समाजवादी पार्टी जैसे छोटे दलों का भी समर्थन मिला। 275 सीटों वाले सदन में बहुमत के लिए मात्र 138 सीटें चाहिए। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के समक्ष ओली ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है।

केएस तोमर
राजनीतिक विश्लेषक

इस बीच अच्छी बात यह है कि सीपीएन-यूएमएल के विदेश मामलों के प्रमुख और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य डॉ. राजन भट्टाराई ने जोर देते हुए कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि नेपाल की प्रगति या नेपाली नागरिकों का कल्याण केवल भारत समर्थक रुख अपनाकर ही हासिल किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ओली नेपाल-भारत संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के इच्छुक हैं, ताकि आधुनिक युग की जरूरतों के साथ तालमेल बिठाया जा सके।

नेपाल में लोकतंत्र की नाजुक स्थिति के कारण निरंतर अस्थिरता सरकार की पहचान रही है, जो तेरह वर्षों के लोकतंत्र में 16 बार सत्ता परिवर्तन से स्पष्ट है, जिससे देश के आम लोगों के हितों पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ही है, देश आर्थिक संकट और ऋण देनदारियों, विशेष रूप से चीनी कर्ज के जाल में फंस गया है। नई सरकार का डेढ़ साल तक नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्री और कट्टर कम्युनिस्ट नेता ओली करेंगे, जिसके बाद समझौते के अनुसार, शेष कार्यकाल के लिए देउबा प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे।

ओली एवं देउबा की नई गठबंधन सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और यही चुनौतियां उनकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण होंगी, अन्यथा इसका नतीजा मध्यावधि चुनाव के रूप में सामने आ सकता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि कम्युनिस्टों (चीन समर्थक) और नेपाली कांग्रेस (भारत समर्थक) की विरोधी विचारधाराओं वाली नई सरकार को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती हो सकती है।

दूसरी बात, ओली और देउबा गठबंधन के समक्ष दो क्षेत्रीय शक्तियों यानी भारत और चीन से समान दूरी बनाए रखने की बाध्यता होगी, जिनके नेपाल के मामलों में भू-राजनीतिक और सामरिक हित जुड़े हैं। तीसरी बात, इससे पहले प्रधानमंत्री रहते हुए ओली ने भारत विरोधी कार्रवाइयों को बढ़ावा दिया था। उन्होंने एक नया नक्शा बनवाया था, जिसमें लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी सहित भारतीय क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। इससे भारत नाराज हो गया और नक्शे को खारिज करते हुए उसे संबंधों को खराब करने का प्रयास बताया था। अब, गठबंधन में प्रमुख भागीदार के रूप में देउबा की जिम्मेदारी होगी कि वह ओली को भारत विरोधी मानसिकता से निकलने के लिए मनाएं और दोनों देशों के सदियों पुराने संबंधों की रक्षा करें।

चौथी बात, प्रचंड के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सरकार ने हमेशा चीन के प्रति प्रतिबद्धता के संकेत दिए हैं। चीन नई सरकार से भी बेल्ट ऐंड रोड (बीआरआई) पहल पर आगे बढ़ने की उम्मीद करेगा, क्योंकि प्रचंड ने 12 मई, 2017 को दोनों देशों के बीच हुए हस्ताक्षरित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ओली सरकार को भारत की तरफ से किसी भी अड़चन से बचने के लिए इसे स्थगित रखने के लिए तार्किक कदम उठाना होगा। प्रचंड ने सितंबर, 2023 में बीजिंग की अपनी यात्रा के दौरान बीआरआई को गति देने के लिए नेपाल की प्रतिबद्धता दोहराई थी। अब ओली के लिए बीआरआई के संकल्प पर टिके रहना मुश्किल होगा, क्योंकि नेपाली कांग्रेस पूरी तरह से इसके खिलाफ है, इसलिए इस मामले में प्रगति की संभावना दूर की कौड़ी लगती है।

पांचवीं बात, भारत की अग्निपथ योजना से निपटना नई सरकार के लिए चुनौती होगी, जो अब तक की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। भारत ने 15 जून, 2022 को अग्निपथ योजना शुरू की थी, जिसे नेपाल में भी लागू किया गया था, लेकिन कुछ आपत्तियों की वजह से अब भी नेपाल ने कोई फैसला नहीं लिया है। जबकि फील्ड रिपोर्ट बताती है कि नेपाल में ऐसे बेरोजगार युवा हैं, जो अग्निवीर के रूप में भारतीय सेना में शामिल होने के इच्छुक हो सकते हैं, लेकिन पिछली दो सरकारों ने इसमें देरी की और तीसरी सरकार भी शायद उससे अलग नहीं होगी।

छठी बात, भारत के साथ नेपाल का सीमा विवाद है, जिसके समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है। नई सरकार एक नई रणनीति अपना सकती है, जिसमें भारतीय समकक्षों के साथ उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता करने और सीमा विवाद को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से सुलझाना शामिल है। तकनीकी और कूटनीतिक माध्यमों से सीमा विवाद के समाधान में तेजी लाने के लिए नेपाल-भारत संयुक्त सीमा आयोग को मजबूत करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अवैध गतिविधियों और अनधिकृत घुसपैठ को रोकने के लिए विवादित सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी बढ़ाना, दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। सातवीं बात, चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि की तरह नेपाल को भी अपनी 'ऋण नीति' में फंसा कर नेपाल को भारी कर्ज दिया है, जिसे चुकाने में सदियां लग सकती हैं।

अंत में, विवादित क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने और उपस्थिति का दावा करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण और सुधार के लिए एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। इन रणनीतियों को अपनाकर नेपाल की नई सरकार अग्निपथ योजना से उत्पन्न चुनौतियों और भारत के साथ चल रहे सीमा विवादों का संतुलित और प्रभावी तरीके से समाधान कर सकती है। लेकिन नए गठबंधन का अस्तित्व पूरी तरह से साझेदारों के आपसी विश्वास और संतुलित कूटनीतिक रणनीति के कार्यान्वयन तथा दो क्षेत्रीय दिग्गजों को नाराज करने से बचने पर निर्भर करेगा, जिसका अतीत में अभाव रहा है। edit@amarujala.com

जीवन धारा

जॉर्ज आई गुरजिएफ

इस समय युद्ध चल रहा है। यह क्या दर्शाता है? इसका अर्थ है कि लाखों सोए हुए लोग, लाखों दूसरे सोए हुए लोगों को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे जगे हुए होते, तो निस्संदेह ऐसा नहीं करते।

जानने के लिए जागना जरूरी है

मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा, जो आपके पूरे जीवन को समृद्ध बना देगी। यहां दो तरह के संघर्ष हैं : एक आंतरिक दुनिया का और दूसरा बाहरी दुनिया का संघर्ष। आपको इन दोनों दुनियाओं से इरादतन संपर्क बनाना होगा, तब आप तीसरी यानी आत्मा की दुनिया को समझ सकते हैं। व्यक्ति को जागृत होने के लिए सबसे पहले यह एहसास होना जरूरी कि वह नींद की अवस्था में है। और यह मालूम करने लिए कि वह वास्तव में नींद की अवस्था में है, उसे कुदरत की उन शक्तियों को पूरी तरह से पहचानना और समझना होगा, जो उसे नींद या सम्मोहन में रखने का काम करती हैं। यह सोचना मूर्खतापूर्ण है कि यह उसी मुखबिर से जानकारी लेकर किया जा सकता है, जो सम्मोहन के लिए प्रेरित करता है।

एक बात निश्चित है, कि मनुष्य की गुलामी बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य स्वेच्छापूर्वक गुलाम बनता जा रहा है। उसे जंजीरों से बांधने की जरूरत नहीं है। अब वह अपनी गुलामी से न सिर्फ प्यार, बल्कि उस पर गर्व भी करने लगा है। और यह गंभीर बात है, जो किसी के साथ हो सकती है।

आइए, हम मानव जीवन की कुछ घटनाएं लें, जैसे युद्ध। इस समय युद्ध चल रहा है। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि लाखों सोए हुए लोग, लाखों दूसरे सोए हुए लोगों को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे जगे हुए होते, निस्संदेह ऐसा नहीं करते। जो कुछ भी घटित होता है, वह इसी नींद के कारण होता है, तो आपको जानना होगा। जानने का अर्थ है सब कुछ जानना। सब कुछ न जानने का अर्थ है कुछ नहीं जानना। जानने के लिए बस थोड़ी-सी जानकारी होना जरूरी है। थोड़ा-सा जानने के लिए भी पहले बहुत कुछ जानना जरूरी है। मैं किसी ऐसी बात पर विश्वास करने के लिए नहीं कहता, जिसे आप स्वयं सत्यापित नहीं कर सकते। याद रखें कि आप यहां खुद से संघर्ष करने की जरूरत को समझकर आए हैं। इसलिए उन सभी का शुक्रिया अदा करें, जो आपको यह अवसर देते हैं। जो बात एक व्यक्ति के लिए संभव है, वह जनसमूह के लिए असंभव है। ज्ञान पूर्ण अध्ययन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, चाहे शुरुआती बिंदु कुछ भी हो। केवल व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि 'सीखना' कैसे है? हमारे सबसे निकट मनुष्य है; और हम सभी मनुष्यों में से अपने सबसे निकट हैं। इसलिए स्वयं के अध्ययन से शुरुआत करें; यह कहावत याद रखें 'स्वयं को जानो।' विचार करें कि हमारे समय की सुसंस्कृत मानवता युद्ध को छोड़कर किस पर पैसा खर्च करती है, सबसे ज्यादा कीमत किस पर मिलती है; सबसे बड़ी भीड़ कहां है? अगर हम इन सवालों के बारे में एक पल के लिए भी सोचें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मानवता, जैसी कि वह अभी है, जिस हित के साथ वह जीती है, वह उससे अलग कुछ पाने की उम्मीद नहीं कर सकती, जो उसके पास है। इच्छा दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है। भगवान से भी बड़ी।

भीड़ को ज्ञान न दें

सूत्र

आप अपने आसपास नजर दौड़ाएं। भीड़ न तो ज्ञान चाहती है और न ही उसे खोजती है। और भीड़ के नेता, अपने हित में हर नई और अज्ञात चीज के प्रति उसके डर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मानव जाति जिस गुलामी में है, वह इसी डर पर आधारित है। पर इसके कारण को समझने के लिए यह देखना काफी है कि लोग कैसे जीते हैं, उनके अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, उनकी इच्छाओं, जुनून और आकांक्षाओं का उद्देश्य क्या है।

दूसरा पहलू

जर्मनी से निर्वासित वालिद कबील जैसे कई लोगों का अनुभव है कि कनाडा में शरण मांगने वाले लोगों से बुरा बर्ताव होता है।

कनाडा में शरणार्थियों का स्वागत करतीं जेलें

जर्मनी से निर्वासित कर दिए जाने के डर से वालिद कबील किसी तरह एक जहाज में छिपते-छिपाते हुए वहां से भाग निकला। उसे डर था कि कहीं उसे वापस मोरक्को न भेज दिया जाए, जहां राजनीतिक कार्यकर्ता की उसकी छवि से सरकार परेशान थी। लेकिन रास्ते में ही उसे पकड़ कर कनाडा की सरकार के हवाले कर दिया गया। अब कबील के चौंकने की बारी थी। उसे वहां शरण चाहिए थी, लेकिन उसे एक प्रांतीय जेल में बंद कर दिया गया, जहां एक से एक खतरनाक कैदी थे।

ईयान ऑस्टिन

कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनका देश शरण मांगने वालों का स्वागत करता है, चाहे शरण मांगने वाले ऐसे लोगों पर उनके अपने देश में मुकदमे ही क्यों न चल रहे हों।

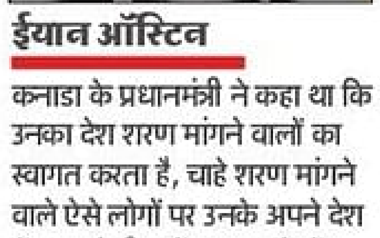

मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि कनाडा ज्यादातर अवैध प्रवासियों को जेल में रखता है। पिछले ही साल 29,455 लोगों ने कनाडा में शरण मांगी, लेकिन इनमें से 5,800 लोगों को प्रांतीय जेलों में रखा गया।

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन त्रूदो ने सोशल मीडिया पर कहा था कि उनका देश शरण मांगने वालों का स्वागत करता है, चाहे शरण मांगने वाले ऐसे लोगों पर उनके देश में मुकदमे ही क्यों न चल रहे हों। दूसरी तरफ कबील जैसे लोगों का अनुभव है कि कनाडा में शरण मांगने वाले लोगों से बुरा बर्ताव होता है और उन्हें जेलों में खतरनाक कैदियों के साथ रख दिया जाता है। हालांकि सरकारी अधिकारी इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि शरण मांगने वाले कुछ ही लोगों को जेल में रखा जाता है, क्योंकि उन्हें जन सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है या फिर उनके बारे में यह आशंका रहती है कि वे बिना बताए भाग सकते हैं। प्रवासन से जुड़े एक विशेषज्ञ का कहना है कि गैर दस्तावेजी प्रवासन पर अंकुश लगाने के लिए यह एक कारगर औजार है। बताया जाता है कि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की तरह कनाडा भी अवैध प्रवासियों से भर गया है और सरकार परेशान है। अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि देखकर राष्ट्रपति बाइडन ने दक्षिणी सीमा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। दूसरी तरफ कनाडा में बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि प्रवासियों को जेल में रखना अमूमन हमारा आखिरी कदम होता है।

लेकिन मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि कनाडा ज्यादातर अवैध प्रवासियों को जेल में रखता है, जबकि हर प्रवासी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं होता। पिछले ही साल 29,455 लोगों ने कनाडा में शरण मांगी, लेकिन इनमें से 5,800 लोगों को प्रांतीय जेलों में रखा गया। औसतन इन शरणार्थियों को 16.5 दिन तक जेल में रखा गया, जबकि इनमें से सात फीसदी शरणार्थियों को औसतन 99 दिन से भी अधिक अवधि के लिए जेल में रखा गया। सर्वेक्षण बताते हैं कि कनाडा के लोगों को शरणार्थियों से परेशानी नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि शरणार्थियों की भीड़ बढ़ने से देश में घरों की कीमत बेतहाशा बढ़ रही है।

©The New York Times 2024

आंकड़े

प्याज निर्यातक देश

प्याज की घरेलू मांग ज्यादा होने के बावजूद भारत प्याज निर्यात के मामले में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।

आंकड़े कुल वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी के हैं। | स्रोत : Comtrade

महर्षि शरभंग काफी वृद्ध हो गए, तो उन्हें लेने के लिए इंद्र अपना विमान लेकर गए। उन्होंने कहा कि मैं श्रीराम के दर्शन किए बिना देह त्याग नहीं करूंगा।

महर्षि शरभंग ने इंद्र को लौटाया

अंतर्यात्रा
संकलित

महर्षि शरभंग दक्षिण भारत के गौतम कुलोत्पन्न एक प्रसिद्ध महर्षि थे, जिनका उल्लेख *रामायण* में है। भगवान राम ने दंडकारण्य में विराध नामक राक्षस का वध करने के बाद लक्ष्मण से कहा कि अब हम महामुनि शरभंग के आश्रम पर चलें।

भगवान श्रीराम, लक्ष्मण और सीता महर्षि शरभंग के आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। इधर, उनसे पहले देवराज इंद्र स्वर्ग से अपना विमान लेकर महर्षि शरभंग के पास पहुंचे और कहा कि हे महामुनि आप हमारे साथ इस विमान में बैठकर ब्रह्मलोक में चलें। महर्षि ने इंद्र से कहा कि ब्रह्मलोक के प्रधान देवता प्रभु श्रीराम हमारे पास आ रहे हैं। उनके दर्शन किए बिना यह शरीर नहीं त्यागना चाहता। प्रभु श्रीराम जब उनके आश्रम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हे राम! इस वन में कभी-कभी ही आपके जैसे अतिथि आते हैं। उन्होंने कहा-

चितवत पंथ रहेउं दिनु राती।
अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती।।
नाथ सकल साधन मैं हीना।
कीन्ही कृपा जानि जनु दीना।।

महर्षि ने कहा कि अपना शरीर त्याग करने के पहले मैं आपके दर्शन करना चाहता था। इसलिए आपकी प्रतीक्षा में मैंने अब तक अपना शरीर नहीं त्यागा था। अब मैं इस नश्वर एवं जर्जर शरीर का परित्याग कर ब्रह्मलोक में जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अंत समय में जिसके सामने साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक पहुंच गए। उसका सौभाग्य पूछना ही क्या? इसके बाद महर्षि शरभंग ने योगाग्नि से अपनी देह त्याग दी।

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 01 फरवरी, 1956

बुनियादी शिक्षा पर आधारित हो राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप

राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप बुनियादी शिक्षा पर आधारित हो
केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री श्री श्रीमाली का भाषण
ईदगाह के प्रति आदर का भाव द्वेष फैलाने वालों की कड़ी निंदा
श्रीकृष्ण जन्मभूमि सहायक समिति के प्रस्ताव

केंद्रीय शिक्षा उपमंत्री डॉ. केएम श्रीमाली ने शिवपुरी में कहा कि भारत सरकार ने पूर्ण रूप से विचार-विमर्श करने के बाद तय किया है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप बुनियादी शिक्षा पर आधारित होना चाहिए।

जनगणना इसलिए जरूरी है

बेहतर और कल्याणकारी नीतियां बन सकें, इसके लिए आबादी की संरचना और आंकड़ों की सटीक जानकारी जरूरी है।

पत्रलेखा चटर्जी | मुद्दा

हम वर्ष 2024 का आधा पड़ाव पार कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में वापसी कर चुकी है। लेकिन हर दस वर्ष में होने वाली जनगणना को लेकर अब तक कोई बात नहीं की जा रही। अंतिम बार जनगणना 2011 में हुई थी।

भारत ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भी जनगणना करवाई थी, लेकिन 1981 से हर दस वर्ष में शुरू हुए जनगणना के क्रम को वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण स्थगित करना पड़ा। लेकिन, आश्चर्य की बात यह है कि चार साल बीत जाने के बावजूद हमारे पास अब भी जनगणना कराने के लिए समय नहीं है। बांग्लादेश और ब्राजील ने अपनी अंतिम जनगणना 2022 में संपन्न कराई थी। अमेरिका और चीन, तो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपनी जनगणना 2020 में ही करवा चुके हैं। जनगणना के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक देश के लोगों की संख्या और जनसांख्यिकीय

व सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं की जानकारियां बड़े स्तर पर जुटाई जाती हैं।

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन ऐंड डेवलपमेंट, केरल से संबंधित दो प्रतिष्ठित जनसांख्यिकीविद एस. इरुदया राजन और यूएस मिश्रा ने हाल ही में टिप्पणी की, कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत में जनसंख्या की गणना वास्तविक नहीं है। दरअसल, भारत की जनसंख्या के ज्यादातर अनुमान दशकों पुराने आंकड़ों पर आधारित हैं। भारत जब तक अपनी समुचित जनगणना नहीं करा लेता, तब तक हमारे पास सिर्फ अनुमान ही होंगे। जनगणना में देरी के पीछे जो भी कारण हों, लेकिन जनगणना के आंकड़ों की कमी एक गंभीर मसला है। यह न केवल शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए नुकसानदेह है, बल्कि जनगणना के आंकड़ों में देरी की वजह से कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी प्रभावित होता है। जैसा राजन और मिश्रा भी इंगित करते हैं कि 'सटीक जनसंख्या और जनसांख्यिकीय संरचना को जानना महत्वपूर्ण है, ताकि हम बेहतर नीतियों का मसौदा तैयार कर सकें।'

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के अंतर्गत देश के करीब 81.35 करोड़ लोगों को 31 दिसंबर, 2028 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। यह राशन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार दिया जा रहा है। सरकार के 2019 के बयान के आधार पर देश की 67 फीसदी आबादी यानी 80 करोड़ लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के हकदार हैं। स्वतंत्र शोधकर्ताओं का अनुमान है कि मौजूदा समय में करीब 92 करोड़ लोग इस दायरे में आने चाहिए। अद्यतन जनसांख्यिकी आंकड़े मिलने पर एनएफएसए को लाभ मिलेगा। यह बात उन अज्ञात लाभार्थियों पर भी लागू होती है, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वृद्धावस्था पेंशन के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता से वंचित हैं।

जनगणना के नवीनतम आंकड़े नहीं होने की कई चुनौतियां हैं। एक शोधकर्ता का कहना है कि यदि हमें बच्चों का टीकाकरण करना है, आंगनवाड़ी कहां खोलनी है या पीडीएस में कितने परिवारों को शामिल करना है, तो इसके लिए जनगणना की जरूरत है। यही जनसंख्या के आंकड़ों का एकमात्र स्वतंत्र स्रोत है, जिससे प्रशासन और गांव स्तर तक आबादी की विशेषताओं, जैसे-आयु, लिंग, परिवार का आकार आदि की जानकारी मिलती है। कई शोधकर्ताओं ने इस ओर ध्यान दिया है कि प्रशासनिक आंकड़े इस बात पर निर्भर करते हैं कि सरकारी तंत्र किन लोगों तक पहुंच पाया। ऐसे में, पक्षपात की आशंका बनी रहती है। यह तथ्य जननीति के लिए स्वतंत्र और पूर्ण जनगणना की मांग को स्पष्ट करता है।

हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि सरकार और उसकी विभिन्न एजेंसियों ने हाल के वर्षों में कोई देशव्यापी सर्वे नहीं किया है। इनमें 2022-23 का वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस/एमपीसीई), 2020 की नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) के तहत जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का वार्षिक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-21 का एनएफएचएस-5) किए गए हैं। लेकिन जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के बिना यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि किसको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। उम्मीद है कि नई गठबंधन सरकार इस ओर ध्यान देगी।

चिंतन

हिंसाग्रस्त मणिपुर में जल्द शांति बहाली हो

मणिपुर में स्थाई शांति जरूरी है। पूर्वोत्तर का यह राज्य करीब 15 से अधिक महीने से हिंसा की आग में जल रहा है। पिछले साल 3 मई से मणिपुर में हिंसा की शुरूआत हुई, जब इस राज्य के दो प्रमुख समुदाय मैतई (घाटी बहुल) और कुकी जनजाति (पहाड़ी बहुल समुदाय) के बीच हाईकोर्ट की एक सिफारिश के बाद आमने-सामने आ गए। मैतई समुदाय को कुकी की तरह अनुसूचित जनताति का दर्जा दिए जाने की राज्य सरकार से हाईकोर्ट की सिफारिश किए जाने से कुकी समुदाय नाराज हो गए और सड़क पर उतर आए। तबसे मणिपुर में जारी हिंसा में करीब दो सौ लोग मारे गए हैं, ग्यारह सौ से अधिक लोग घायल हुए हैं और करीब 65 हजार लोग विस्थापित हुए हैं। मणिपुर के जिरीबाम में रविवार को सीआरपीएफ और पुलिस टीम के काफिले पर कुकी उग्रवादियों ने हमला कर दिया। इसमें सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। यह पहली बार नहीं है जब कुकी उग्रवादी सुरक्षा बलों पर उग्र हुए हैं। इस साल ही पांच बड़ी घटनाए हो चुकी हैं। 10 जून को मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह के काफिले पर हमला हुआ था। 8 जून को कुकी उग्रवादियों ने 2 पुलिस चौकियां व मैतई गांव में 70 घर जलाए। 26 अप्रैल को कुकी उग्रवादियों ने सीआरपीएफ चौकी पर बम फेंका था, जिसमें दो जवान शहीद हो गए। 15 फरवरी को भीड़ ने एसपी ऑफिस पर हमला किया, दो नागरिकों की मौत हो गई। 17 जनवरी को सुरक्षाबलों की गाड़ी पर उग्रवादियों ने हमला किया, 2 जवान सहित 3 की मौत हो गई। वर्ष 2023 की मई से दिसंबर तक अनेक बार हिंसा हुई। दरअसल, 38 लाख जनसंख्या वाले छोटे से पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में तीन प्रमुख समुदाय हैं- मैतेई, नगा और कुकी। मैतई ज्यादातर हिंदू हैं। नगा-कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं व अनुसूचित जनजाति वर्ग में आते हैं। मैतेई समुदाय की भी मांग है कि उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति (एसटी) में शामिल किया जाए। नगा-कुकी जनजाति इसके विरोध में हैं। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से मैतेई बहुल इंफाल घाटी में हैं। ऐसे में एसटी वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा। हाईकोर्ट की सिफारिश के बाद से वहां हिंसक संघर्ष जा रही है। पिछले साल गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर में शांति की स्थापना के लिए तीन दिवसीय यात्रा की थी, इस दौरान लगा कि शांति बहाल करने में सरकार सफल होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। इस वर्ष लोकसभा चुनाव के दौरान भी विपक्ष ने मणिपुर में हिंसा को मुद्दा बनाया था। पिछले महीने संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आम चुनाव के नतीजे के बाद अपनी प्रतिक्रिया में मणिपुर में हिंसा का समाधान न होने पर चिंता जाहिर की थी। चूंकि पूर्वोत्तर के सीमावर्ती राज्यों को अशांत रखने में चीनी भूमिका रहती है, इसलिए केंद्र व राज्य सरकार को चाहिए कि मणिपुर में जल्द से जल्द समाधान हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में कहा है कि जंग व हिंसा से समस्या हल नहीं होगी, तो देश के अंदर केंद्र व राज्य की प्रशासनिक मशीनरी को चाहिए कि मणिपुर में जल्द से जल्द हिंसक संघर्ष खत्म करने के लिए वार्ता का मंच बनाए और शांति बहाल करे। हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर को उसकी नियति पर नहीं छोड़ा जा सकता।

मुद्दा

डॉ. रमेश ठाकुर

बाढ़-प्रलय से हुई जनहानि का जिम्मेदार कौन?

आपदाएं अपने पीछे ऐसा दर्दनाक मंजर छोड़ जाती हैं जिसे इंसान वर्षों सहता है। मौजूदा बाढ़-बारिश से जनजीवन भयभीत हुआ है। हिंदुस्तान के विभिन्न हिस्सों में प्रलयकारी बाढ़ से अब तक अनुमानित 600 करोड़ रुपये के नुकसान का हुआ है। आर्थिक नुकसान के अलावा जानमाल की भी क्षति लगातार हो रही है। करीब 300 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। बाढ़ की विभिषिका से निपटने के लिए समाज आगे आया हुआ है, लेकिन बाढ़ से मचे हाहाकार को देखकर भारतीय आपदा प्रबंधन ने पूरी तरह से पत्ते डाले हुए हैं। उनकी कोशिशें और राहत-बचाव के प्रयास घटना स्थलों पर हांफ रहे हैं। भयंकर बाढ़ की भयाभता ने चारों ओर कहर बरपाया हुआ है। आपदा प्रबंधन से तो कहीं अच्छा कार्य इस वक्त स्थानीय प्रशासन जैसे एसडीएम, तहसीलदार, जिला कर्मचारियों के अलावा ग्राम प्रधान और राजनीतिक कार्यकर्ता करते दिख रहे हैं। आपदा प्रबंधन की हमेशा की तरह इस बार भी मानसून की पहली बारिश ने पोल खोली है। विभागीय अधिकारी-कर्मचारी तैयारियां कितनी करते हैं और कितनी गंभीरता से करते हैं? उसकी तस्वीर बाढ़ आने पर दिखती हैं। भारतीय आपदा प्रबंधन को अच्छे से ज्ञात होता है कि हिंदुस्तान अपनी अनूठी भू-जलवायु स्थितियों के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप और भूस्खलन बार-बार होने वाली घटनाएं स्वाभाविक होती हैं। लगभग 60 फीसदी भ-ूभाग विभिन्न तीव्रता के भूकंपों के लिए है, 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र बाढ़ के लिए है, 8 फीसदी चक्रवातों के लिए और 68 प्रतिशत क्षेत्र सूखे के लिए अतिसंवेदनशील माना जाता है। ऐसे में इन जगहों पर पूर्व में की जाने वाले तैयारियां विकट समस्याओं में विफल क्यों होती हैं? इसका जवाब आपदा प्रबंधन को ऐसे वक्त देना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं, कि मानसून के दो-ढाई महीने ऐसे होते हैं जो आपदा प्रबंधन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होते हैं। मानसून से पूर्व करीब 10 महीनों का पर्याप्त समय उनके पास तैयारियों का होता है। चाहे केंद्र सरकार हो, या राज्यों की हुकूमतें, प्रबंधन विभाग को धन से लेकर जरूरत की तमाम वस्तुएं मुहैया करवाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ती, ताकि बाढ़ आपदा से उनका आपदा प्रबंधन विंग अच्छे से निपट सके। पर, अफसोस विभाग उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता। आपदा प्रबंधन को सरकारें मुंह मांगा बजट आवंटित करती हैं। लेकिन इसके बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए सेना, एयरफोर्स, सीआरपीफए की टुकड़ियां लगानी पड़ती हैं। सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों को मोर्चा संभावना पड़ता है। आपदा प्रबधंन को रिफार्म करने की दरकार है। विभाग को आधुनिक करके नई तकनीकों को अपनाना होगा। करीब 33 लाख वर्ग किमी क्षेत्र के भौगोलिक विस्तार एवं 140 से ज्यादा आबादी वाले भारत में शायद ही इस वक्त कोई ऐसा भाग बचा हो जहां बाढ़ या बारिश आपदा की स्थिति न उत्पन्न हुई हो। नेपाल ने बारिश का अपना सारा पानी भारत की ओर मोड़ दिया है, जिससे भारत का तराई क्षेत्र और आसपास सटे जिले और गांव-कस्बे पानी से लबालब भरे हैं। उनसे निपटना जल आपदा प्रबंधन के बस का नहीं? पूर्वी बिहार में बहने वाली कोसी नदी उफान पर है। दर्जनभर जिलों को सड़क मार्ग पूरी तरह से कट गया है। बाढ़ पीड़ित लोग बमुश्किल सुरक्षित जगहों पर पनाह ले पा रहे हैं। तराई क्षेत्र के जिले पीलीभीत, लखीमपुर, बलरामपुर, बहराईच आदि जिलों के लोग जहां-तहां भाग रहे हैं। पीलीभीत में अभी हाल में बिछाया गया नया रेल ट्रैक भी पानी से बह गया। इस बार मानसून अच्छा है। बाढ़ से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की कमजोर तैयारियों निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करती हैं। असम, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमालच, पश्चिम बंगाल, बिहार जैसे 9 राज्य ऐसे हैं जो ज्यादा प्रभावित हैं। इन समस्याओं से निपटने की पहली जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन पर होती है, लेकिन ऐसे में वहां सिर्फ कमियां ही दिख रही हैं। उनमें आपसी समन्वय में कमी, अपर्याप्त फंडिंग का रोना, सीमित सार्वजनिक भागीदारी और अपर्याप्त संसाधनों की दुहाई दे रहे हैं। आपदा एक अचानक, विपत्ति पूर्ण घटना है, जो जीवन और संपत्ति को भारी क्षति, हानि, विनाश और तबाही में बदलती है। आपदाओं से होने वाला नुकसान सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। अफसोस इस बात का है कि बाढ़ जैसी समस्यायों से निपटने में हम अभी भी अक्षम हैं। केंद्रीय हुकूमत को गंभीरता इस मसले पर मंथन करना होगा। ताकि, भविष्य में ऐसे समस्याओं से सफल मुकाबला किया जा सके।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

विश्लेषण

डॉ. एल. एस. यादव

प्रगाढ़ होते भारत-बांग्लादेश संबंध

भारत में नई सरकार गठन के बाद यह किसी विदेशी नेता की पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा थी। प्रधानमंत्री शेख हसीना की इसी माह में यह दूसरी भारत यात्रा थी। इससे पहले वे प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत आईं थीं। बांग्लादेश और भारत के प्रधानमंत्रियों ने 22 जून को बैठक करके व्यापक वार्ता की। इस वार्ता में नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए भविष्य की योजना पर सहमति जताई और समुद्री क्षेत्र सहित अनेक मुख्य क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों द्वारा प्रमुख समझौतों में डिजिटल, हरित व रक्षा क्षेत्रों में बढ़ावा देने के समझौते शामिल हैं।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 21 एवं 22 जून की दो दिवसीय भारत यात्रा की। उनकी इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच पहले से ही बने घनिष्ठ संबंधों को और आगे बढ़ाना था। भारत में नई सरकार गठन के बाद यह किसी विदेशी नेता की पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा थी। प्रधानमंत्री शेख हसीना की इसी माह में यह दूसरी भारत यात्रा थी। इससे पहले वे प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत आईं थीं। इसके बाद वे जुलाई महीने चीन की यात्रा पर जाएंगी। चीन की यात्रा पर जाने से पहले उनका दो बार भारत आना यह दर्शाता है कि चीन यात्रा से उनके भारतीय संबंधों को कोई खतरा नहीं है। इधर भारत सरकार भी बांग्लादेश से अपने मधुर संबंधों को आगे जारी रखना चाहती है।

बांग्लादेश और भारत के प्रधानमंत्रियों ने 22 जून को बैठक करके व्यापक वार्ता की। इस वार्ता में नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए भविष्य की योजना पर सहमति जताई और समुद्री क्षेत्र सहित अनेक मुख्य क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए करीब 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित प्रमुख समझौतों में डिजिटल, हरित व रक्षा क्षेत्रों में बढ़ावा देने के समझौते शामिल हैं। इनमें बांग्लादेश के रोगियों के लिए ई-वीजा प्रमुख है। उल्लेखनीय है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेश के लोग इलाज कराने के लिए भारत आते हैं। वहां से भारत आने वाले ऐसे लोग 30 प्रतिशत के करीब हैं। ई-वीजा मिलने से ऐसे लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने नए क्षेत्रों में सहयोग के लिए भविष्योन्मुखी विजन तैयार किया है, जिसमें हरित साझेदारी, डिजिटल साझेदारी, अंतरिक्ष एवं ब्लू इकॉनोमी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत-बांग्लादेश की बनी सहमति से दोनों देषों के नवयुवकों को काफी लाभ मिलेगा। दोनों देशों की मैत्री भारत-बांग्लादेश संबंधों को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि हम अपनी वरीयता में डिजिटल और ऊर्जा कनेक्टिविटी पर फोकस रखेंगे। हमने पिछले 10 वर्षों में कार्य करते हुए 1965 से पहले की कनेक्टिविटी को बहाल कर दिया है। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था गतिशील होगी। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश हमारे लिए एक बड़ा विकास साझीदार है और हम उसके साथ अपने संबंधों को सबसे अधिक प्राथमिकता देते है। उन्होंने दोहराया कि मैं बंगबंधु के स्थिर, समृद्ध और प्रगतिषील बांगलादेश के विजन को साकार रूप प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इनमें दूसरा समझौता बांग्लादेश के रंगपुर में भारत का नया सहायक उच्चायोग होगा। बांग्लादेश के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के लोगों के लिए रंगपुर में एक सहायक उच्चायोग खोलने का निर्णय लिया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और कोलकाता के बीच नई रेल सेवा चालू की जाएगी। इसी तरह चटगांव और कोलकाता के बीच नई बस सेवा चालू हो जाएगी। पांचवा समझौता मेदे-दरसाना और हल्दीबाड़ी-चिलाहाटी के बीच दलगांव तक मालगाड़ी सेवाओंकी शुरूआत किए जाने का है। इसके अलावा

अनुदान सहायता के तहत सिराजगंज में अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो का निर्माण किया जाएगा। भारतीय ग्रिड से नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली के निर्यात की शुरूआत की जाएगी। इससे बांग्लादेश को फायदा होगा। 1996 की गंगा जल संधि के नवीनीकरण एक समिति बनाई जाएगी। बांग्लादेशी पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण में सहयोग किया जाएगा।

रक्षा संबंधों को मजबूत बनानें उदेश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और षेख हसीना के बीच चर्चा हुई। इसमें दोनों देशों ने लम्बी अवधि के हितों को ध्यान में रखकर एक रक्षा सहयोग की नीति बनाने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि भारत-बांग्लादेश के बीच सैनिक व रक्षा सहयोग की गति अभी तक काफी धीमी रही है, लेकिन अब किए गए नए समझौते के बाद से भारत जो सहयोग करेगा उससे बांग्लादेश की आर्मी अत्याधुनिक बनेगी। इसके अलावा बांग्लादेश की रक्षा आवश्यकताओं के मुताबिक रक्षा उपकरणों का उत्पादन प्रारम्भ होगा। यह कार्य इस प्रकार का होगा कि बांग्लादेश की रक्षा व यौद्धिक क्षमता काफी बढ़ सके। अभी तक भारत ने इस तरह का रक्षा समझौता किसी पड़ोसी देश के साथ नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और शेख हसीना ने आतंकवाद, कट्टरवाद और सीमा पर षांतिपूर्ण प्रबंधन अपनी सहभागिता को मजबूत करने का भी निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के मध्य हिन्द महासागर क्षेत्र के लिए समान दृष्टिकोण अपनाये जाने की बात निश्चित हुई। दोनों देशों ने अन्य क्षेत्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय मंचों पर अपना-अपना सहयोग जारी रखने का निर्णय लिया। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष यान से बांग्लादेश के लिए खासतौर पर निर्मित उपग्रहों को को स्थापित करने की सहमति कायम हुई। दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात में भारत ने बांग्लादेश की पुरानी मांग मान ली और बांग्लादेश को भूटान व नेपाल के साथ भारतीय रेलवे के जरिए कारोबार करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। इस स्वीकृति से बांग्लादेश को निर्यात बढ़ाने का एक बेहतर अवसर प्राप्त होगा। इस कदम से उत्साहित दोनों देश शीघ्र ही एक विशेष समझौता करने वाले हैं। अब दोनों देशों का यह प्रयास है कि भूटान, नेपाल व बांग्लादेश के बीच एक साझा बाजार तैयार किया जा सके। यदि इस कार्य में सफलता मिल गई तो भविष्य में इस बाजार में अन्य पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, म्यांमार आदि को शामिल किया जा सकेगा, इसीलिए दोनों दो रेल, सड़क, हवाई मार्ग व समुद्री मार्ग के जरिये आवागमन व माल ढुलाई के लिए कनेक्टविटी को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच बैठक में इस बात की भी सहमति बनी कि तीस्ता नदी जल प्रबंधन पर वार्ता के लिए भारत की एक तकनीकी टीम ढाका का दौरा करेगी। यह टीम तीस्ता नदी की गाद को साफ करने तथा नदी को पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए एक रोडमैप तैयार करेगी। बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण पर बातचीत के लिए एक भारतीय दल भेजने का निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की आपत्तियों के बावजूद एक अरब अमेरिकी डॉलर की इस परियोजना पर चीन की नजर थी। दरअसल चीन ने यह संकेत दिए थे कि वह तीस्ता नदी की सफाई के लिए भारी भरकम धनराशि की मदद देने को तैयार है। यह मुद्दा भारत के लिए अत्यन्त संवेदनशील है क्योंकि चीन की कंपनियों को ठेका मिलने का मतलब है कि उन्हें तीस्ता नदी से संबंधित सारा डाटा हासिल हो जाएगा, इसलिए भारत का यही प्रयास था कि चीन का इसमें प्रवेश न हो। इस आश्वासन के बाद अपने देश पहुंचकर शेख हसीना ने कहा कि उनकी भारत यात्रा सार्थक रही। निश्चित है कि उपर्युक्त समझौतों के बाद भारत तथा बांग्लादेश के आपसी संबंध और अधिक मधुरता की ओर बढ़ेंगे।

(लेखक सैन्य विज्ञान के प्राध्यापक रहे हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

जीवन का प्रथम अनुबंध किसको माना है?

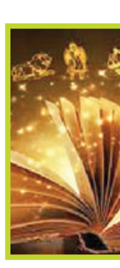

संकलित

दर्शन

अनुबंध चतुष्टय में 'अधिकारी' को प्रथम अनुबंध स्वीकार किया गया है। मानव की आध्यात्मिक और लौकिक यात्रा के निर्विघ्न संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लोक में इसके लिए योग्यता या पात्रता पद का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य है, किसी कार्य के निष्पादनार्थ पात्रता प्राप्त करना। सामान्यतः प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति पात्र नहीं होता। इसलिए अनधिकारी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य सफल और लोकमंगलकारी हो, यह आवश्यक नहीं, परंतु अधिकारी (पात्र) व्यक्ति द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य सफल भी होता है और लोकमंगलकारी भी। इसलिए अधिकारी आत्मिक और जागतिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला मानव जीवन का प्रथम अनुबंध है। इसीलिए इसे शास्त्रों में विशेष महत्व दिया गया है। वेदांत में अधिकारी को परिभाषित करते हुए कहा गया-जिसने विधिवत ज्ञान प्राप्त कर काम्य एवं निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर दिया है। नित्य, नैमित्तिक और उपासनादि कर्म करने से जिसकी बुद्धि परिष्कृत और अंतःकरण निर्मल हो चुका है, ऐसा पापरहित व्यक्ति ही विशिष्ट ज्ञान का अधिकारी है। विश्वामित्र आदि ऋषियों ने अधिकारी समझकर ही राम को विविध आयुध प्रदान किए, जिससे उनका दुरुपयोग न हो सके। उसी प्रकार अधिकारी को प्रदान की गईं शक्तियां समाज, देश और मानवता की रक्षा के लिए होती हैं। इतिहास साक्षी है कि जब भी अनधिकारी को शक्तियां प्रदान की गई हैं, उनका दुरुपयोग ही हुआ है।

जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों?

संकलित

प्रेरणा

एक गाय घास चरने के लिए एक जंगल में चली गई। शाम ढलने के करीब थी। उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव बढ़ रहा है। वह डर के मारे इधर-उधर भागने लगी। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वह बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर घुस गया। उसमें पानी कम था और वह कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरी काफी कम हुई थी। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। वह गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे-धीरे धंसने लगी। बाघ भीधीरे-धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों भी करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फस गए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बावजूद वह बाघ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद गाय ने उस बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूं। मेरा कोई मालिक नहीं। मैं खुद ही जंगल का मालिक हूं। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारे उस शक्ति का यहां पर क्या उपयोग है? उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फस गई हो और मरने के करीब हो। तुम्हारी भी तो हालत मेरे जैसी है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिलकुल नहीं। मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहां पर नहीं पाएगा तो वह ढूंढते हुए यहां जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकाल कर अपने घर ले जाएगा। तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर में सच में ही एक आदमी वहां पर आया और गाय को कीचड़ से निकालकर अपने घर ले गया।

अंतर्मन

आज की पाती

भारत में मजबूत है लोकतंत्र

हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अभी भी यहां के लोगों को लोकतंत्र पर विश्वास है। अगर यहां लोकतंत्र पर लोगों को विश्वास नहीं होता तो लोग लंबी-लंबी कतारों में लगकर अपने कीमती मत का प्रयोग कर सरकारें न चुनते और न ही अपनी मांगों के लिए धरने-प्रदर्शन कर पाते। हाल ही में अमरीकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कितने लोग अपने यहां के लोकतंत्र से खुश या संतुष्ट हैं। इसमें हमारा देश एशिया का दूसरा और विश्व का तीसरा देश है। यहां लगभग 77 फीसदी नागरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था से खुश या संतुष्ट हैं। हमारे देश के लोकतंत्र पर उंगली उठाने वाले देशों में जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका आदि के लोग अपने लोकतंत्र से उतने संतुष्ट नहीं हैं।

- राजेश गुप्ता, रायगढ़

ट्रेंड

ट्रंप पर हमले से चिंतित हूं

मेरे मित्र, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूं। घटना की कड़ी निंदा करता हूं. राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों और अमेरिकी लोगों के साथ हैं।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

हिंसा के लिए जगह नहीं

हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। हालांकि हम अभी तक नहीं जानते कि वास्तव में क्या हुआ था, यह राहत की बात है कि ट्रंप को गंभीर चोट नहीं आई। हमें खुद को प्रतिबद्ध करने के लिए करना चाहिए।

-बराक ओबामा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति

झूठ का मायाजाल

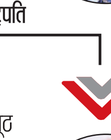

कल आप मुंबई में नौकरियां देने पर झूठ का मायाजाल बुन रहे थे। मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि आपने एनआरए की घोषणा करते हुए क्या कहा था। एनआरए करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। यह समय के साथ संसाधनों की भी बचत करेगा।

-मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष

मुफ्त की राजनीति का लेबल नहीं

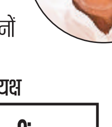

यदि आप प्रत्येक नागरिक के लिए 'सम्मान जनक जीवन के अधिकार' में विश्वास करते हैं, तो आप मुफ्त की राजनीति का लेबल नहीं देंगे। मैंने कैंब्रिज इंडिया कॉन्फ्रेंस में आप द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के महत्व के बारे में बात की।

-राघव चड्ढा, आप सांसद

करंट अफेयर

चीन की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट : राजा कृष्णमूर्ति

अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था में भारी सुस्ती आई है और बीजिंग के सामने दो रास्ते हैं-या तो वह अपने पड़ोसियों के खिलाफ आक्रामकता जारी रखे या फिर आक्रामकता कम करे और अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाए। भारतीय-अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा, 'वास्तव में चीन अपनी अर्थव्यवस्था में इस कदर सुस्ती का सामना कर रहा है कि कुछ क्षेत्रों में अपस्फीति (वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य के स्तर में गिरावट) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उपभोक्ता विश्वास खत्म हो गया है। आप दशकों तक एक-संतान नीति पर अमल करने वाले देश में 25 प्रतिशत से अधिक युवा बेरोजगारी देख रहे हैं। यह बहुत ही खराब आंकड़ा है।' कृष्णमूर्ति ने कहा, 'इससे खास तौर पर प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर कर्ज बढ़ गया है? साथ ही लोगों की कुल संपत्ति में काफी गिरावट आई है। ऐसे में शी चिनफिंग देश को गंभीर आर्थिक संकट में घिरा पा रहे हैं।' उन्होंने कहा कि चिनफिंग के पास दो विकल्प हैं, 'या तो वह वर्तमान रुख पर कायम रहें जो आर्थिक आक्रामकता को बढ़ावा दे रहा है, पड़ोसियों के प्रति तकनीकी और सैन्य आक्रामकता को बढ़ावा दे रहा है।

ऑफ बीट

जैल मैनीक्योर व ऐक्रेलिक नाखून लगते हैं सुंदर

काइली जेनर और रिहाना से लेकर एरियाना ग्रांडे और कार्डी बी तक, मशहूर हस्तियां अपनी शैली की अभिव्यक्ति के रूप में लंबे, एक्रेलिक - अक्सर नेल आर्ट से अत्यधिक अलंकृत - नाखून रखती हैं। नेल फैशन अब एक उभरता हुआ उद्योग है जिसमें जैल मैनीक्योर और ऐक्रेलिक नाखून सबसे लोकप्रिय वर्तमान रुझानों में से एक हैं। जबकि मैनीक्योर खुद की देखभाल की तरह लग सकता है, वे स्वस्थ प्राकृतिक नाखूनों को बर्बाद कर सकते हैं - और इन्हें करवाने वाले लोगों के नाखूनो में अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऐक्रेलिक को प्राकृतिक नाखून से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नेल गोंद आमतौर पर अल्कोहल, साइनोएक्रिलेट और फोटो-बॉन्ड मेथैक्रिलेट का मिश्रण होता है, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड सहित अन्य तत्व होते हैं, जो एक ज्ञात कैंसर कारक है। नाखून चिपकने वाले पदार्थों में मौजूद रसायन त्वचा में जलन और सूजन का कारण बन सकते हैं। नेल ग्लू के जलने की भी व्यापक रूप से सूचना मिलती है। कुछ मामलों में, कपड़ों पर गिरा हुआ नेल गोंद जलने से त्वचा को भी जला देता है, जिसमें बाद में संक्रमण हो सकता है।

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।